



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 939]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 18, 2009/ज्येष्ठ 28, 1931

No. 939]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 18, 2009/JYAISTHA 28, 1931

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जून, 2009

का.आ. 1507(अ).—विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 4(4) के अनुसार दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति श्री एस. एन. अग्रवाल की अध्यक्षता में गठित अधिकरण, जिसको विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 4(1) के अन्तर्गत यह न्याय निर्णय करने के लिए एक संदर्भ भेजा गया था कि क्या असम के नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (एनडीएफबी) को विधिविरुद्ध घोषित करने के पर्याप्त कारण हैं अथवा नहीं, का आदेश आम सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है।

[सं. 11011/54/2008-एन ई-III]

नवीन वर्मा, संयुक्त सचिव

माननीय न्यायमूर्ति एस. एन. अग्रवाल.

की अध्यक्षता में

विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिकरण के समक्ष

सरकार द्वारा दिनांक 12-12-2008 की अधिसूचना सं. का. आ. 2869(अ) के तहत गठित एनडीएफबी अधिकरण की रिपोर्ट

संदर्भ : नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोरोलैण्ड

बोरो सुरक्षा बल नामक एसोसिएशन, जिसे अब नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रण्ट आफ बोरोलैण्ड के रूप में पुनर्नामित किया है (जिसे एतदपश्चात् एन डी एफ बी कहा जाएगा), का अपना घोषित लक्ष्य असम के बोरो वासी क्षेत्र को मिलाकर बने "बोरोलैण्ड" को "आजादी" दिलाना और उपर्युक्त क्षेत्र को पूर्वोत्तर के अन्य सशस्त्र अलगाववादी संगठनों के सहयोग से भारत से पृथक करना है। ऐसा कहा जाता है कि इसके क्रियाकलाप इसके उद्देश्य का संवर्धन कर रहे हैं। भारत सरकार गृह मंत्रालय द्वारा दिनांक 23.11.2008 को जारी तथा उसी दिन सरकारी राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना निम्नलिखित है:-

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 नवम्बर, 2008

का.आ. 2714(अ)- जबकि बोडो सुरक्षा बल, जिसे अब नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रण्ट आफ बोरोलैण्ड (जिसे एतदपश्चात् एन डी एफ बी कहा जाएगा) का अपना घोषित लक्ष्य असम के बोडो वासी क्षेत्रों को मिलाकर बने बोडोलैण्ड को "आजादी" दिलाना तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के अन्य सशस्त्र अलगाववादी संगठनों के सहयोग से उक्त क्षेत्र को भारत से पृथक करना है;

यह विचार कि एन डी एफ बी, भारत सरकार एवं असम सरकार के साथ 1 जून, 2005 को अभियानों का निलम्बन करने के करार पर हस्ताक्षर करने के पश्चात् हिंसा का संत्याग करने पर सहमत होते हुए भी, निम्नलिखित कृत्य जारी रखे -

- (i) पृथक बोडोलैण्ड के अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में भारत की संप्रभुता तथा भू-भागीय अखंडता को विघटित करने वाले विभिन्न विधिविरुद्ध एवं हिंसक क्रियाकलापों में शामिल रहा है;
- (ii) इसने, पृथक बोडोलैण्ड का निर्माण करने के लिए स्वयं को यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम तथा नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (इसाक मुईवाह) जैसे पूर्वोत्तर के अन्य भूमिगत संगठनों के साथ स्वयं को मिला लिया है;

- (iii) अनेक विधिविरुद्ध एवं हिंसक क्रियाकलापों में रत होना, इस प्रकार इसने सरकार और असम सरकार के प्राधिकार को कम किया तथा लोगों में आतंक एवं दहशत फैलाई;
- (iv) अपनी योजनाओं एवं क्रियाकलापों को वित्तपोषित तथा कार्यान्वित करने के लिए समाज के विभिन्न वर्गों से जबरन धन वसूली में शामिल रहा है;
- (v) अपने आतंकवादी एवं विद्रोही क्रियाकलापों को जारी रखने के उद्देश्य से नए काडरों की भर्ती के लिए सुनियोजित अभियान चलाना;
- (vi) गैर बोडो लोगों में दहशत और असुरक्षा की भावना उत्पन्न करने तथा असम में बोडो बहुल क्षेत्रों में रहने वाले हजारों गैर-बोडो लोगों को अपने निवास स्थल छोड़कर जाने के लिए नृजातीय हिंसा एवं हत्या करने में रत रहा है जिससे गैर बोडो लोगों की सम्पत्ति को क्षति हुई;
- (vii) अपने अलगाववादी क्रियाकलापों को चलाने के लिए इसने देश की सीमा पर शिविर तथा छिपने के अड्डे स्थापित करना जारी रखा;

और जबकि भारत सरकार की यह राय है कि हिंसक गतिविधियों में निम्नलिखित शामिल है :-

- (i) वर्ष 2006 में 16 हिंसक घटनाएं हुई जिनमें 5 सुरक्षा बल कार्मिक और 9 सिविलियनों की मृत्यु हुई;
- (ii) वर्ष 2007 में 31 हिंसक घटनाएं हुई जिनमें 3 सिविलियन मारे गए;
- (iii) वर्ष 2008 (15 जुलाई, 2008 तक) में 63 हिंसक घटनाएं हुई जिनमें 14 सिविलियन मारे गए।

और जबकि उपर्युक्त के आधार पर केन्द्रीय सरकार की यह राय भी है कि एन डी एफ बी के उपर्युक्त क्रियाकलाप भारत की सम्प्रभुता एवं अखण्डता के लिए हानिकर हैं तथा यह एक विधिविरुद्ध संगम है;

और जबकि केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि यदि एन डी एफ बी की विधिविरुद्ध गतिविधियों को नियंत्रित नहीं किया गया तो यह पुनर्गठित होकर

स्वयं को शस्त्रों से लैस करके नई भर्तियां करना शुरू कर देगी तथा हिंसक, आतंकवादी एवं अलगाववादी गतिविधियों में शामिल होगी, धन संग्रहण करेगी तथा मासूम नागरिकों एवं सुरक्षा बल कर्मियों की जान के लिए खतरा उत्पन्न करेगी अतः इसे तत्काल प्रभाव से विधिविरुद्ध संगम घोषित करने की पर्याप्त परिस्थितियाँ हैं।

अब, अतः, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 की 37) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रण्ट आफ बोरोलैण्ड (एनडीएफबी) को विधिविरुद्ध संगम के रूप में घोषित करती है।

केन्द्रीय सरकार की आगे राय है कि एन डी एफ बी को तत्काल प्रभाव से एक विधिविरुद्ध संगम घोषित करना जरूरी है और तदनुसार, उपर्युक्त अधिनियम की धारा 3 की उप धारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का अनुकरण करते हुए केन्द्रीय सरकार निदेश देती है कि यह अधिसूचना उक्त अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत किए जाने वाले अन्य आदेशों के अध्यधीन, सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[फाइल सं. 11011/54/2008-एन ई-111]

नवीन वर्मा, संयुक्त सचिव

2. विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (जिसे एतदपश्चात् संक्षेप में "यू ए अधिनियम" कहा जाएगा) की धारा 5(1) में किए गए प्रावधान के अनुरूप मुझे, भारत सरकार ने दिनांक 12-12-2008 की अधिसूचना सं. का.आ. 2869(अ) के तहत एक सदस्यीय अधिकरण के रूप में नियुक्त किया था और केन्द्रीय सरकार द्वारा दिनांक 23.11.2008 की अधिसूचना मेरे पास यह न्यायनिर्णय करने के लिए भेजी गई कि एन डी एफ बी संगठन को विधिविरुद्ध संगठन के रूप में घोषित करने के लिए पर्याप्त कारण हैं अथवा नहीं।

3. सरकार की ऊपर उल्लिखित दिनांक 12.12.2008 की अधिसूचना के तहत एक सदस्यीय अधिकरण के रूप में मेरी नियुक्ति होने के परिणामस्वरूप मैंने श्री अनिल कुमार कौशल को अधिकरण के रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्त किया और अधिकरण के रजिस्ट्रार के रूप में उनकी नियुक्ति को सरकार द्वारा दिनांक



16.12.2008 के आदेश सं. 11011/54/2008 एन.ई.-III के तहत अधिसूचित किया गया। तत्पश्चात्, मैंने अपने दिनांक 07.01.2009 के आदेश के तहत अधिकरण के रजिस्ट्रार को निदेश दिया कि वह एन डी एफ बी संगठन को नोटिस भेजें जिसमें इस नोटिस के तामील किए जाने की तारीख से 30 दिन के अंदर एन डी एफ बी संगठन से लिखित रूप में यह कारण बताने के लिए कहा जाए कि उक्त संगठन को विधिविरुद्ध संगम क्यों न घोषित कर दिया जाए। यह निदेश यू.ए. अधिनियम की धारा 4(2) के परन्तुक के अन्तर्गत यथापेक्षित के रूप में दिया गया था। यह कारण बताओं नोटिस दो राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों तथा असम के दो स्थानीय अखबारों में प्रकाशित करवाने के साथ-साथ एन डी एफ बी संगठन के सभी उपलब्ध पत्तों पर भेजने का निदेश दिया। इस नोटिस की एक प्रति एन डी एफ बी संगठन कार्यालय के दृष्टिगोचर स्थल पर चिपकाकर भी एन डी एफ बी संगठन को तामील किए जाने का निदेश दिया गया। यह नोटिस यू.ए. अधिनियम की धारा 4(2) के अन्तर्गत यथापेक्षित एन डी एफ बी संगठन को विधिवत रूप से तामील कराया गया और मैं रिकार्ड में दर्ज सेवा हलफनामों से इस बात से संतुष्ट हूँ कि उक्त संगठन को नोटिस की तामील विधिवत ढंग से कराई गई।

4, एन डी एफ बी संगठन को नोटिस दिए जाने के प्रत्युत्तर में एन डी एफ बी इस अधिकरण के समक्ष अपने अधिवक्ता श्री अतनु गांगुली और श्रीएन. जमान के साथ उपस्थिति रूप। उन्होंने इस अधिकरण के समक्ष 24.02.2009 को एन डी एफ बी की ओर से जवाब दायर किया और तत्पश्चात् 02.03.2009 को एक अतिरिक्त जवाब भी प्रस्तुत किया। यह जवाब तथा अतिरिक्त जवाब कारण बताओ नोटिस में उनको दिए गए समय सीमा के अन्तर्गत एन डी एफ बी ने प्रस्तुत किया।

5, चूंकि एन डी एफ बी ने इसकी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने वाली सरकार की अधिसूचना के विरोध में अपना प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया था, इसलिए मैंने भारत के विद्वान अतिरिक्त सालिसिटर जनरल श्री पी.पी. मलहोत्रा और असम राज्य सरकार के स्थायी अधिवक्ता को भारत संघ की ओर से उपस्थिति होने और एन डी एफ बी के काउन्सेल को अपने प्रतिपक्षी आकलन के समर्थन के साक्ष्य में स्वतंत्र हलफनामे देने को कहा। इस निदेश के अनुसरण में असम राज्य सरकार की ओर से साक्ष्य में तेरह हलफनामे दायर किए गए, एक हलफनामा असम

राज्य सरकार के संयुक्त सचिव (गृह) श्री एस.के. राय ने दायर किया तथा एक अन्य हलफनामा भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली के निदेशक (पूर्वोत्तर-॥) श्री आ.आर. झा ने दायर किया। एन डी एफ बी की ओर से साक्ष्य में तीन हलफनामे दायर किए गए। मुख्य साक्ष्य के रूप में जिन गवाहों ने हलफनामों दायर किए उनका प्रतिपक्ष के अधिवक्ता ने व्यापक रूप से प्रति-परीक्षण किया।

6. असम राज्य के विभिन्न जिलों के पुलिस अधीक्षकों द्वारा दर्ज तेरह हलफनामों को अधिकरण के समक्ष तीन खण्डों अर्थात् खण्ड-१ - खण्ड-॥ के रूप में प्रस्तुत किया गया। सभी तेरहों पुलिस अधीक्षक जिन्होंने साक्ष्य के रूप में अपने हलफनामों दायर किए थे अधिकरण के समक्ष गवाह के रूप में उपस्थित हुए। साक्ष्य के रूप में अपना हलफनामा दायर करने वाले तेरहों पुलिस अधीक्षकों का व्यौरा निम्नलिखित है :-

- पी डब्ल्यू-१ श्री प्रदीप चन्द्र सालोई, पुलिस अधीक्षक, गुवाहाटी सिटी, असम (हलफनामा-खण्ड-॥ में पृष्ठ १५४-३८८ तक)
- पी डब्ल्यू-४ श्री अर्णव डेका, पुलिस अधीक्षक, चैरैंग जिला, असम (हलफनामा-खण्ड ॥ में पृष्ठ ४६४-४९९ तक)
- पी डब्ल्यू-५ श्री देवोज्योति मुखर्जी, पुलिस अधीक्षक बाड़पेटा जिला असम (हलफनामा, खण्ड ॥ में पृष्ठ ६३०-६६० तक)
- पी डब्ल्यू-६ श्री अरविन्द कालिता, पुलिस अधीक्षक, जिला-कोकराझार असम (हलफनामा, खण्ड-॥ में पृष्ठ ८०६-८८५)
- पी डब्ल्यू-७ श्री कृष्ण कुमार शर्मा, एस.पी. कारबी आंगलांग जिला, असम (हलफनामा- खण्ड-॥ में पृष्ठ ५०० से ६१५ तक)
- पी डब्ल्यू-८ श्री नितुल गोगोई, एस.पी. नागाँव जिला, असम (हलफनामा-खण्ड-॥ ६१६ से ६२९ तक)
- पी डब्ल्यू-९ श्री सुरेन्द्र कुमार, एस.पी. सोनितपुर, जिला असम (हलफनामा - खण्ड-॥ में ६६८ से ६८९ एल तक)
- पी डब्ल्यू-११ जनाब सैय्यद अतौल करीम, एस.पी. लखीमपुर जिला, असम (हलफनामा- खण्ड-॥ पृष्ठ संख्या ७८१-८०५ तक)
- पी डब्ल्यू-१२ श्री राणा भूयान, एस.पी. बक्सा जिला, असम (हलफनामा - खण्ड-॥ पृष्ठ ३८९-४२६ तक)

- पी डब्ल्यू-13 श्रीबीर बिक्रम गोगोई, ए.एस.पी.(मुख्यालय) गोलाघाट जिला, असम (हलफनामा- खण्ड-III में पृष्ठ 886-905)
- पी डब्ल्यू-14 श्री आनन्द प्रकाश तिवारी, एस.पी. उदालगिरि जिला, असम (हलफनामा-खण्ड-II पृष्ठ 427-463 तक)
- पी डब्ल्यू-15 श्री पारथा सारथी महन्त, एस.पी. धुबरी जिला, असम (हलफनामा-खण्ड-III) में पृष्ठ 689एम-780 तक)
- पी डब्ल्यू-3 श्री बान्या गोगोई, एसपी, स्पेशल आपरेशन यूनिट, असम सरकार, गुवाहाटी (हलफनामा - खण्ड-I पृष्ठ 146-153 तक)

7. भारत सरकार की ओर से अधिसूचना के समर्थन में जिन दो अन्य गवाहों का परीक्षण किया गया उनका ब्यौरा निम्नलिखित है -

- पी डब्ल्यू-2 श्री एस.के. राय, संयुक्त सचिव, गृह एवं राजनीतिक विभाग, असम सरकार, दिसपुर, गुवाहाटी (हलफनामा- खण्ड-II पृष्ठ 1-145 तक)
- पी डब्ल्यू-10 श्री आर.आर. झा, निदेशक, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली (हलफनामा - पृष्ठ 1-31 तक पार्ट IV फाइल के रूप में वर्णित पृथक फोल्डर में)

8. प्रश्नाधीन अधिसूचना के विरोध में एन डी एफ बी द्वारा जाँच किए गए तीन गवाहों का ब्यौरा निम्नलिखित है :-

- डी डब्ल्यू-1 श्री बी. स्वमख्यर, एन डी एफ बी के महासचिव (हलफनामा- भाग V फाइल के रूप में वर्णित पृथक फोल्डर में पृष्ठ 1-44 तक)
- डी डब्ल्यू-2 श्री आई. दामिनी, एन डी एफ बी के गृह सचिव (हलफनामा- भाग V फाइल के रूप के रूप में वर्णित पृथक फोल्डर में पृष्ठ 1-6 तक)
- डी डब्ल्यू-3 श्रीबी.के. ओल्लोंगवार, एन डी एफ बी के शिक्षा सचिव (हलफनामा - भाग V फाइल के रूप में वर्णित पृथक फोल्डर में पृष्ठ 1-6 तक)

9. अब, मैं एन डी एफ बी को विधिविरुद्ध संगम के रूप में प्रतिबंधित करने के समर्थन में भारत सरकार और असम राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य दिनांक 23.11.2008 की अधिसूचना पर पुनः आता हूँ। पी डब्ल्यू-1, पी डब्ल्यू-3 से पी डब्ल्यू-9 और पी डब्ल्यू-11 से पी डब्ल्यू-15, जो सभी असम राज्य के विभिन्न जिलों में पुलिस अधीक्षक हैं, ने अपने साक्ष्य में कहा है कि वे सभी

अपने-अपने जिलों में कानून एवं व्यवस्था की जिम्मेदारी निभाने के अतिरिक्त, विधिविरुद्ध मामलों, खासकर आतंकवादी संगठनों द्वारा किए गए मामलों की जाँच को मानीटर भी करते हैं। पुलिस गवाहों के अनुसार एन डी एफ बी के काडर असम राज्य में तथा उसके आसपास सक्रिय हैं और वे भारी पैमाने पर विधिविरुद्ध क्रियाकलापों में संलिप्त हैं तथा असम राज्य सरकार सहित भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध में रत हैं। पुलिस गवाहों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अनुरूप एन डी एफ बी के काडर अतिक्रम एवं कमीशन के अपने विभिन्न कृत्यों के जरिए स्थानीय लोगों के मन में भय सृजित करके उन्हें आतंकित कर रहे हैं।

10. पी डब्ल्यू-1 श्री सालोई ने अपने हलफनामा, ई एक्स पी डब्ल्यू-1/1, में हिंसा की कुछ घटनाओं का उल्लेख किया है जो उनके क्षेत्राधिकार में हुईं जिनमें, उनके अनुसार, एन डी एफ बी के काडरों की संलिप्तता पाई गई। उन्होंने साक्ष्य दिया कि दिनांक 30.10.2008 को प्रातः 11.20 से 11.30 बजे के बीच 10 मिनट के अल्प समयान्तराल में गुवाहाटी शहर में तीन श्रृंखलाबद्ध बम विस्फोट हुए। पी डब्ल्यू-1, श्री सालोई के साक्ष्य के अनुसार प्रातः 11.20 के लगभग मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कारमरूप, गुवाहाटी के कार्यालय की पार्किंग स्थल में पार्क की गई एक कार में रखे बम में विस्फोट हुआ और उक्त विस्फोट में 13 व्यक्ति मारे गए एवं 68 व्यक्ति जख्मी हुए। इस विस्फोट में ऐसा सूचित किया गया कि, 91 वाहन पूरी तरह से जल गए। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय का न्यायालय भवन तथा जिला न्यायालय कारमरूप (एम.) के कार्यालय की बाउण्ड्री वाल आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गई। लगभग 11.25 बजे बैप्टिस्ट चर्च, पान बाजार के सामने एच.वी. रोड साइड के पास पार्क की गई एक गाड़ी में रखे बम में विस्फोट हो गया और ऐसी रिपोर्ट मिली है कि उक्त विस्फोट में 8 व्यक्ति मारे गए तथा 44 व्यक्ति जख्मी हो गए। प्रातः लगभग 11.25 बजे हुए विस्फोट में 13 चौपहिया एवं दुपहिया वाहन तथा 7 दुकानें आग में जल गईं। तीसरा विस्फोट उसी दिन अर्थात् 30.10.2008 को लगभग 11.30 बजे हुआ जब होटल डेलीकेसी के सामने गणेशगुरी फ्लाईओवर के नीचे पार्क की गई एक गाड़ी में रखे बम में विस्फोट हो गया। लगभग प्रातः 11.30 बजे हुए इस बम विस्फोट में 32 व्यक्ति मारे गए और 142 व्यक्ति जख्मी हो गए। 65 वाहन पूरी तरह से नष्ट हो गए और ऐसी रिपोर्ट है कि 8 दुकानें और बिजनेस अवस्थापन तथा गणेशगुरी फ्लाईओवर ब्रिज आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गया।

11. श्री सालोई (पी डब्ल्यू-1) ने अपने हलफनामों में साक्ष्य दिया कि श्रंखलाबद्ध तीन कार बम विस्फोटों की घटनाओं के संबंध में तीन प्राथमिकियाँ दर्ज कराई गईं और उन्होंने इन तीनों प्राथमिकियों का अपने हलफनामा ई एक्स. पी डब्ल्यू-1/1 के पैरा (1), (2) और (3) में विस्तृत वर्णन किया है। श्री सालोई ने साक्ष्य दिया कि थाना पान बाजार के क्षेत्राधिकार में लगभग प्रातः 11.20 बजे हुए बम विस्फोट के मामले में की गई जाँच के दौरान एन डी एफ बी संगठन के (1) राजीब सैनारी (2) फुंखा ब्रह्म (3) मृदुल बसुमातारी और (4) पबित्र बोरो नामक चार व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और उन्होंने पूछताछ के दौरान यह स्वीकार किया कि 30.10.2008 को थाना पान बाजार के क्षेत्राधिकार में प्रातः 11.30 बजे जो बम विस्फोट हुआ वह एन डी एफ बी काडरों द्वारा रखा गया था जो युद्ध विराम के आधारभूत नियमों का उल्लंघन करते हुए अलगाववादी क्रियाकलापों में संलिप्त हैं। थाना पान बाजार के क्षेत्राधिकार में प्रातः लगभग 11.25 बजे हुए कार बम विस्फोट के संबंध में मि. सालोई ने अपने साक्ष्य हलफनामों में कहा कि एन डी एफ बी संगठन के (1) दीपक बसुमातारी उर्फ डैंग्ख्या राजा और (2) अनुप कुमार बोरो उर्फ नाला नामक दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था और उन्होंने माना कि प्रातः लगभग 11.25 जो बम विस्फोट हुआ वह एन डी एफ बी काडरों ने रखा था। इसी तरह, मि. सालोई के बयान के मुताबिक एन डी एफ बी संगठन के (1) अनुप कुमार बोरो उर्फ नाला (2) निलिम दैमारी उर्फ डी. निजिम्सा (3) साबिन बोरो उर्फ बी. सुसंरागू और (4) श्री बिमल मौसहारी नामक चार व्यक्तियों को गनेशगुरी फ्लाईओवर के नीचे प्रातः लगभग 11.30 बजे हुए बम विस्फोट की घटना के संबंध में गिरफ्तार किया गया और इस घटना में गिरफ्तार चारों व्यक्तियों ने पूछताछ के दौरान यह स्वीकार किया कि इस घटना में एन डी एफ बी के काडर संलिप्त थे।

12. पी डब्ल्यू-4 मि. डेका ने अपने हलफनामा ई एक्स, पी डब्ल्यू-4/1 में अपने क्षेत्राधिकार अर्थात् असम के चिरांग जिला में हुई दो घटनाओं - पहली घटना 14.06.2007 और दूसरी 06.10.2008 के संबंध में साक्ष्य दिया है। दिनांक 14.06.2007 को हुई घटना के संबंध में मि. डेका ने अपने हलफनामों में उल्लेख किया कि श्री रामेश्वर सिन्घा, सहायक कमाण्डेंट, डी/116 बटालियन सी आर पी एफ, न्यू बोंगाईगाँव, असम ने बिजनी पुलिस थाने में इस आशय की रिपोर्ट दायर की कि दिनांक 14.06.2007 को सायं 15.30 बजे उनके नेतृत्व में सी आर पी एफ कार्मिकों द्वारा दी गई सूचना पर काम करते हुए, उसने फैन्सी बाजार एरिया

की नाका-बंदी कर दी तथा उन्होंने ए एस 15बी 1152 पंजीयन सं. वाली एक हीरो होण्डा मोटर साइकिल पर सवार श्री कोनोक दैमारी नामक एक बoro युवक को गिरफ्तार किया। जब कोनोक दैमारी की सी आर पी एफ सी/एन संतोष चौधुरी ने तलाशी ली तो कोनोक दैमारी ने पिस्तौल बाहर निकाल ली और सन्तोष चौधुरी पर उससे प्रहार किया तथा सी आर पी एफ जवानों के हाथों से छूटकर भाग गया। तथापि उसका तुरन्त पीछा किया गया और उसे दबोच लिया गया। उसके पास से निम्नलिखित वस्तुएं जब्त की गई -

1. एक 7.62 चीनी पिस्तौल
2. एक मैग्जीन
3. 8 राउण्ड जिन्दा एम्युनिशन
4. 4 पर्स जिनमें कुल 1900.00 रुपये थे।
5. एक नोकिया मोबाइल फोन
6. एक आई कार्ड
7. ए एस 15 बी 1152 नम्बर वाली एक हीरो होण्डा मोटर साइकिल।

13. पी डब्ल्यू-4 मि. डेका द्वारा दिए गए साक्ष्य के अनुसार गिरफ्तार व्यक्ति श्री कोनोक दैमारी उर्फ डी. खान्नांग की जाँच के दौरान इस बात के पर्याप्त साक्ष्य मिले कि वह संदिग्ध एन डी एफ बी काडर का है।

14. पी डब्ल्यू-4 मि. डेका द्वारा वर्णित 06.10.2008 की दूसरी घटना के संबंध में उन्होंने बताया कि गाँव मुजबारी के आजमल हक खान्नांग ने पुलिस थाना सिडली में 06.10.2008 को इस आशय की एक प्राथमिकी दायर की कि उस दिन रात को लगभग 0045 बजे कुछ अज्ञात सशस्त्र बदमाश उनके आंगन में आ गए तथा दो राउण्ड गोलियाँ चलाई और फायरिंग करने के बाद वह अज्ञात बदमाश उनके पड़ोसी रुस्तम अली और कुड्डुस अली के घर की ओर गए और फिर उन्होंने बाहर से उसके घर की ओर अंधाधुंध गोलियाँ चलाई जिसके परिणामस्वरूप रुस्तम अली की विवाहित पुत्री के पेट में चोट लग गई और उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। रुस्तम अली के सिर में गोली लगी तथा कुड्डुस अली के कंधे में गोली लगी। घायल व्यक्तियों को पुलिस ने उपचार के लिए लोअर असम हास्पिटल, बोंगाई गाँव भेज दिया। पी डब्ल्यू-4 मि. डेका के क्षेत्राधिकार में दिनांक 06.10.2008 को हुई घटना के संबंध में थाना सिडली में एक मामला संख्या

41/2008 दर्ज किया गया (पी डब्ल्यू-4 मि. डेका के हलफनामा का अनुलग्नक-“एच”)। इस मामले सं. 41/2008 की जाँच के दौरान ओगल वैरी तथा मोडा गोयरी उर्फ मुकुल नामक दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और पुलिस ने उनसे पूछताछ की और उनसे पूछताछ के दौरान उन्होंने पुलिस के समक्ष खुलाशा किया कि वे एन डी एफ बी के उस छह सदस्यीय दल के भाग हैं जिसने लोगों में दहशत फैलाने के लिए मुजाबारी गाँव में मुस्लिम परिवारों पर हमला किया था। मि. डेका ने अपने हलफनामा ई एक्स पी डब्ल्यू-4/1 के साथ अनुलग्नक दस्तावेज “के” और “एल” के रूप में गवाहों के बयानों तथा जाँच अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए दोषी व्यक्तियों के बयानों की प्रतियाँ संलग्न की हैं। एन डी एफ बी काइरों के गिरफ्तार दोषी व्यक्तियों के पास से कुछ शस्त्र एवं गोलाबारूद भी बरामद किया गया जिसे मि. डेका ने अपने हलफनामा के अनुलग्नक में रूप में संलग्न किया है। पी डब्ल्यू-4 मि. डेका ने शपथपूर्वक बयान दिया है कि उन्होंने दिनांक 14.06.2007 तथा 06.10.2008 की दोनों घटनाओं के मामलों की केस डायरी देखी है जिससे, उनके अनुसार यह व्यक्त होता है कि एन डी एफ बी तथा इसके सदस्यों ने भारत सरकार, असम राज्य सरकार तथा एन डी एफ बी के बीच 01.06.2005 को सहमत अभियान निलम्बन के आधारभूत नियमों का उल्लंघन करते हुए साम्प्रदायिक सहभाव को बाधित किया है, तथा वे मनोभावनात्मक रूप से लोगों में दहशत पैदा करने के इरादे से गैर बोरो लोगों पर हमले करने, हत्या का प्रयास करने, हमला करने, हत्या करने, गैर-कानूनी रूप से शस्त्र एवं गोला बारूद रखने सहित विधिविरुद्ध क्रियाकलापों में संलिप्त हैं और उन्होंने राज्य के विरुद्ध सक्रिय रूप से युद्ध की स्थिति बना रखी है।

15. पी-डब्ल्यू-5 मि. मुखर्जी ने, पी डब्ल्यू-1 मि. सालोई के क्षेत्राधिकार में दिनांक 30.10.2008 को हुए श्रृंखलाबद्ध कार बम विस्फोटों के साथ-साथ, उसी दिन और उसी समय के लगभग उनके क्षेत्राधिकार में हुए इन्टीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक डिवायस (आई ई डी) विस्फोटों के संबंध में साक्ष्य दिया है। पी डब्ल्यू-5 श्री मुखर्जी के साक्ष्य के अनुसार बाड़पेटा रोड रेलवे स्टेशन के उत्तरी ओर स्थित सब्जी बाजार में दिनांक 30.10.2008 को प्रातः लगभग 11.28 बजे एक आई ई डी बम विस्फोट हुआ और उस बम विस्फोट में 9 व्यक्तियों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई तथा 164 व्यक्ति गंभीर रूप/हल्के-फुल्के रूप से घायल हुए जिसके लिए विस्फोटक पदार्थ अधिनियम धारा 3 के साथ पठित भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120ख/121(क)/126/153ख/302/326 के अन्तर्गत थाना बाड़पेटा रोड

में प्राथमिकी (मि. मुखर्जी के हलफनामा का अनुलग्नक-1) के तहत मामला संख्या 262/08 दर्ज किया गया है। श्री मुखर्जी ने आगे साक्ष्य दिया कि एक अन्य आई ई डी विस्फोट बाइपेटा रोड टाउनशिप के अन्तर्गत चौधरी मार्केट काम्प्लेक्स के सामने दिनांक 30.10.2008 को सायंकाल लगभग 12.29 बजे हुआ जिसमें 7 व्यक्ति घटनास्थल पर ही मारे गए और कुछ अन्य इलाज के दौरान मर गए तथा काफी संख्या में लोग घायल हुए। इस विस्फोट के संबंध में पुलिस थाना बाइपेटा रोड में मामला सं. 261/08 दर्ज किया गया।

16. पी डब्ल्यू-5 मि. मुखर्जी ने अपने साक्ष्य हलफनामा में आगे साक्ष्य दिया कि जाँच-पड़ताल के दौरान यह खुलासा हुआ कि एन डी एफ बी काडर उपर्युक्त दोनों बम विस्फोट करने तथा अन्य अपराध करने में संलिप्त हैं। एन डी एफ बी का एक अभियुक्त श्री अनूप बोरो को गिरफ्तार कर लिया गया और उसने एन डी एफ बी काडरों की संलिप्तता का रहस्योद्घाटन किया और राजेन गोयारी, मृदुल गोयारी, बी. मुदोई और बी. बिदाई जैसे को सूचीबद्ध एन डी एफ बी काडरों के नाम बताए। इन सूचीबद्ध एन डी एफ बी काडरों के नाम अभियुक्त अनूप बोरो ने न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज धारा 164 के अन्तर्गत दिए गए अपने बयान में बताये। पी डब्ल्यू-5 के अनुसार थाना बाइपेटा रोड में दर्ज मामला सं. 261/08 और 262/08 की केस डायरियों से उनके क्षेत्राधिकार में हुए दुहरे आई ई डी विस्फोटों में एन डी एफ बी तथा इसके सदस्यों की अन्तर्ग्रस्तता का खुलासा होता है।

17. पी डब्ल्यू-6 मि. कालिता ने दिनांक 24.02.2007, 27.02.2007, 24.09.2007, 28.5.2008 और 29.07.2008 को उनके क्षेत्राधिकार में हुई हत्याओं एवं अपहरण की 5 घटनाओं के संबंध में साक्ष्य दिया है। पी डब्ल्यू-6 ने अपने हलफनामों के साथ इन 5 मामलों की प्राथमिकियों की प्रतियाँ तथा इन मामलों की जाँच-पड़ताल के दौरान जाँच अधिकारी द्वारा रिकार्ड बयानों की प्रतियाँ संलग्न की हैं। उन्होंने साक्ष्य दिया कि इन सभी 5 मामलों की केस डायरियों का अध्ययन करने से एन डी एफ बी तथा इसके सदस्यों की हत्या करने, हमला करने, अपहरण करने, जबरन धन वसूली करने और अवैध हथियार रखने आदि सहित अन्य विधि विरुद्ध क्रियाकलापों में संलिप्तता उदघाटित होती है।

18. पी डब्ल्यू-7 मि. कृष्ण कुमार शर्मा ने अपने हलफनामा ई एक्स. पी डब्ल्यू-711 में व्यपहरण, हत्या आदि की कई घटनाओं के साक्ष्य दिए हैं जो उनके



क्षेत्राधिकार में अप्रैल 2007 से जुलाई 2008 के बीच विभिन्न तारीखों को हुई थी। उन्होंने साक्ष्य दिया कि दिनांक 03.04.2007 को अपराह्न लगभग 12.30 बजे 45 वर्षीय रोमेश नरजारी की चार संदिग्ध एन डी एफ बी काडरों ने उनके घर में उनकी हत्या कर दी और (पुलिस थाना हावड़ाघाट के मामले सं. 27/07) हत्या के इस मामले की जाँच के दौरान यह उजागर हुआ कि (i) रुद्र बसुमतारी (ii) बाना बसुमतारी (iii) लैचोन (iv) डोकमाई और (v) श्री मार नामक एन डी एफ बी के पाँच काडर इस घटना में संलिप्त थे और प्राथमिकी में उनका नाम अभियुक्त के रूप में दर्ज किया गया था।

19. पी डब्ल्यू-7 ने आगे साक्ष्य दिया कि दिनांक 12.03.2008 को संदिग्ध एन डी एफ बी के काडरों ने थाना हावड़ाघाट के क्षेत्राधिकार में आने वाले लैन्घिन ईटापारा क्षेत्र से बिन्दा गौड़ नामक एक 22 वर्षीय व्यक्ति का व्यपहरण कर लिया। एन डी एफ बी कारबी आंगलांग जिले में सेकेण्ड-एन-कमाण्ड, बिस्टु बसुमतारी उर्फ रन्जन बसुमतारी, जिसे 23.03.2008 को डोकमोका पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया, उसके अपराध स्वीकृति बयान के आधार पर डोकमोका पुलिस ने दिनांक 31.3.2008 को उसके द्वारा बताए गए स्थान से बिन्दा गौड़ का मृत शरीर खोज निकाला। इस शव को एक मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में जमीन के अंदर से खोदकर निकाला गया। उपर्युक्त बिन्दा गौड़ के व्यपहरण तथा उसकी हत्या करने की इस घटना के संबंध में थाना हावड़ाघाट में मामला संख्या 21/2008 दर्ज कर लिया गया। पी डब्ल्यू-7 ने साक्ष्य दिया कि जाँच के दौरान तथा गवाहों के बयान के आधार पर यह खुलाशा हुआ कि बिन्दा गौड़ की हत्या एन डी एफ बी काडरों ने ही की।

20. पी डब्ल्यू-7 ने यह भी साक्ष्य दिया कि 6/7.07.2008 की मध्यस्थ रात्रि में प्रातः लगभग 12.30 बजे मणिकपुर गाँव के राबिन बसुमतारी ने डोकमोका आउटपोस्ट को सूचित किया कि एक दिन जब उसने गोली चलने की आवाज सुनी तो वह एक टार्च लाइट लेकर बाहर आया और उसने संदिग्ध एन डी एफ बी काडर के कुछ अज्ञात बदमाशों को उस पर गोली चलाते देखा जिसके कारण उसके बाएं हाथ और पैर में गोलियाँ लग गईं। यह उद्घाटित किया गया कि उक्त घटना में समर बसुमतारी के नेतृत्व में एन डी एफ बी गुप्त अन्तर्ग्रस्त था। आशु बसुमतारी उर्फ रिबिसन नामक एन डी एफ बी के एक काडर को डोकमोका पुलिस तथा 20 बटालियन सी आर पी एफ द्वारा गिरफ्तार किया गया। पी डब्ल्यू-7 के

साक्ष्य के मुताबिक यह गिरफ्तार एन डी एफ बी काडर शिकायतकर्ता राबिन बसुमतारी पर गोली चलाने की घटना में संलिप्त था।

21. पी डब्ल्यू-7 ने आगे इस तथ्य का साक्ष्य दिया कि दिनांक 13.07.2008 का सायं लगभग 7.30 बजे कुछ उग्रवादियों ने हावड़ाघाट पुलिस थाना के अन्तर्गत स्थित पूर्व बी एल डी कल्याण समिति के लैण्डिंग स्थित कार्यालय के पिछवाड़े की ओर एक हथगोला रखा जिसका विस्फोट हो गया। इन उग्रवादियों ने पूर्व - बी एल टी कल्याण समिति कार्यालय पर स्वचालित हथियारों से अंधाधुंध गोलियाँ चलाई। पी डब्ल्यू-7 के अनुसार दिनांक 13.07.2008 की घटना दर्शाती है कि एन डी एफ बी काडर सामान्य जनजीवन में शामिल होने वाले आत्मसमर्पण किए उग्रवादियों को डराने में नियमित रूप से संलिप्त हैं। उन्होंने अपने हलफनामा में कहा कि दिनांक 13.07.2008 की घटना और पूर्व बी एल टी शिविर पर हमला करने की घटना एन डी एफ बी काडरों का सशक्त संदिग्ध कारनामा है जैसा कि अपुष्ट आसूचना इनपुटों से ज्ञात हुआ है। पी डब्ल्यू-7 के अनुसार एक गवाह ने बयान दिया कि दिनांक 13.07.2008 की रात्रि को पूर्व बी एल टी कल्याण समिति, लैण्डिंग के कार्यालय के पिछवाड़े की ओर जो विस्फोट हुआ था उसमें अधिकतम एन डी एफ बी काडर संलिप्त थे।

22. पी डब्ल्यू-7 ने अपने हलफनामा में आगे बताया कि इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए कि कुछ संदिग्ध एन डी एफ बी काडर पनबाली बेल्लोला, मिथिफंग और आर्टगसो कचारीगाँव क्षेत्र में शरण लिए हुए हैं, उसने अपने स्टाफ के साथ उक्त क्षेत्रों में छापा मारा/तलाशी अभियान चलाया और वहाँ से (i) भरत बसुमातारी (ii) श्री मोहेश्वर बोरो उर्फ टुटु (iii) श्री लोगान बसुमातारी (iv) श्री स्वप्न बोरो (v) श्री सिराज मोशहारी और (vi) श्री बाबूलाल हस्नू नामक एन डी एफ बी उग्रवादियों को गिरफ्तार किया तथा वह उन सबको पुलिस थाना डिफु लेकर आया जहाँ पुलिस ने उनके पास से एन डी एफ बी उग्रवादियों से संबंधित अभिशंसात्मक दस्तावेज बरामद किए। पुलिस द्वारा बरामद किए गए अभिशंसात्मक दस्तावेज में 10 धनकर्षण नोट वाउचर विवरण, व्यय आदि युक्त एक डायरी तथा भरत बसुमतारी तथा मोहेश्वर बोरो से क्रमशः सिम सं. 9854415516, एवं 9435574296 वाला एक मोबाइल हैंडसेट शामिल हैं। दिनांक 06.05.2007 की इस घटना के संबंध में एक मामला सं. 84/2007 दिनांक 08.05.2007 को थाना डिफु के क्षेत्राधिकार में दर्ज किया गया।

23. पी डब्ल्यू-7 मि. शर्मा ने अपने हलफनामों में कुछ अन्य घटनाओं का साक्ष्य भी दिया है। उन्होंने उल्लेख किया कि संदिग्ध एन डी एफ बी उग्रवादियों में सुनील रुसित को डिफु थाना अन्तर्गत पनवाड़ी डिफु के पुल के निकट बुलाया, उसकी इस सूचना पर कार्य करते हुए 15.3.2008 को अपराह्न लगभग 12.30 बजे डिफु पुलिस उस स्थान पर गई तथा वहाँ पुलिस को देखकर तीन संदिग्ध एन डी एफ बी उग्रवादी घने जंगलों की आड़ में नजदीक की पहाड़ी की ओर भाग गए और यह देखने पर कि पुलिस उनका पीछा कर रही है उन्होंने पुलिस दल पर गोली चलाना शुरू कर दिया इस पर पुलिस ने जवाबी फायरिंग की जिसके परिणामस्वरूप इस गोलीबारी में संदिग्ध एन डी एफ बी काडर का एक अज्ञात व्यक्ति मारा गया तथा शेष दो वहाँ से भाग गए। इस संदिग्ध एन डी एफ बी काडर के अज्ञात मृतक के पास से तलाशी के दौरान एक राउण्ड जिन्दा एम्यूनिशन से लोडेड “32 पिस्तौल, एक चीनी हथगोला तथा एक मोबाइल फोन बरामद किया गया और इन मदों को पी डब्ल्यू-7 के हलफनामा के साथ संलग्न जब्ती सूची, अनुलग्नक 18.(कौली) के रूप में, के अनुसार विधिवत जब्त कर लिया गया। इस मृतक उग्रवादी की बाद में पनवाड़ी गाँव के स्वपन स्वर्गियारी के रूप में शिनाख्त हुई। दिनांक 15.03.2008 की उपर्युक्त घटना के संबंध में थाना डिफु में एक मामला सं. 47/08 दर्ज किया गया।

24. एक आसूचना पर कार्रवाई करते हुए कि शायद एन डी एफ बी काडर धन वसूलने आ रहे हैं जिसकी उन्होंने श्री जे.के. बर्मन, प्रधानाचार्य, डिफु गवर्नमेंट हायर सेकेण्डरी स्कूल, डिफु से मांग की है, दिनांक 12.04.2008 को प्रातः लगभग 6.15 बजे प्रभारी अधिकारी डिफु थाना अपने स्टाफ के साथ उक्त स्कूल की बाउण्ड्री पर गणेश डेका तथा अन्यो के घर के पास छिपकर बैठ गए। जब यह पार्टी छुपकर बैठी थी तभी दो संदिग्ध एन डी एफ बी काडर उस मार्ग पर आए तथा पुलिस कार्मिकों को सादे कपड़ों में देखकर सादे कपड़े पहने लोगों पर उन्हें पुलिस कार्मिक मानते हुए, इन उग्रवादी काडरों ने गोली चला दी। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करने के लिए उनका पीछा किया और उन दो अतिवादियों में से एक को जिसने पुलिस पर हथगोला फेंकने की कोशिश की थी, आत्मरक्षा में मार गिराया। अन्य आतंकवादी आस-पास की बस्ती में छिपते-छिपाते बचकर भाग निकला। बाद में पुलिस ने मृतक उग्रवादी की जेब से एक चीनी हथगोला और एक मोबाइल हैंड सेट (नोकिया-5300) सं. 9859381016 जब्त किया। घटनास्थल की तलाशी लेने पर पुलिस को घटनास्थल से एक अन्य हथगोला

(चीनीमेक) और संदिग्ध एम-20 आग्नेयास्त्र के छह खोखले केस भी मिले और वहाँ से प्राप्त इन मदों को भी डबल्यू-7 के हलफनामा के साथ अनुलग्नक-21 (कोली) के रूप में संलग्न जब्ती सूची के अनुसार विधिवत जब्त कर दिया गया। दिनांक 12.04.2008 की उक्त घटना के संबंध में पुलिस थाना डिफू में एक मामला संख्या 66/2008 दायर कर दिया गया।

25. दिनांक 25.04.2008 को लगभग 6.00 बजे प्रातः, एक बार फिर इस सूचना पर काम करते हुए कि संदिग्ध एन डी एफ बी के बदमाश पी डबल्यू डी (आवास) के कर्मचारी, एंगलांग चिराप निवासी किसी पणिराम बे से जबरन धन वसूली करने के लिए चन्द्र सिंह टेरोन हाई स्कूल के निकट आ रहे हैं डिफू थाने की पुलिस आस-पास के क्षेत्र में पुलिस लगा दी और जबरन धन वसूली करने वाली (1) श्रीमती मुस्कान चौधुरी और (2) श्रीमती मम्पी राय नामक दो महिलाओं को तब गिरफ्तार कर लिया जब वे श्री पणिराम बे से मांगा गया धन लेने आईं। जाँच के दौरान यह पाया गया कि संदिग्ध एन डी एफ बी उग्रवादियों ने पणिराम बे से मोबाइल सं. 9854422208 से फोन पर 2 लाख रुपये की मांग की थी और जबरन धन वसूली करने वाली उपर्युक्त दो महिलाओं को तब गिरफ्तार कर लिया गया जब वे एन डी एफ बी के नाम पर धन वसूलने आईं। ऐसा कहा जाता है कि पुलिस ने उक्त व्यक्ति से धन की मांग करने के लिए काम में लाया गया नोकिया मोबाइल हैंडसेट जिसका सिम. 9854422208 था, अपने कब्जे में ले लिया। यह घटना डिफू थाना के मामला सं. 75/2008 से संबंधित है।

26. दिनांक 05.08.2008 को बड़ी सुबह ही लगभग 2.00 बजे 5वीं बिहार रेजीमेंट शिविर/धंसिरी ने, डिफू थाने के अधिकार क्षेत्र वाले डोलडोली क्षेत्र में तलाशी अभियान चलाते समय एनडीएफबी संवर्गों के दो संदिग्ध लोगों नामतः (1) पोबित्र वासुमतारी और (2) अबिता मुशहारी को डोलडोली रेलवे स्टेशन के निकट एक स्थान से गिरफ्तार किया और एक 9 एम एम रिवाल्वर वरामद की जो गोलीबारूद के 4 राउंड से भरी थी। यह मामला शस्त्र अधिनियम की धारा 25(1-बी)/35 के तहत पी एस डिफू में मामला संख्या 143/2008 के रूप में दर्ज है।

27. दिनांक 03.07.2008 को बोकुलिया थानांतर्गत बेंगेनाटी में एनडीएफबी उग्रवादियों की हलचल के बारे में स्रोत सूचना के आधार पर ई/कांय 20 बटालियन सी. आर पी एफ शिविर/ लांघिन ने उस क्षेत्र में पूर्वाह्न 4.00 बजे से

तलाशी अभियान चलाया और एनडीएफबी संवर्ग के एक ज्ञात और वांछित उग्रवादी नामतः अजोय बासुमतारी उर्फ बिंदा को गिरफ्तार किया जो उस समय एनडीएफबी के कारपोरल का रैंक धारण किए हुए था और उससे एक चार्जर के साथ 2 मोबाइल हैंडसेट (नोकिया और स्पाइस) और बिना रजिस्ट्रेशन के एक मोटर साइकल टी वी एस स्टार बरामद किए। यह घटना बोकुलिया पुलिस स्टेशन में धारा 10/13 यू ए (पी) अधिनियम के साथ पठित आई पी सी की धारा 120(बी)/121/121(ए)/122 के तहत मामला सं० 20/08 के रूप में दर्ज है।

28. पी डब्ल्यू-7 श्री के.के. शर्मा ने अपने हलफनामे ईएक्स.पी.डब्ल्यू-7/1 में अभिसाक्ष्य दिया कि उनके अनुसार उल्लिखित सभी घटनाओं से यह सिद्ध होता है कि संघर्ष विराम की भावना के विरुद्ध बड़े पैमाने पर अवैध/आपराधिक क्रियाकलापों में एनडीएफबी संवर्ग संलिप्त थे और इससे यह पता चलता है कि एनडीएफबी के सदस्य अभी भी संघर्ष विराम की निबंधन और शर्तों का उल्लंघन कर अपनी अलगवादी गतिविधियों को जारी रखे हुए हैं। उन्होंने अपने साक्ष्य में दायर अपने हलफनामे के साथ उल्लिखित मामलों की जांच पड़ताल के दौरान पुलिस द्वारा तैयार की गई एफ आई आर और दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न की हैं।

29. पी डब्ल्यू-8 श्री नितुल गोगोई ने अपने हलफनामे ईएक्स.पी.डब्ल्यू-8/1 में यह बताया है कि दिनांक 26.02.2007 को पूर्वाह्न लगभग 5.30 बजे सी आर पी एफ के दो कमांडो के साथ हावराघाट पुलिस स्टेशन की पुलिस ने उस समय बेलटोला बाजार की ओर कूच किया जब उसे इस आशय की गुप्त सूचना मिली कि कुछ सशस्त्र युवा, बेलटोला बाजार के व्यवसायियों को जान से मारने की धमकी दे कर उनसे धन वसूली कर रहे हैं। बेलटोला बाजार पहुंचने पर छापामार दल ने तुरंत ही बाजार का घेराव कर दिया और इसी बीच 3 सशस्त्र युवाओं ने पुलिस दल को लक्ष्य करके अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी और अपने बचाव में पुलिस ने भी जबाबी गोलीबारी कर दी। यह गोलीबारी लगभग 15 मिनट तक चली। इस घटना के बाद बेलटोला बाजार में घटना स्थल पर एक युवा मरा पाया गया। तथापि, यह बताया गया है कि उसके दो साथी घटना स्थल से भाग खड़े होने में सफल हो गए। यह बताया गया है कि तलाशी के दौरान पुलिस ने एक चीनी ग्रेनेड, एक मोबाइल फोन, एक पाकेट डायरी मृत उग्रवादी के कब्जे से बरामद की और घटना स्थल से बरामद की गई इन वस्तुओं को पी डब्ल्यू-8 के हलफनामे के

अनुलग्नक 2,3 और 4 के रूप में सलग्न जल्ती सूचियों के तहत जब्त किया गया था। पी डब्ल्यू-8 ने यह भी बताया कि दिनांक 26.02.2007 की इस घटना में एनडीएफबी के 2 उग्रवादियों नामतः पुलिन बर्मन और रंजय बासुमतारी को गिरफ्तार किया गया था और मृत संतोष बासुमतारी के साथ इन दोनों की पहचान, पुलिस दल के स्वतंत्र गवाहों/ सदस्यों द्वारा एनडीएफबी के उग्रवादियों के रूप में की गई थी। यह घटना काकी पुलिस स्टेशन में शस्त्र अधिनियम की धारा 5(1)(ए)/27 के साथ पठित आई पी सी की धारा 387/307 और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 5 के तहत मामला सं० 11/2007 के रूप में दर्ज है।

30. पीडब्ल्यू-9 श्री सुरेन्द्र कुमार ने अपने हलफनामे ईएक्स पी डब्ल्यू-9/1 में निम्नलिखित घटनाओं का साक्ष्य दिया है। दिनांक 21.04.2008 को अपराह्न लगभग 5.20 बजे असम राइफल्स के शिकायतकर्ता मेजर सुनील कुमार ने 5 युवा उग्रवादियों नामतः (i) रिंगखंग बासुमतारी, (ii) नबा डेका, (iii) इश्राइल डोइमरी, (iv) विलियम डोइमरी और (v) बिकी खक्लरी तथा पूरे भरे एक रिवाल्वर, एक 9 एम एम पिस्तौल, 6 राउंड गोली से भरी एक मैग्जीन, 2 मोटर साइकल, 2 मोबाइल फोन, 5 सिम कार्ड, नकदी और भूटानी मुद्रा और कुछ अन्य आपत्तिजनक दस्तावेज सोनितपुर जिले के अधिकार क्षेत्र वाले मिसामरी थाने की पुलिस को सौंपे। शिकायतकर्ता मेजर सुनील कुमार ने आपत्तिजनक सामग्री के साथ गिरफ्तार किए गए जिन युवा उग्रवादियों और गोली बारूद को मिसामरी थाने की पुलिस को सौंपा था उन्हें उस दिन शिकायतकर्ता ने गांव बसबेरा में कुछ सशस्त्र युवाओं की हलचल के बारे में स्रोत सूचना मिलने पर गांव बसबेरा में उनके द्वारा चलाए गए अभियान में कथित रूप से जब्त किया था। मिसामरी थाने की पुलिस ने जब उक्त 5 युवा उग्रवादियों से पूछताछ की तो यह बताया गया कि सभी उग्रवादियों ने कथित रूप से यह बात स्वीकार की है कि वे एनडीएफबी के उग्रवादी हैं। इस संबंध में मिसामरी थाने में उक्त नामित अभियुक्तों (युवा उग्रवादी) के विरुद्ध शस्त्र अधिनियम की धारा 25(I-ए) के साथ पठित आई पी सी की धारा 120 (बी) के तहत मामला सं० 15/2008 के रूप में दर्ज है।

31. दिनांक 30.04.2008 को पूर्वाह्न 7.00 बजे शिकायतकर्ता नायब सुबेदार आई.बी.थापा ने बेहली थाने की पुलिस को 7 युवा नामतः (1) धर्मेश्वर बासुमतारी, (2) तपन डोइमरी, (3) सुबोध बासुमतारी, (4) परसुराम बासुमतारी, (5)

सीलफा नरजरी, (6) संजोय नरजरी और (7) अमित खक्लरी सौंपे। उन्होंने बेहली थाने की पुलिस में एक एफ आई आर दर्ज की जिसमें यह बताया गया था कि दिनांक 29.04.2008 को क्षेत्र की गश्त लगाने के लिए वे गांव डिश्री में थे और उस दौरान उन्हें इस आशय की सूचना मिली कि सात संदिग्ध युवाओं ने गांव डिश्री के कमल डोड़मरी नामक व्यक्ति के मकान में आश्रय लिया हुआ है। उन्होंने उक्त मकान की तलाशी ली और एफ आई आर दर्ज करते समय उन्होंने गिरफ्तार किए गए 7 युवाओं को पुलिस को सौंप दिया। उन्होंने एफ आई आर में यह भी बताया कि उन्होंने जिन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था उनसे एक नोकिया मोबाइल फोन और 3570/-रुपए नकद भी बरामद हुए। शिकायतकर्ता ने एफ आई आर में पुलिस को बताया कि उनके द्वारा गिरफ्तार किए गए उक्त नाम वाले सात व्यक्तियों ने यह बताया कि वे एनडीएफबी के उग्रवादी हैं और संगठनात्मक कार्यों के लिए उन्हें गांव डिश्री में भेजा गया था। उनके कब्जे से जो राशि बरामद की गई है उसके बारे में यह बताया गया है इसे एक ठेकेदार से जबरन वसूला गया था। शिकायतकर्ता नायब सुबेदार आई.बी. थापा द्वारा दिनांक 30.04.2008 को दायर की गई यह शिकायत बेहली थाने में एफ आई आर मामला सं० 88/2008 के रूप में दर्ज है।

32. दिनांक 16.06.2008 को अपराहन लगभग 2.45 बजे शिकायतकर्ता सुश्री रैमली खक्लरी ने रंगपाड़ा थाने की पुलिस को इस आशय की लिखित रिपोर्ट दी कि दिनांक 15.06.2008 को अपराह्न 6/7 बजे उनका केंजिन श्री बीरू बासुमतारी अपने दोस्त श्री प्रोनोय बासुमतारी के साथ पंजीकरण सं० ए एस-12-सी/6544 वाली मोटर साइकल से अपने गांव रंगपाड़ा की ओर आ रहा था। वे उरहिलोगा एल.पी. स्कूल के निकट थे। एनडीएफबी संवर्ग डोंडा ने अपने दो सहयोगियों के साथ शिकायतकर्ता के भाई और प्रोनोय बासुमतारी को रोका और कहा कि वे उनसे कुछ बातचीत करना चाहते हैं। प्रोनोय बासुमतारी से कहा गया कि वह एनडीएफबी के एक उग्रवादी के साथ वहीं पर रहे जब कि बीरू बासुमतारी को किसी दूसरी जगह ले जाया गया। बाद में उसी रात प्रोनोय बासुमतारी को मोटर साइकिल लौटाई गई लेकिन दिनांक 16.06.2008 को एफ आई आर लिखे जाने तक बीरू बासुमतारी नहीं लौटा था। बीरू बासुमतारी का शव गांव मनावोश्री के जंगल से बरामद किया गया। यह घटना आई पी सी की धारा 341/365/34 के साथ जुड़ी आई पी सी की धारा 302/201 के तहत दिनांक 16.06.2008 को रंगपाड़ा मामला सं० 95/08 के रूप में दर्ज है।

33. पी डब्ल्यू-11 श्री सैयद अतुल करीम ने अपने साक्ष्य में दायर अपने हलफनामे में कहा है कि दिनांक 26.02.2008 को अपराह्न लगभग 12.30 बजे नारायणपुर वाह्य चौकी का एक पुलिस दल अलगाववादी तत्वों की हलचलों और क्रियाकलापों की जांच करने के लिए नारायणपुर में नाका-चैकिंग की इ्यूटी कर रहा था। लगभग उसी समय लखीमपुर की तरफ से नारायणपुर की ओर आ रही पंजीकरण सं० ए एस-01-एक्स-5629 वाली एक इंडिका कार को रोका गया और पुलिस ने उसकी जांच की। कार के अंदर 5 लोग थे। उक्त वाहन की तलाशी के दौरान उक्त ग्रुप के कब्जे से एक मैग्जीन, 78,083.00/- नकद, 6 मोबाइल फोन, 9 सिम कार्ड और एक कैमरे के साथ एक पिस्तौल (अमरीका में निर्मित सं० 2211) जब्त की गई। उन युवाओं ने यह स्वीकार किया कि वे एनडीएफबी संगठन के सक्रिय सदस्य हैं। पी डब्ल्यू-11 ने बताया कि इस मामले की आगे की गई जांच-पड़ताल से यह पता चला है कि इंडिका कार में सवार जिन युवाओं को जांच चौकी पर रोका गया था वे एनडीएफबी संगठन के लिए लोगों से जबरन धन ऐंठने की घटनाओं में संलिप्त थे। गिरफ्तार किए गए एनडीएफबी के सदस्य हैं: (1) पुंज बासुमतारी, (2) राजेश मोचाहारी, (3) बिबुंग बासुमतारी (4) लोहीराम स्वर्गियारी और (5) बिनोश नाके। जांच-पड़ताल के दौरान 8 गवाहों के बयान रिकार्ड किए गए और उन्होंने गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान, एनडीएफबी संवर्गों के रूप में की थी तथा यह बताया गया कि उन्होंने शस्त्र अधिनियम की धारा 25(1-ए) के साथ पठित आई पी सी की धारा 384 और 10/13 यू ए (पी) अधिनियम के तहत दिनांक 27.02.2008 को दर्ज की गई एक आई आर मामला सं० 65/2008 की विषय-वस्तु से सहमति प्रकट की है।

34. पी डब्ल्यू-12 श्री राणा भुयान ने अपने हलफनामा ईएक्स. पी डब्ल्यू-12/1 में बताया है कि बक्स जिले में एनडीएफबी के सदस्य बहुत सक्रिय हैं तथा वे सरकार के प्राधिकार को नकारते हुए बड़े पैमाने पर विधि विरुद्ध और हिंसात्मक क्रियाकलापों में संलिप्त रहते हैं और लोगो में भय फैला रहे हैं और एनडीएफबी के जिन कार्यकर्ताओं ने समर्पण कर दिया है तथा बी एल टी के भूत-पूर्व सदस्यों, सिविलियनों, गैर-बोडो लोगों को भी अपना निशाना बना रहे हैं और सामान्य जीवन में अत्यधिक बाधा पहुंचा रहे हैं। यह बताया गया है कि बारबरी थानांतर्गत धनबिल में स्थित एनडीएफबी के नामित शिविर के उग्रवादी, संघर्ष विराम का आश्रय लेकर बड़े पैमाने पर हिंसा कर रहे हैं।



35. पी डब्ल्यू-12 ने बताया है कि एनडीएफबी के संवर्गों को अक्सर मूल नियमों का उल्लंघन करते हुए पकड़ा जाता है और वे नामित शिविर का प्रबंधन करने के लिए संयुक्त निगरानी समिति (जे एम सी) द्वारा तैयार और अनुमोदित "मानक परिचालन प्रक्रिया (एस ओ पी) का पालन भी नहीं करते हैं। पी डब्ल्यू-12 की सूचना के अनुसार एनडीएफबी के जो सदस्य नामित शिविरों के अंदर और बाहर रहते हैं उन्होंने अलग-अलग तरह के घिनौने अपराध किए हैं जिसकी परिणति संबंधित समयावधि के दौरान विधि-विरुद्ध क्रियाकलाप किया जाना है और ऐसे आपराधिक क्रियाकलापों के कारण अलग-अलग थानों में उनके विरुद्ध कई मामले दायर किए गए हैं तथा समय-समय पर काफी संख्या में एनडीएफबी कार्यकर्ता गिरफ्तार किए गए हैं। एनडीएफबी संवर्गों के विधि विरुद्ध क्रियाकलापों की निम्नलिखित घटनाओं के संबंध में पीडब्ल्यू-12 ने अपने हलफनामे में विशिष्ट साक्ष्य दिए हैं।

36. दिनांक 07.08.2008 को श्री फुलेन ब्रह्मा ने तमुलपुर थाने में इस आशय की एफ आई आर दर्ज कराई कि उसी दिन अपराह्न लगभग 12:30 बजे एनडीएफबी के 4 अज्ञात कार्यकर्ताओं नामतः 1) श्री विपुल बोरो, 2) श्री रत्नेश्वर बोरो, 3) श्री मोनिल डैमरी और 4) श्री केदार बोरो ने उनके भाई श्री सोमेश ब्रह्मा पर गांव कट्टीबारी में उस समय अचानक हमला कर दिया जब उनका भाई एक और व्यक्ति के साथ लोटीबारी बाजार से मोटर साइकल पर घर लौट रहा था। उनके भाई को घटना स्थल पर ही गोली से मार दिया गया। दूसरे व्यक्ति श्री विश्व गोयरी इस हमले में गंभीर रूप से घायल हो गए और इलाज के लिए उन्हें गुवाहाटी मेडिकल कालेज अस्पताल, गुवाहाटी भेजा गया। दिनांक 07.08.2008 की इस घटना को तमुलपुर थाने की पुलिस में शस्त्र अधिनियम की धारा 25(1-बी)/27 के साथ पठित आई पी सी की धारा 307/326/302/34 के तहत मामला संख्या 134/2008 के रूप में दर्ज किया गया है।

37. दिनांक 18.06.2008 को अपराह्न लगभग 2.00 बजे श्री बेठल मुशारी ने तमुलपुर थाने की पुलिस में इस आशय की एफ आई आर दर्ज कराई कि दिनांक 17.06.2008 को अपराह्न 7:40 बजे जब श्री राजा बासुमतारी और श्री भीम बोरो, बी पी एफ (युवा) कार्यालय, दारंगमेला में रात्रि भोजन करने के बाद लौट रहे थे तो एनडीएफबी के कुछ सदस्यों ने एन. के. दारंग बाजार के निकट उन्हें जबरन रोका और अधुनातन हथियारों से गोलीबारी करके उनकी हत्या कर दी

तथा अपराध करने के बाद वे मोटर साइकल पर बोगजुली क्षेत्र की ओर चले गए। इस घटना के संबंध में तमुलपुर थाने में शस्त्र अधिनियम की धारा 25(1-बी)/27 के साथ पठित आई पी सी की धारा 302/34 के तहत मामला सं० 101/08 दर्ज है। इस मामले की जांच-पड़ताल के दौरान जांचकर्ता अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए गवाहों के बयानों से यह पाया गया कि एनडीएफबी के 4 कार्यकर्ता नामतः (1) जाला गोयरी, (2) रिलेशन बोरो, (3) सुकुर सिंह बासुमतारी और (4) रतन बासुमतारी, दिनांक 17.06.2008 को राजा बासुमतारी और भीम बोरो की हत्या की घटना में संलिप्त थे जिसके लिए दिनांक 18.06.2008 को मामला सं० 101/2008 दर्ज किया गया था।

38. दिनांक 05.10.2008 को मो० सरबेस अली ने तमुलपुर थानांतर्गत नगरिजुली बाह्य पुलिस चौकी में इस आशय की एफ आई आर दर्ज की कि उस दिन उनकी पत्नी सरबानु बेगम (लगभग 24) और उनका पुत्र मो० सिराज अली अपने छोटे भाई मो० मंशर अली के साथ सं० 2 पीपलसी गांव में एक विवाह समारोह में शामिल होने जा रहे थे जब अंथैबारी गांव के निकट दो अज्ञात बड़ो युवाओं ने उनकी पत्नी के साथ छेड़खानी की। उनका छोटा पुत्र मो० मंशर अली किसी तरह बच निकलने में सफल हो गया। बाद में मंशर अली कुछ पड़ोसियों के साथ वहां आया और वहां उसने देखा कि सरबानु बेगम और उनके पुत्र को किसी तेज धार वाले हथियार से काटा गया है और वे जमीन पर पड़े हैं। बाद में लगभग 12.00 बजे उसे पता चला कि पुलिस और सेना के संयुक्त अभियान में दो व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं और उसके छोटे भाई मंशर अली ने इन दोनों की पहचान ऐसे व्यक्तियों के रूप में की जो शिकायतकर्ता की पत्नी और उनके पुत्र की हत्या में संलिप्त थे और पी डब्ल्यू-12 के हलफनामे में यथा उल्लिखित गिरफ्तार किए गए इन व्यक्तियों के नाम (1) जबरंग बोरो और (2) दहर बोरो हैं। इस घटना के संबंध में तमुलपुर थाने में आई पी सी की धारा 302/34 के तहत मामला संख्या 169/08 दायर किया गया है और इस मामले की जांच-पड़ताल के दौरान लिए गए गवाहों के बयानों से यह पता चलता है कि पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए उक्त नाम वाले दोनों व्यक्ति एनडीएफबी सदस्य हैं।

39. पी डब्ल्यू-13 श्री वीर बिक्रम गोगोई ने अभिकरण में दायर किए गए अपने हलफनामे ईएक्स.पी.डब्ल्यू-13/1 में उन तीन अपराधों का साक्ष्य दिया है

जो उनके अधिकार क्षेत्र में हुए हैं। अपने हलफनामे में उनके द्वारा बताए गए ये अपराध निम्नानुसार हैं:

40. दिनांक 03.06.2007 को श्री रोमेश बोरो ने इस आशय की एफ आई आर दर्ज करवाई कि दिनांक 02.06.2007 को अपराह्न लगभग 8:00 बजे एनडीएफबी के लगभग 7/8 उग्रवादी उनके घर में घुसे और उनके भाई श्री सुरेश बोरो को पकड़ा तथा उसे लोहे की छड़, दाव और लाठी से बुरी तरह से पीटा और अत्यंत खराब हालात में उसे सड़क पर छोड़ दिया। बाद में गुवाहाटी ले जाते समय सुरेश बोरो (शिकायतकर्ता का भाई) की घायलावस्था में मृत्यु हो गई। जांच-पड़ताल के दौरान पुलिस ने घटनास्थल से बांस की दो लाठियां और लोहे की छड़ का एक टुकड़ा बरामद किया जिनके बारे में यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि अभियुक्तों ने अपराध करते समय इनका प्रयोग किया हो। जांच-पड़ताल के दौरान यह पाया गया कि एनडीएफबी के उग्रवादी इस मामले में प्रत्यक्ष रूप से संलिप्त थे जो विभिन्न गवाहों द्वारा दिए गए बयानों से भी साबित होता है। यह अपराध, आई पी सी की धारा 147/452/325/326/365/302 के तहत दिनांक 03/06/2007 को मेरापाती मामला सं० 42/07 के रूप में दर्ज है।

41. यह बताया गया है कि दिनांक 08.05.2007 को एनडीएफबी के दो उग्रवादी हल्दीबारी गांव आए और उन्होंने दुकानदारों और ग्रामीणों से 20000/- रुपए की मांग की। अगली बार दिनांक 16.05.2007 को पूर्वाह्न लगभग 6 बजे एनडीएफबी के उक्त सदस्य शिकायतकर्ता श्री बाबू कुमार पुत्र श्री कुलु कुमार के घर आए और उनसे उक्त राशि का भुगतान करने की मांग की। इस पर शिकायतकर्ता ने शोर मचाया जिसे सुन कर गांव के लोग वहां पर एकत्र हुए और उन्होंने एनडीएफबी के दो सदस्यों को पकड़ लिया और जब उनसे पूछताछ की गई तो उनकी पहचान (1) श्री जितेन बासुमतारी और (2) श्री रमेश खकलरी के रूप में की गई। घटना स्थल से गिरफ्तार किए गए इन अभियुक्तों से जब पूछताछ की गई तो उन्होंने यह बात स्वीकार की कि वे प्रतिबंधित एनडीएफबी संगठन के दुर्दांत उग्रवादी हैं। इस मामले में जांचकर्ता अधिकारी द्वारा गवाहों के दर्ज किए गए बयान से यह स्पष्ट होता है कि उक्त नाम वाले दोनों व्यक्ति प्रतिबंधित एनडीएफबी संगठन के सदस्य हैं और वे क्षेत्र में भय फैलाने के लिए अपने विधि विरुद्ध क्रिया कलाप जारी रखे हुए हैं। यह घटना, यू ए (पी)

अधिनियम की धारा 10/13 के साथ पठित आई पी सी की धारा 384 के तहत दिनांक 16.05.2007 को मामला सं० 56/07 के रूप में सरूपथर थाने में दर्ज है।

42. दिनांक 13.12.2008 को श्री दीपक कुमार तिवारी, सेक्टर कमांडर, 155 बटालियन सी आर पी एफ, रंगापानी ने इस आशय की एफ आई आर दर्ज करवाई कि जब उसी दिन यह सूचना मिली कि दीमापुर से पोहोटो गांव की तरफ “ए” सेक्टर में डी ए बी क्षेत्र (असम-नागालैंड के विवादित क्षेत्र की बेल्ट) में कुछ संदिग्ध उग्रवादी घुस रहे हैं तो यह सूचना तत्काल ही एस डी पी ओ सरूपथर, ओ/सी सरूपथर और सी आर पी एफ के वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई। सूचना मिलने के बाद उक्त अधिकारियों ने लगभग 1120 बजे उपलब्ध बलों के साथ पोहोटो गांव की ओर कूच किया। उस समय पंजीकरण सं० एन एल-07/3673 वाला एक ऑटो-रिक्शा दीमापुर की ओर से आ रहा था। जब पुलिस- सी आर पी एफ दल ने ऑटो-रिक्शा को रूकने का संकेत दिया तो उस ऑटो-रिक्शा में सवार तीन अज्ञात युवा उस ऑटो-रिक्शा से बाहर कूद पड़े और उन्होंने पुलिस-सीआरपीएफ दल पर गोलीबारी कर दी। इस गोलीबारी का जवाब देने और अपनी रक्षा के लिए पुलिस-सीआरपीएफ दल ने उन पर गोलीबारी कर दी। यह गोलीबारी 15 मिनट तक चली और इसके परिणामस्वरूप एक युवा, बाद में जिसकी पहचान जोय चरण मुसाहरी पुत्र बिजोय मुसाहरी के रूप में की गई और जो एनडीएफबी का दुर्दांत उग्रवादी था, गोलियां लगने के कारण घायल हो गया। इलाज के लिए उसे तत्काल बोकाजन पी एच सी भेजा गया। एनडीएफबी के अन्य दो उग्रवादी जंगल की आड़ में भागने में सफल हो गए। तलाशी के दौरान इटली में निर्मित एक 32 पिस्तौल और 3 राउंड जीवित गोलीबारूद बरामद किया गया। घायल हुए जोय सरण मुसाहरी का बोकाजन पी एच सी में प्राथमिक इलाज करने के बाद उसका बेहतर इलाज करने के लिए उसे गोलाघाट सिविल अस्पताल भेजा गया। जब वह इस अस्पताल पहुंचा और सिविल अस्पताल गोलाघाट के डाक्टर आए तो उन्होंने उसे मृत लाया गया घोषित कर दिया। जांच पड़ताल के दौरान यह पाया गया कि जोय सरण मुसाहरी पुत्र बिजोय मुसाहरी, एनडीएफबी का सक्रिय सदस्य था और गोलाघाट जिले का एरिया कमांडर था। अमर बासुमतारी और देबलाल नामक उसके दो अन्य सहयोगी भी एनडीएफबी के सक्रिय सदस्य थे। जांच पड़ताल के दौरान यह भी पता चला कि एनडीएफबी का मृतक और भगोड़ा उग्रवादी अपहरण के कई मामलों में संलिप्त था। यह मामला शस्त्र अधिनियम की धारा 25(1)(ए)/27 और यू ए (पी)

अधिनियम की धारा 10/13 के साथ पठित आई पी सी की धारा 120(बी)/353.307 के तहत दिनांक 13.12.2008 को मामला सं० 121/08 के रूप में सरूपथर थाने में दर्ज है।

43. पी डब्ल्यू-13 ने दायर किए गए अपने हलफनामे में यह साक्ष्य दिया है कि उन्होंने सभी तीन आपराधिक मामलों की केस डायरियां देखी हैं और उनके अनुसार उनका अध्ययन करने पर इन केस डायरियों से यह पता चलता है कि एनडीएफबी के सदस्य जबरन धन बसूलने, अपहरण करने, हत्या करने, अवैध रूप से हथियार और गोलीबारूद रखने, हत्या, आतांकित आदि करने सहित विधि विरुद्ध क्रियाकलापों में संलिप्त थे और इस तरह वे भारत सरकार, असम सरकार और एनडीएफबी के बीच दिनांक 01.06.2005 को हुए अभियान स्थगन करार के मूल नियमों का उल्लंघन कर रहे थे।

44. पी डब्ल्यू-14 श्री आनंद प्रकाश तिवारी ने दायर किए गए अपने हलफनामे ईएक्स. पी डब्ल्यू -14/1 में अभिकरण के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत किया जिसमें असम राज्य के दूसरे जिलों के पुलिस अधीक्षकों द्वारा दिए गए साक्ष्यों का समर्थन किया गया था। उन्होंने अपने हलफनामे में यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि एनडीएफबी संगठन पूरी तरह से सक्रिय है और इसके सदस्य राज्य के विरुद्ध लड़ाई लड़ने के साथ-साथ बड़े पैमाने पर विधिविरुद्ध क्रियाकलापों में भी संलिप्त हैं।

45. पी डब्ल्यू-14 श्री तिवारी ने अपने हलफनामे में कुछ दृष्टांतों/मामलों का उल्लेख किया है जिनमें एनडीएफबी के सदस्यों को विधिविरुद्ध क्रियाकलापों संलिप्त पाया गया। उनके द्वारा उल्लिखित ये दृष्टांत/मामले निम्नवत् हैं:

- (i) ओदलगुरि थाने में आई पी सी की धारा 147/148/341/353/387/435/427 के तहत मामला सं० 24/2008, घटना की तारीख: 29.02.2008, समय: पूर्वाह्न 7.30 बजे, घटनास्थल: गोलांडी पुल, ओदलगुरि। यह बताया गया है कि इस घटना की तारीख और समय अभियुक्त हुलुंगा नरजरी उर्फ हबीला नरजरी, जो गोहपुर थाना, जिला सोनितपुर के निकट स्थित एनडीएफबी शिविर का सदस्य था, ने 10/11 अन्य लोगों के साथ शिकायतकर्ता को सरकारी इयूटी पर जाने से गलत ढंग से रोके रखा और उनकी मोटरसाइकल को जबरन छीनने की बाद उसे जला दिया।

- (ii) आई पी सी की धारा 147/148/448/427/353/224/325 के तहत ओदलगुरि मामला सं० 26/08, घटना की तारीख: 01.03.2008, समय: अपराह्न 2.30 बजे, घटना स्थल: पी एस आई कोर्ट, ओदलगुरि, शिकायतकर्ता: ए एस आई उत्तम बोरा, ओदलगुरि थाना। यह बताया गया है कि घटना की तारीख को जब अभियुक्त हुलुंगा नरजरी उर्फ हबीला नरजरी को पी एस आई कोर्ट ओदलगुरि ले जाया गया तो एनडीएफबी के लगभग 20 उग्रवादी पी एस आई कोर्ट के अंदर आपराधिक आधार पर घुस गए और गिरफ्तार किए गए अभियुक्त को जबरन छुड़ा कर ले गए। बाद में उसे फिर गिरफ्तार कर दिया गया। यह बताया गया है कि दूसरे अभियुक्तों को गिरफ्तार किए जाने तक यह मामला लंबित है।
- (iii) शस्त्र अधिनियम की धारा 25(1)(ए) के तहत मजबत थाना का मामला सं० 32/08, घटना स्थल: मेराबिल, घटना की तारीख: 15.05.2008, समय :अपराह्न 10.00 बजे, सूचना देने की तारीख: 16.05.2008, पूर्वाह्न 8.00 बजे। यह बताया गया है कि घटना की तारीख को 46 बटालियन असम राइफल्स, मजबत शिविर ने एनडी एफ बी के (1)श्री हरवम्सा बासुमतारी और (2) श्री जखन नरजरी नामक दो सदस्यों को गिरफ्तार किया था और उनके कब्जे से मैग्जीन के साथ एक 7.65 एम एम ऑटो पिस्तौल, 7.65 एम एम जीवित गोली बारूद (5 नग), एक बजाज पल्सर मोटर साइकल सं० ए एस-01/एसी-1020, सिम कार्ड के साथ एक मोबाइल फोन, उनके पहचान पत्र, 3,000/-रुपए नकद बरामद किए गए। दोनों ही उक्त अभियुक्तों को घटना स्थल से गिरफ्तार किया गया था और बताया गया है कि जांच-पड़ताल के लिए उनके विरुद्ध मामला लंबित है।
- (iv) आई पी सी की धारा 387 के तहत मजबत थाना में मामला सं० 60/08, घटना की तारीख: 10.09.2008, समय: पूर्वाह्न 1:30 बजे, घटना स्थल: जवलिया सेंटर, ओरंग बस्ती, सूचना देने की तारीख: 10.09.2008, पूर्वाह्न 11.00 बजे, शिकायतकर्ता: कैप्टेन सी. शिबु जॉन, "ई" कॉय, 46 बटालियन, असम राइफल्स, शिविर-मजबत, जिला-ओदलगुरि, अभियुक्त: होगम स्वरगियारी। इस मामले का संक्षिप्त विवरण यह है कि दिनांक 10.09.2008 को शिकायतकर्ता को विध्वस्त सूत्रों से यह सूचना मिली कि घटनास्थल के सामान्य क्षेत्र में एनडीएफबी के कार्यकर्ता जबरन धन

वसूली कर रहे हैं और शिकायतकर्ता ने 46 बटालियन असम राइफल्स की “ई” और “सी” कंपनी के साथ तलाशी अभियान चलाया तथा उक्त नामित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया और उनसे एक खुबरी, जबरन धन वसूली की रसीदें और धन राशि के विस्तृत व्यौरे वाली 4 बहियां बरामद की। बताया जाता है कि यह मामला जांचाधीन है।

46. पी डब्ल्यू-14 श्री तिवारी ने उक्त मामलों की केस डायरियों के आधार पर यह बताया है कि एनडीएफबी संगठन और इसके सदस्य, विधि-विरुद्ध क्रियाकलापों में संलिप्त हैं जिनमें जनता पर गोलीबारी करना, हथियार और विस्फोटक पदार्थ अपने पास रखना और राज्य आदि के विरुद्ध लड़ाई लड़ना शामिल है।

47. पी डब्ल्यू-15 श्री पार्थ सारथी महंत ने अपने हलफनामे ‘ईएक्स.पी डब्ल्यू-15/1 में अभिसाक्ष्य दिया है कि उनके जिले अर्थात्, धुब्री जिले में एनडीएफबी के सदस्य बहुत अधिक सक्रिय हैं और वे बड़े पैमाने पर विधि-विरुद्ध क्रियाकलापों में संलिप्त हो करके सरकार के प्राधिकार को नकार रहे हैं तथा लोगों में आतंक फैला रहे हैं तथा राज्य के विरुद्ध लड़ाई छेड़ रहे हैं। श्री महंत ने आगे यह भी बताया कि एनडीएफबी के कार्यकर्ता बोडो लिबरेशन टाइगर (बीएलटी) के उन कार्यकर्ताओं को भी अपना निशाना बना रहे हैं जिन्होंने समर्पण कर दिया है और सामान्य जीवन जीने की राह में अत्यधिक बाधाएँ उत्पन्न कर रहे हैं। उन्होंने अपने हलफनामे में तीन दृष्टांत प्रस्तुत किए हैं जिनमें उनके अनुसार एनडीएफबी संलिप्त है। हलफनामे में उनके द्वारा गिनाये गए मामले निम्नवत हैं:

- (i) दिनांक 12.03.2008 को अपराह्न लगभग 2.00 बजे घातक हथियारों से लैस एनडीएफबी के सशस्त्र युवा सपतग्राम स्थित वन निरीक्षण बंगले में आए जहां पर बोडो लिबरेशन टाइगर (बी एल टी) के कुछ भूत-पूर्व सदस्य और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट (बीपीएफ) की युवा विंग के सदस्य ठहरे हुए थे और उन सशस्त्र युवाओं ने 8/10 राउंड गोलियां हवा में चलाई तथा वन निरीक्षण बंगले पर भी आग लगा दी जिसके कारण यह बंगला पूरी तरह जल कर राख हो गया। जांच-पड़ताल के दौरान गवाहों के बयानों से यह पता चलता है कि एनडीएफबी के कार्यकर्ता नामतः (1) कमल ब्रह्मा, (2) श्री कुमंत ब्रह्मा (3) जसुश ब्रह्मा (4) प्रणो ब्रह्मा, (5) मुक्कल संगमा, 40/45 अन्य सदस्यों के साथ उक्त घटना में संलिप्त थे और यह बताया गया है

कि दोषियों का पता लगाने के लिए जांच-पड़ताल की जा रही है। यह मामला शस्त्र अधिनियम की धारा 25(1) (ए) के साथ पठित आई पी सी की धारा 147/148/149/447/436/427 के तहत दिनांक 12.03.2008 को बागड़ीबारी थाने में मामला सं० 32/08 के रूप में दर्ज है।

- (ii) दिनांक 14.07.2008 को बागड़ीबारी क्षेत्र में एनडीएफबी की हलचल के संबंध में स्रोत सूचना मिलने पर पुलिस और 21 जाट सेना के कार्मिकों ने तलाशी अभियान चलाया/घात लगाई और अपराह्न लगभग 2:17 बजे एनडीएफबी के तीन सदस्य नामतः (1) जयदीप डे, (2) कनिराम बासुमतारी और (3) स्वजल सरकार को बागड़ी बारी थानांगर्तत महामाया मंदिर के निकट एक सांत्रो कार के साथ उन्हें गिरफ्तार किया तथा जयदीप डे (सांत्रो कार पर सवार व्यक्ति) के कब्जे से एक 7.65 एम एम ऑटो पिस्तौल तथा दो राउंड जीवित गोलीबारूद बरामद किया। एनडीएफबी के दो अन्य सदस्य नामतः गोडा नरजरी और लौरी ब्रह्मा को भी उस समय उसी स्थान से एक मोटर साइकल के साथ गिरफ्तार किया गया था जब उन्होंने पुलिस और सेना को देख कर भागने की कोशिश की। जांच पड़ताल के दौरान एक 7.65 एम एम ऑटो पिस्तौल और दो राउंड जीवित गोली बारूद, सांत्रो कार, मोटर साइकल (बजाज पल्सर), दो से मोबाइल फोन और 2000/-रुपये नकद जब्त किए गए। जांचकर्ता अधिकारी द्वारा की गई जांच पड़ताल के दौरान अभियुक्त जयदीप डे ने स्वीकार किया कि वह एनडीएफबी का सदस्य है और जैसा कि ऊपर बताया गया है जब्त किया गया पिस्तौल और गोली-बारूद उसके पास था। यह बताया गया है कि घटना स्थल से गिरफ्तार किए गए दूसरे अभियुक्तों ने भी इस मामले में अपना अपराध स्वीकार किया है। यह मामला शस्त्र अधिनियम की धारा 25(1)(ए)/27 के साथ पठित आई पी सी की धारा 384 के तहत दिनांक 14.07.2008 को बागड़ीबारी थाने में मामला सं० 123/08 के रूप में दर्ज है।

- (iii) दिनांक 12.08.2008 को अपराह्न लगभग 2:00 बजे इस आशय की स्रोत सूचना मिलने पर कि सपतग्राम बाह्य चौकी के अंतर्गत भेलकोबा रिजर्व फारेस्ट (पहाड़ी क्षेत्र) में एनडीएफबी के कुछ उग्रवादी शिविर लगाए हुए हैं, एस डी पी ओ बिलासीपाड़ा, सी.आई.बिलासीपाड़ा, ओ/सी बिलासीपाड़ा के कर्मचारियों ने 21 वीं जाट सेना के कार्मिकों के साथ भेलकोबा वन क्षेत्र में संयुक्त तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान पुलिस ने एनडीएफबी



के (1) ऐली ब्रह्मा (2) श्री माखोंव बासुमतारी, (3) श्री मोकली गोयरी, (4) सिबू वासुमतारी, (5) श्री दन्शाँ खक्लैरी, (6) श्री जितेन बासुमतारी और (7) श्री खर्बू बासुमतारी नामक सदस्यों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए उक्त लड़कों का नेतृत्व दन्शाँ खक्लैरी और जितेन बासुमतारी कर रहे थे और उक्त अस्थाई शिविर से एक ए.के-56 राइफल, जीवित गोलीबारूद के 10 राउंड और 'हीरो होंडा ग्लेमर' मोटर साइकल बरामद और घटना स्थल पर पुलिस द्वारा जब्त किए गए। यह मामला शस्त्र अधिनियम की धारा 25(1)ए के तहत दिनांक 12.08.2008 को बागड़ीबारी थाने में मामला सं० 207/2008 के रूप में दर्ज है।

मजिस्ट्रेट के दिनांक 17.02.2009 के आदेश के तहत अतिरिक्त धारा जोड़ने की अनुमति के अनुसार उल्लिखित सभी मामलों में बाद में यू ए (पी) अधिनियम की धारा 10/13 जोड़ी गई थी और पी डब्ल्यू-15 के हलफनामे में मजिस्ट्रेट के दिनांक 17.02.2009 के आदेश की प्रति अनुलग्नक 'अ' (कोली.) के रूप में संलग्न है।

48. पी डब्ल्यू-3 सुश्री बन्या गोगोई, पुलिस अधीक्षक, विशेष अभियान यूनिट (एस ओ यू), असम हैं और उन्होंने अपने हलफनामे ईएक्स. पी डब्ल्यू-3/1 में कहा है कि अपनी सरकारी इयूटी का निर्वहन करने के रूप में वे पूरे असम राज्य में आतंकवादी क्रियाकलापों पर निगरानी रखती हैं और असम राज्य में कार्यरत प्रतिबंधित एनडीएफबी सहित आतंकवादी संगठनों के विधिविरुद्ध कृत्यों के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और विभिन्न जिलों के सभी पुलिस अधीक्षकों से रिपोर्ट प्राप्त करती हैं। उन्होंने अभिसाक्ष्य दिया है कि इन सूचनाओं के आधार पर वह असम सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती हैं तथा एस पी और एसएसपी के साथ भी सूचना का आदान-प्रदान करती हैं ताकि एनडीएफबी सहित आतंकवादी संगठनों की विधिविरुद्ध गतिविधियों को रोकने के लिए समय पर कार्रवाई की जा सके।

49. पी डब्ल्यू-3, सुश्री गोगोई, के साक्ष्य के अनुसार भारत सरकार, असम सरकार और एनडीएफबी के बीच 6 महीने की अवधि के लिए 1.6.2005 को अभियान स्थगन संबंधी एक करार निष्पादित हुआ था, और इस करार को चरणबद्ध तरीके से इस एक लक्ष्य के साथ बढ़ाया गया था कि क्षेत्र में शांति

व्यवस्था बनी रहे। सुश्री गोगोई ने यह साक्ष्य दिया कि उपरोक्त करार के बावजूद, एनडीएफबी 1.6.2005 को हुई सहमति के अनुसार अभियान स्थगन संबंधी मूल नियमों का उल्लंघन करता रहा है और राज्य के खिलाफ सक्रियता से युद्ध की स्थिति पैदा करता रहा है। उपरोक्त करार के बावजूद, एनडीएफबी ने सेना/पुलिस/ सुरक्षा बल के जवानों तथा कानून का पालन करने वाले नागरिकों पर हमला करने और सरकारी एवं निजी सम्पत्तियों का विनाश करने सहित आतंकवादी हिंसा की अपनी गतिविधियों को बढ़ाकर संप्रभु बोरोलैण्ड की स्थापना करने के अपने दृष्टिकोण से अपनी अलगाववादी एवं हिंसक गतिविधियों को जारी रखा। एनडीएफबी ने क्रमशः मेघालय एवं मिजोरम के साथ लगने वाली बांग्लादेश सीमा की चिटगाँव पहाड़ी क्षेत्र तथा शेरपुर जिला में कई शिविर/ शरणस्थली स्थापित कर रखे हैं। विदेशी भूमि पर शिविरों की स्थापना से एनडीएफबी के कैडरों को प्रशिक्षण में मदद मिली जिस पर नियंत्रण नहीं किया जा सका। इससे विदेशी भूमि पर भर्ती किए गए नए कैडरों को प्रशिक्षण देने के बाद राज्य में विध्वंसक गतिविधियों को जारी रखने में उन्हें सहायता मिली। बांग्लादेश में एनडीएफबी शिविरों के निकट परिसर में एएनबीसी, एचएनएलसी, एनएससीएन (आई एम), एटीटीएफ तथा एनएलएफटी जैसे अन्य पूर्वोत्तर उग्रवादी दलों की समान शिविरों से दल में हथियारों को लाने-लेजाने में सहायता मिलती है। यू एलएफए तथा मेघालय के एचएनएलसी के साथ एनडीएफबी का दुर्भाग्यपूर्ण गठजोड़ अभी भी बना हुआ है। उन्होंने गुवाहाटी शहर की सीमा के अन्दर पड़ने वाले मेघालय के रिभोई जिला सहित असम- मेघालय सीमा पर एक शिविर स्थापित कर रखा है। 2008 में, उक्त स्थान से, उन्होंने संयुक्त रूप से गुवाहाटी शहर में जबरन धनवसूली हेतु व्यापारियों का अपहरण करने जैसी कार्रवाईयों का संचालन किया। इसी तरह से पश्चिम बंगाल पुलिस (सितम्बर 9, 2008) द्वारा केएलओ (कामतपुर लिबरेशन आर्गनाइजेशन) उग्रवादी, रामनाथ राय उर्फ बाबू की गिरफ्तारी से यह तथ्य उजागर हुआ कि केएलओ के नए भर्ती काडरों को मशिम खताल प्रशिक्षण शिविर स्थित एनडीएफबी के एक शिविर में हथियार चलाने का प्रशिक्षण दिया गया और यह प्रशिक्षण उन्हें केएलओ एवं एन डीएफबी के वरिष्ठ नेताओं द्वारा प्रदान किया गया। केएलओ काडरों के नवीनतम दो बैचों को एनडीएफबी प्रशिक्षकों द्वारा बांग्लादेश के मशिम खताल में एनडीएफबी शिविर में 2008 में प्रशिक्षण दिया गया था। अध्यक्ष रंजन डोमारी सहित बांग्लादेश में स्थित एनडीएफबी नेतृत्व के बारे में कहा जाता है कि वह अभी भी एक संप्रभु स्वतंत्र बोरोलैण्ड की स्थापना के उद्देश्य को समर्थन प्रदान कर रहा है।

रंजन डोमारी (अध्यक्ष, एनडीएफ ) ने बांग्लादेश के खग्रचारी शिविर में एक पासिंग आऊट परेड में प्रशिक्षणार्थियों का आह्वान किया कि वे स्वतंत्र बोरोलैण्ड की स्थापना के लिए अपनी जान न्यौछावर करें। एनडीएफबी के महासचिव गोविन्द बासुमुतारी, ने 28.2.2007 को धेमाजी जिला में हुई “ऑल बोडो पीस फॉरम” की एक खुली बैठक में कथित रूप से यह स्पष्ट किया कि एनडीएफबी का लक्ष्य और उद्देश्य बोडो नागरिक को स्वतंत्र कराना एवं बचाना है तथा इसे संघीय भारत से अलग करना है। पी डब्ल्यू-3, सुश्री गोगोई ने अगस्त, 2007 में बांग्लादेश में हुई एनडीएफबी काडरों की पासिंग आऊट परेड को प्रदर्शित करने हेतु अपने शपथपत्र के सथ कॉम्पैक्ट डिस्क की एक प्रति संलग्न की है। सुश्री गोगोई ने कहा है कि गुवाहाटी, बारपेटा रोड, बोंगाईगांव तथा कोकराझाड़ के विभिन्न स्थानों पर 30.10.2008 को होने वाले 9 श्रृंखलाबद्ध धमाकों, जिसमें 89 निर्दोष लोगों की जानें गईं तथा 593 घायल हो गए थे, की जाँच से पता चला है कि इन धमाकों में एनडीएफबी काडरों की स्पष्ट भागीदारी थी। उनके अनुसार इन मामलों को अब असम सरकार की अधिसूचना सं० पीएलए 633/2008/17 दिनांक दिसपुर 16.12.2008 के तहत आगामी जाँच-पड़ताल के लिए सीबीआई को सौंप दिया गया है। पी डब्ल्यू-3, सुश्री गोगोई ने यह भी स्पष्ट किया है कि एनडीएफबी के सदस्यों को धन की उगाही करने हेतु विभिन्न व्यक्तियों/संगठनों को मांग पत्र जारी करने में भी संलिप्त पाया गया था। एनडीएफबी काडरों द्वारा धन संग्रह की कार्य-पद्धति को सरल शब्दों में ‘अंशदान’ या ‘दान’ या ‘वित्तीय सहायता’ के नाम से जाना जाता है, जिसे और कुछ नहीं बल्कि धन उगाही का युक्तिपूर्ण तरीका माना गया है। एनडीएफबी ने अभी भी अपने भर्ती अभियान को जारी रखा हुआ है और राज्य के विभिन्न हिस्सों से बड़ी संख्या में युवाओं की भर्ती की है। नई भर्तियों को हथियारों एवं विस्फोटकों आदि का संचालन करने का प्रशिक्षण देने के लिए समूहों में बांग्लादेश भेजा जाता है। पी डब्ल्यू-3 के अनुसार, एनडीएफबी संगठन अभी भी विभिन्न गैर-कानूनी गतिविधियों में संलिप्त है जिसमें हत्या, उगाही, बम धमाके, गैर-कानूनी अस्त्र-शस्त्र एवं विस्फोटक सामग्रियों को रखना, भारत की संप्रभुता एवं अखण्डता को आघात पहुँचाने के दृष्टिकोण से गैर-बोरो आबादी के दिमाग में दहशत पैदा करना और नागरिकों के बीच असुरक्षा की भावना को पैदा करना शामिल है। 23.11.2006 से 22.11.2008 की अवधि के दौरान एनडीएफबी द्वारा कुल 138 व्यक्ति मारे गए तथा 656 व्यक्ति उनके घातक हमलों में घायल हो गए। एनडीएफबी संगठन द्वारा हिंसा की 176 वारदातों को अंजाम दिया गया। उन्होंने उगाही के लिए 20 व्यक्तियों का अपहरण भी किया।

पी डब्ल्यू-3 द्वारा अपने शपथपत्र में बताए गए इन तथ्यों के कारण ही उन्होंने 23.11.2008 की अधिसूचना के तहत एनडीएफबी को एक गैर-कानूनी संगठन घोषित किए जाने को न्यायसंगत ठहराया और उनके अनुसार ऐसी घोषणा एनडीएफबी की गैर-कानूनी गतिविधियों को नियंत्रित एवं समाप्त करने के लिए आवश्यक है जो भारत की संप्रभुता एवं अखण्डता के लिए नुकसानदायक है।

50. पी डब्ल्यू-2, श्री एस.के.राय, संयुक्त सचिव, असम सरकार, गृह एवं राजनीतिक विभाग तथा पी डब्ल्यू-10, श्री आर.आर.झा, निदेशक, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली ने अपने अलग-अलग शपथपत्रों में और पूर्व पी डब्ल्यू-2/1 एवं पूर्व पी डब्ल्यू-10/1 ने क्रमशः उस प्रश्नगत अधिसूचना को न्यायोचित ठहराया है जिसके द्वारा एनडीएफबी को यह कहते हुए गैर-कानूनी संगम घोषित किया कि ऐसी घोषणा एनडीएफबी की गैर-कानूनी गतिविधियों को नियंत्रित एवं समाप्त करने के लिए आवश्यक है जो भारत की संप्रभुता एवं अखण्डता के लिए नुकसानदायक है। इन दोनों गवाहों ने मामले के समस्त वास्तविक पहलुओं पर उपरवर्णित पुलिस साक्ष्यों के कथन का समर्थन किया है, इसलिए पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उनके शपथपत्रों की विषय-वस्तु को यहाँ अलग से वर्णित नहीं किया गया है।

51. एनडीएफबी ने उनके संगठन पर प्रतिबंध लगाने वाली अधिसूचना के विरोध में, श्री बी स्वंखर, एनडीएफबी के महासचिव, श्री आई० दामिनी, एनडीएफबी के गृह सचिव तथा श्री बी.के. ओलंगवार, एनडीएफबी के शिक्षा सचिव के तीन शपथपत्रों को दाखिल किया है। उनके शपथपत्रों को पूर्व डीडब्ल्यू-1/1, पूर्व डीडब्ल्यू-2/1 और पूर्व डीडब्ल्यू-3/1 के रूप में दर्शाया गया है और वे समान तर्ज पर हैं। अपनी प्रमुख जाँच में समस्त तीनों बचाव साक्ष्यों ने कहा है कि बोरो नागरिक, जो मंगोलियन प्रजाति के चीनी-तिब्बती मूल के हैं, ने सम्पूर्ण ब्रह्मपुत्र एवं बराक घाटी पर शासन किया, जो त्रिपुरा, उत्तरी बंगाल, उत्तरी बिहार और नेपाल एवं बांग्लादेश के कुछ हिस्से तक फैला हुआ था और जिसकी एक अलग राजनीतिक एवं सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान थी। उन्होंने यह भी कहा कि अंग्रेजों की घुसपैठ तथा बोरो राजतंत्र को उसमें शामिल किए जाने के कारण उन्होंने अपने संप्रभु भूभागों को खो दिया तथा 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के बाद बोरो नागरिकों ने अपना सम्मान, स्वाभिमान सबकुछ खो दिया और सबसे ऊपर अपने समस्त भूभाग एवं संप्रभुता को भी खो दिया। उन्होंने कहा कि भारत

सरकार ने बोरो नागरिकों के सामाजिक-आर्थिक एवं राजनीतिक ढांचे को पूर्णतः झकझोर दिया है। उन्होंने यह भी कहा है कि देशज नागरिक संबंधी अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र घोषणापत्र के अनुच्छेद (ए3) के अनुसार बोरो नागरिक चूँकि पूर्वोत्तर भारत के देशज नागरिक हैं, इसलिए उन्हें आत्म-निर्णय लेने का अधिकार है और वे स्वतंत्र रूप से राजनीतिक सत्ता का निर्धारण कर सकते हैं तथा आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास के लिए अपनी प्रगति की ओर स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ सकते हैं। परन्तु भारत सरकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38 के अन्तर्गत प्रतिबद्ध अपने संवैधानिक दायित्व का पालन करने से चूक गई है। उन्होंने कहा कि इसकी पृष्ठभूमि में बोरो सुरक्षा बल को 3 अक्टूबर, 1986 को गठित किया गया था और उसके बाद बीएसएफ की आम परिषद की एक बैठक में इसे नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोरोलैण्ड के रूप में पुनर्स्थापित किया गया था। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि एनडीएफबी की विचारधारा और उद्देश्य बोरोलैण्ड को उपनिवेशवादी ताकत से बचाना है तथा स्वतंत्रता, समानता एवं भाईचारे को बढ़ाने के लिए एक लोकतांत्रिक समाजवादी समाज की स्थापना करना तथा सामाजिक आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए प्रयास करना और अपनी भूमि के प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित एवं सुरक्षित करना है।

52. एनडीएफबी के साक्षियों ने यह भी कहा कि उनकी तरफ से विद्वेषों को समाप्त कर दिया गया है क्योंकि उनके संगठन ने भारत सरकार एवं असम सरकार के साथ अभियान स्थगन नामक एक विराम संधि करार पर 25 मई, 2005 को हस्ताक्षर करते हुए एक राजनीतिक समझौते पर सहमति जाहिर कर दी है। अभी भी लागू 1 जून, 2005 से प्रभावी इस करार के अनुसार एनडीएफबी हिंसा के रास्ते से दूर रहने लगा और उनके द्वारा सामना की जा रही विभिन्न समस्याओं को भारतीय संविधान की रूपरेखा के अन्दर निपटाने के लिए वचनबद्ध रहा। उनके काडर असम में ओडलगुरी जिला में सबकैथी, कोकराझाड़ में खुमगुरी (सफनगुरी) और बसका जिला में धनबिल (बरबरी) स्थित तीन अभिनिर्धारित शिविरों में रह रहे हैं जिनका रखरखाव एवं पर्यवेक्षण असम सरकार द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार गलत तरीके से उनके सदस्यों को उन हिंसक एवं गैर-कानूनी गतिविधियों में घसीट रही है जिन्हें अन्य असामाजिक तत्वों द्वारा निष्पादित किया जा रहा है। उन्होंने क्रमबद्ध तरीके से आरोप का खंडन किया कि उनका संगठन 3 अक्टूबर, 2008 को ओडलगुरी एवं दरांग जिले में सांप्रदायिक झड़पों में तथा 30 अक्टूबर, 2008 को गुवाहाटी में

होने वाले बम धमाकों में शामिल था। उन्होंने कहा कि उनके संगठन का यूएलएफए, एनएससीएन आदि जैसे उग्रवादी दलों से बिल्कुल भी निकट गठजोड़ नहीं है और वे सेना में लागू मूल नियमों का अधिकतम संभव स्तर तक पालन कर रहे हैं। साक्ष्यों ने पुरजोर गुजारिश की कि उनके संगठन को अधिनियम की धारा 3 (1) के अन्तर्गत एक गैर-कानूनी संगम घोषित किए जाने का उपयुक्त कारण मौजूद नहीं था।

53. मैंने श्री ए.बी. चौधरी, विद्वान वरिष्ठ कौंसल जो एनडीएफबी संगठन की ओर से उपस्थित हुए और श्री संजीव भण्डारी, वकील जो केन्द्र सरकार की ओर से उपस्थित हुए तथा श्री जे आर लुआंग, असम राज्य सरकार के लिए स्थायी कौंसल की दलिलों को भी सुना है। मैंने दोनों पक्षों के कौंसलों द्वारा प्रस्तुत की गई लिखित दलिलों को भी देखा है और उनपर मैंने गहन विचार किया है।

54. केन्द्र सरकार तथा असम राज्य सरकार की ओर से उपस्थित हुए विद्वान कौंसल ने अर्ज किया है कि दिनांक 23.11.2008 की अधिसूचना जिसके द्वारा एनडीएफबी संगठन को एक गैर-कानूनी संगम के रूप में घोषित किया गया था, को इस अदालत द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए क्योंकि उनके अनुसार उनके साक्ष्यों ने प्रमाणित कर दिया है कि एनडीएफबी संगठन 2005 के युद्धविराम करार के बावजूद विगत दो वर्षों के दौरान विभिन्न गैर-कानूनी आपराधिक गतिविधियों में शामिल होता रहा था और उसके बाद उनके अनुसार निर्णय हेतु इस अदालत को भेजे गए अधिसूचना दिनांक 23.11.2008 के तहत एक गैर-कानूनी संगम के रूप में एनडीएफबी संगठन की घोषणा करने के लिए सरकार के पास समुचित कारण थे।

55. दूसरी ओर, श्री चौधरी, एनडीएफबी संगठन की ओर से उपस्थित हुए विद्वान वरिष्ठ कौंसल ने दलील दी कि एक गैर-कानूनी संगठन के रूप में समुचित कारणों की उपस्थिति को साबित करने का कानूनी रूप से स्वीकार्य कोई साक्ष्य नहीं है। श्री चौधरी ने दलील दी कि पुलिस साक्ष्यों अथवा सरकार की ओर से जाँच करने वाले सरकारी अधिकारियों को कोई महत्व नहीं दिया जा सकता क्योंकि उनके सबूत में उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए शपथपत्रों को कोड ऑफ सिविल प्रोसिजर, 1908 के आर्डर 6 रूल 15 में निहित प्रावधानों के आलोक में सत्यापित नहीं किया गया जिसमें प्रावधान है कि "दलीलों का सत्यापन करने

वाला व्यक्ति दलीलों में उल्लिखित पैराग्राफों के संदर्भ में यह विनिर्दिष्ट करेगा कि वह अपने ज्ञान के अनुसार क्या सत्यापित करता है और उसे प्राप्त हुई सूचना के अनुसार वह क्या सत्यापन करता है तथा किसे वह सच मानता है।” श्री चौधरी की दलील यह थी कि चूँकि सरकार द्वारा जाँच किए गए समस्त साक्ष्यों ने अपने जाँच के दौरान माना है कि उनके शपथपत्रों में निहित सत्यापन मद यह नहीं स्पष्ट करती है कि उनके विवेक के अनुसार उनके शपथपत्रों का कौन सा पैराग्राफ सत्य और सही हैं और किन पैराग्राफों को रिकार्डों से प्राप्त जानकारी के अनुसार सही माना जाए, उनके शपथपत्रों में निहित साक्ष्य पर अदालत द्वारा कोई सत्यता या प्रत्यय प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए। श्री चौधरी ने और भी दलील दी कि चूँकि सरकार के साक्ष्यों द्वारा संलग्न किए गए दस्तावेज मात्र उनके मूल दस्तावेजों की फोटो प्रतियाँ हैं, इसलिए ऐसी फोटो प्रतियों पर अदालत द्वारा कोई सत्यता या प्रत्यय प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए। क्योंकि उनके अनुसार, गौण साक्ष्य को प्रस्तुत करने के लिए सरकार द्वारा कोई आधार प्रस्तुत नहीं किया गया है। यह कहा गया था कि सरकार के साक्ष्यों के शपथपत्रों के साथ संलग्न किए गए दस्तावेजों को किसी भी स्थिति में अदालत द्वारा प्रयोग में अथवा कार्रवाई में नहीं लाया जाना चाहिए क्योंकि इन दस्तावेजों के लेखक की अदालत के समक्ष जाँच नहीं की गई है। एनडीएफबी संगठन की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान वरिष्ठ कौंसल के अनुसार सरकार द्वारा जाँच किए गए एक भी साक्ष्य वास्तविकता के परीक्षण के समय खरे नहीं उतरे जब उन्हें फिर से पूछताछ के लिए ले जाया गया और इसी कारणवश उनके अनुसार अदालत द्वारा निर्णय के अन्तर्गत दिनांक 23.11.2008 की अधिसूचना पर निर्णय लेते समय उनके तथ्य को कोई सत्यता प्रदान नहीं की जानी चाहिए। इसके बाद एनडीएफबी संगठन की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान वरिष्ठ कौंसल का तर्क यह था कि सरकार के साक्ष्यों को इसलिए भी सत्यता प्रदान नहीं की जा सकती है क्योंकि विगत दो वर्षों के दौरान दर्ज विभिन्न आपराधिक मामलों, जिसमें एनडीएफबी काडरों के शामिल होने की आशंका है, की विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की धारा 43 के अन्तर्गत अपेक्षित रूप से पुलिस उपाधीक्षक की रैंक के पुलिस अधिकारी द्वारा जाँच नहीं की गयी थी। श्री चौधरी द्वारा यह कहा गया था कि निर्णयाधीन अधिसूचना दिनांक 23.11.2008 को इस अदालत द्वारा चरु कहकर खारिज कर दिया जाना चाहिए कि इस अधिसूचना के समर्थन में कानूनी तौर पर स्वीकार्य सबूत पेश किए जाएं।

56. मैंने दोनों पक्षों द्वारा अधिसूचना दिनांक 23.11.2008 के पक्ष एवं विपक्ष में प्रस्तुत किए गए साक्ष्य की सावधानीपूर्वक जांच, परख और मूल्यांकन कर लिया है।

57. विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा २ के खण्ड (ण) एवं (त) में क्रमशः 'विधिविरुद्ध क्रियाकलाप' एवं 'विधिविरुद्ध संस्था' की परिभाषा दी गई है। ये निम्न प्रकार हैं:-

“(ण) “विधिविरुद्ध क्रियाकलाप” का तात्पर्य किसी व्यक्ति अथवा संगम के संबंध में ऐसे व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा किए गए किसी कार्य (चाहे वह कोई कार्य करके या बोलकर, चाहे बोला गया हो या लिखा गया हो, अथवा चिन्हों द्वारा या दृष्टिगत चित्रण द्वारा या किसी अन्य रूप में किया गया हो) से है,-

- (i) जो किसी भी आधार पर भारतीय भूभाग के एक हिस्से को समाप्त करने अथवा संघ से भारतीय भूभाग के एक हिस्से को पृथक करने के लिए अभिप्रेत हो अथवा ऐसे किसी दावे को समर्थन प्रदान करता हो, या जो किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह को ऐसी समाप्ति अथवा पृथकीकरण के लिए भड़काता हो;
- (ii) जो भारत की क्षेत्रीय अखण्डता एवं सहिष्णुता को नकारता हो, प्रश्नचिन्ह लगाता हो, बाधित करता हो अथवा बाधित करने के लिए अभिप्रेत हो; या
- (iii) जो भारत के विरुद्ध असन्तोष पैदा करने के लिए अभिप्रेत हो अथवा कारण बनता हो।”

“(त)“विधिविरुद्ध संगम” का तात्पर्य किसी ऐसे संख्या से है,-

- (i) जिसका उद्देश्य किसी तरह विधिविरुद्ध क्रियाकलाप करना हो, या जो किसी तरह का विधिविरुद्ध क्रियाकलाप करने के लिए व्यक्तियों को बढ़ावा देता हो अथवा सहायता करता हो या जिसके सदस्य इस तरह के क्रियाकलाप करते हों; अथवा



- (ii) जिसका उद्देश्य किसी तरह का ऐसा विधिविरुद्ध क्रियाकलाप करना हो जो भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 153 ए या धारा 153 बी के अन्तर्गत दण्डनीय हो, या जो किसी तरह का ऐसा क्रियाकलाप करने के लिए व्यक्तियों को बढ़ावा देता हो अथवा सहायता करता हो या जिसके सदस्य इस तरह के क्रियाकलाप करते हों;  
परन्तु यह कि उप-खण्ड (ii) में निहित कोई भी शर्त जम्मू व कश्मीर राज्य में लागू नहीं होगी;"

58. उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि खण्ड (ण) में परिभाषित 'विधिविरुद्ध क्रियाकलाप' का तात्पर्य उसमें वर्णित स्वरूप की 'कोई कार्रवाई' तथा उसके वर्णित परिणाम से हैं। दूसरे शब्दों में, 'विधिविरुद्ध क्रियाकलाप' को संगठित करने वाले ऐसे व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा की गई 'कोई कार्रवाई' जिनकी परिभाषाओं में वर्णित क्षमता हो। इन तथ्यों की सुनिश्चितता एक संस्था को अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा 1 के अन्तर्गत विधिविरुद्ध घोषित करने के लिए आधार तैयार करती है। खण्ड (त) 'विधिविरुद्ध संगम' को उसके उप-खण्ड (i) में 'विधिविरुद्ध क्रियाकलाप' के संदर्भ में परिभाषित करती है, और उप-खण्ड (ii) में इसका संदर्भ ऐसे अपराधों से है जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 153-ए या धारा 153-बी के अन्तर्गत दण्डनीय है। उप-खण्ड (ii) में, वास्तविक अवधारणा ऐसे अपराधों के संदर्भ में है जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 153-ए या धारा 153-बी के अन्तर्गत दण्डनीय है जबकि उप-खण्ड (i) में, यह ऐसे 'विधिविरुद्ध क्रियाकलाप' के संदर्भ में है जैसा कि खण्ड (ण) में परिभाषित किया गया है। ये परिभाषाएँ इस तथ्य को स्पष्ट करती हैं कि प्रश्नगत अवधारणा कि कोई संस्था एक विधिविरुद्ध संगम है या बन गई है, ऐसे निर्णय को प्रमाणित करती हैं और अवधारणा यह होनी चाहिए कि ऐसी संस्था द्वारा की गई 'कोई कार्रवाई' एक 'विधिविरुद्ध क्रियाकलाप' को स्वरूप प्रदान करती हैं जैसा कि संस्था का उद्देश्य है।

59. एनडीएफबी (मूलतः बोरो सुरक्षा बल के रूप में जानी जाती है) का गठन 03.10.1986 को किया गया था जिसका घोषित उद्देश्य एवं लक्ष्य सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से भारत से असम के बोरो बहुल क्षेत्रों को अलग करना तथा एक स्वतंत्र एवं संप्रभु बोरोलैण्ड की स्थापना करना था। एनडीएफबी के लक्ष्य एवं उद्देश्य इस प्रकार हैं:-

- i) बोरो लैण्ड को भारतीय विस्तारवाद एवं स्वामित्व से आजाद करना;
- ii) बोरो राष्ट्र को उपनिवेशिक दोहन, संचालन एवं वर्चस्व से मुक्त करना;
- iii) स्वतंत्रता, एकता एवं भाईचारा कायम करने के लिए एक लोकतांत्रिक, जनतांत्रिक समाज की स्थापना करना;
- iv) बोरोलैण्ड की अखण्डता एवं संप्रभुता को बनाए रखना।

60. एनडीएफबी संगठन 01.06.2005 से मूलतः एक वर्ष के लिए भारत सरकार एवं असम सरकार के साथ 'अभियान स्थगन' संबंधी एक करार में शामिल हुआ। (अभियान स्थगन संबंधी इस करार को इसके बाद '2005 का युद्धविराम करार' के रूप में संदर्भित किया जाएगा।) 2005 के युद्धविराम करार, जो 01.06.2005 से मूलतः एक वर्ष के लिए प्रभावी था, को समय-समय पर बढ़ाया गया था और अन्तिम ऐसा विस्तार 06.01.2009 को प्रदान किया गया था। 2005 का युद्धविराम करार आज भी जारी है। युद्धविराम करार के सम्मत आधारभूत नियमों की प्रतियाँ श्री बी.स्वमखर, एनडीएफबी संगठन का प्रथम साक्ष्य के शपथपत्र के पृष्ठ 32 से 36 पर संलग्नक (ग) एवं संलग्नक (घ) पर दिया गया है। उपरवर्णित संलग्नक (ग) एवं संलग्नक (घ) को देखने से पता चलेगा कि एनडीएफबी संगठन, सरकार के साथ युद्धविराम करार में शामिल होते वक्त, शांति बनाए रखने तथा हथियार लेकर या पोशाक पहनकर नहीं चलने पर सहमत हुआ। एनडीएफबी संगठन आगे भी सहमत हुआ कि उसके सदस्य/काडर पूर्वनिर्धारित शिविरों में रहेंगे और शिविर कमाण्डर से उचित अनुमति लिए बिना शिविरों से बाहर नहीं निकलेंगे।

61. सरकार का मामला यह है कि 2005 के युद्धविराम करार के बावजूद, एनडीएफबी काडरों ने शांति वार्ताओं में हिस्सा नहीं लिया है और उनके नेताओं ने अपने काडरों को बिल्कुल तैयार रहने के लिए प्रेरित किया है जिससे भारत सरकार द्वारा संप्रभुता संबंधी उनकी मांग को अस्वीकृत किए जाने के मामले में सशस्त्र युद्ध को फिर से शुरू किया जा सके। सरकार का अगला मामला यह है कि एनडीएफबी संगठन अभी भी असम के कोकराझाड़, चिरांग, ओडलगुडी, बस्का, बारपेटा, नलबाडी, दरांग, कामरूप, सोनितपुर, बोंगाईगांव तथा कर्बी आंगलांग जिलों में सक्रिय है। ऐसा कहा गया है कि इसके काडरों का अभियान गोलाघाट, लखीमपुर, धेमाजी तथा डिब्रूगढ़ जैसे असम के ऊपरी जिलों में भी चलता हुआ

पाया गया है। विगत दो वर्षों के दौरान, कई आपराधिक मामलों, जिनमें एनडीएफबी काडरों के शामिल होने की संभावना थी, को असम राज्य के विभिन्न जिलों में दर्ज किया गया था तथा गिरफ्तार किए गए घुसपैठियों ने, उन मामलों में अपनी छानबीन के दौरान, यह उजागर किया है कि एनडीएफबी संगठन के पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों से सम्पर्क हैं और उनके काडरों को भूटान, बांग्लादेश तथा अन्य विदेशी भूभागों पर प्रशिक्षित किया गया था।

62. एनडीएफबी संगठन को अधिसूचना दिनांक 23.11.1992 के तहत पहली बार सरकार द्वारा एक विधिविरुद्ध संस्था के रूप में प्रतिबंधित किया गया था और इसके बाद यह प्रतिबंध प्रत्येक दो वर्षों बाद नई अधिसूचना जारी कर आज तक कायम रखा गया है। अन्तिम अधिसूचना दिनांक 23.11.2006 (निर्णयाधीन 23.11.2008 की अधिसूचना से पहले की अधिसूचना) को दिनांक 14.05.2007 के आदेश के तहत जस्टीस प्रदीप नन्दराजोग की अध्यक्षता वाली अदालत द्वारा पुष्टि प्रदान की गई थी।

63. पी डब्ल्यू-10, श्री आर आर झा, निदेशक, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली ने वर्ष 2006, 2007 एवं 2008 के दौरान एनडीएफबी काडरों के आपराधिक क्रियाकलापों को अदालत के समक्ष अपने सबूत में सत्यापित किया है। उन्होंने उजागर किया है कि एनडीएफबी संगठन, अपने लक्ष्यों एवं उद्देश्यों के अनुसरण में, विभिन्न हिंसक गतिविधियों में शामिल होता आ रहा है और लोगों के बीच डर एवं भय पैदा कर रहा है। उन्होंने अपने शपथपत्र एक्स.पी डब्ल्यू-10/1 में संलग्नक -III के रूप में शामिल की गई एक सूची में 2006, 2007 एवं 2008 में एनडीएफबी काडरों द्वारा हिंसा की मुख्य घटनाओं का ब्यौरा दिया है। उन मुख्य घटनाओं के ब्यौरों, जिसमें एनडीएफबी के काडर मुख्य रूप से संलिप्त थे, में बम धमाके, नागरिकों पर हमले, अपहरण, धनउगाही, सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ तथा आगजनी की घटनाएँ शामिल हैं। श्री झा (पी डब्ल्यू-10) ने अपने साक्ष्य शपथपत्र के पैरा 10 में यह भी उजागर किया है कि 30.10.2008 को असम के विभिन्न जिलों में नौ श्रृंखलाबद्ध बम धमाके हुए थे, जिसमें 86 नागरिक मारे गए थे और 477 व्यक्ति घायल हुए थे। असम राज्य सरकार द्वारा इसकी प्रारंभिक छानबीन की गई थी जिसमें एनडीएफबी के कुछ सक्रिय सदस्यों की भागीदारी का पता चला और इसका षडयंत्र बांग्लादेश में तैयार किया गया था। पी डब्ल्यू-10 को एनडीएफबी कौंसल द्वारा फिर से छानबीन करने की बात कही गई परन्तु

उनके शपथपत्र के संलग्नक-III में निहित घटनाओं के व्यौरों के संबंध में उन्हें रतीभर भी सुझाव नहीं दिया गया। सरकार द्वारा जाँच किए गए समस्त साक्ष्यों ने एनडीएफबी संगठनों के काइरों/सदस्यों की विभिन्न विधिविरुद्ध आपराधिक क्रियाकलापों में भागीदारी को उजागर किया जिसके परिणामस्वरूप उनके उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को हासिल करने के उद्देश्य से हत्याएँ एवं धन वसूली की गई। सरकार के साक्ष्यों के शपथपत्रों के साथ संलग्न किए गए दस्तावेजों में न केवल एनडीएफबी संगठन के सदस्यों/काइरों की विधिविरुद्ध आपराधिक गतिविधियों में भागीदारी को उजागर किया गया है वरन् यह भी प्रमाणित किया गया है कि जब असम राज्य सरकार और भारत सरकार के साथ एनडीएफबी संगठन युद्धविराम करार में शामिल हुआ था, तब उन्होंने अपनी बेहतर जानकारी के अनुसार सरकार को अपने सदस्यों की पूर्ण सूची नहीं दी थी, जिसके पीछे उनकी पूर्वनिर्धारित द्वेषपूर्ण नीयत छुपी थी कि सरकार को उनके काइरों की विधिविरुद्ध क्रियाकलापों में भागीदारी के संबंध में गुमराह किया जा सके और धोखे में रख जा सके। सर्व सम्मति से, श्री रंजन दिमारी, 29.12.2008 को एनडीएफबी संगठन द्वारा निलम्बित किए जाने से पहले वह उक्त संगठन का अध्यक्ष था। उनका नाम 2005 के युद्धविराम करार के समय सदस्यों की और इसके बाद भी 29.12.2008 को संगठन से निलम्बित किए जाने तक शामिल नहीं था। एनडीएफबी संगठन से संबंधित विद्वान वरिष्ठ कौंसल कोई स्पष्टीकरण, कम-से-कम विश्वास दिलाने वाला स्पष्टीकरण नहीं दे सके कि क्यों रंजन दिमारी, एनडीएफबी का तत्कालीन अध्यक्ष, का नाम युद्धविराम करार के समय सरकार को संगठन द्वारा दी गई सदस्यों की सूची में शामिल नहीं था। सरकार को दी गई सदस्यों की सूची में न केवल रंजन दिमारी का नाम शामिल नहीं था, वरन् विगत दो वर्षों में आपराधिक मामलों में गिरफ्तार किए गए कई अन्य एनडीएफबी काइरों के नाम भी उक्त सूची में शामिल नहीं थे। पी डब्ल्यू-1, श्री सलोई ने 30.10.2008 को अपने सीमा क्षेत्र में होने वाले तीन बम धमाकों के सबूत प्रस्तुत किए हैं। पुलिस स्टेशन, दिसपुर के मामला सं० 1419/2008 के प्रथम बम धमाके के मामले में एनडीएफबी काइरों के चार संदिग्ध अभियुक्त व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था और उनमें से दो अर्थात् नीलिम दिमारी उर्फ डी० निजुम्सा एवं सबिन बोरो उर्फ बी. सुसरांगु ने अपने कबूलनामा वक्तव्य में माना है कि वे एनडीएफबी काइरों के सदस्य हैं। अभियुक्त नीलिम दिमारी उर्फ डी. निजुम्सा ने पुलिस को कहा है कि वह मार्च 2007 में एनडीएफबी काइर में शामिल हुआ था और बांग्लादेश में हथियारों का प्रशिक्षण लिया था। इस संबंध में खण्ड II में पृष्ठ 339 में इसका संदर्भ दिया

गया है। अभियुक्त नीलिम दिमारी उर्फ डी० निजुम्सा का वक्तव्य दर्शाता है कि एनडीएफबी संगठन 2005 में सरकार के साथ युद्धविराम करार में शामिल होने के बाद भी अपने काडरों की नई नियुक्तियाँ कर रहा था। अभियुक्त सबिन बोरो उर्फ बी. सुसरांगु का बयान यह उजगार करता है कि वह 1990 में एनडीएफबी काडर में भर्ती हुआ और उसने भूटान में सैनिक प्रशिक्षण लिया। इससे संबंधित संदर्भ खण्ड II में पृष्ठ 340 पर दिया गया है। इसी प्रकार अभियुक्त मृदुल बासुमतरी और पवित्र बोरो उर्फ बी. फुथई उर्फ लेंगरा ने पुलिस को दिए गए अपने बयान में माना कि उन्हें युद्धविराम करार से पहले एनडीएफबी काडरों के रूप में सूचीबद्ध किया गया था परन्तु आश्चर्य है कि सरकार को सौंपी गई सदस्यों की सूची में उनके नाम शामिल नहीं किए गए थे। इसी तरह से आपराधिक मामलों में गिरफ्तार किए गए कई अन्य अभियुक्त व्यक्तियों के एनडीएफबी काडरों में होने की आशंका है, जिनके संबंध में सरकारी गवाहों द्वारा सबूत दिए गए हैं; और उन्होंने अपने बयान में एनडीएफबी काडरों का सदस्य होने की बात मानी है परन्तु उनके नाम सरकार को दी गई सूची में शामिल नहीं किए गए हैं। एनडीएफबी संगठन ने सदस्यों की पूर्ण सूची को क्यों छुपा लिया, यह तथ्य अदातल के समक्ष पूर्णतः अवर्णित रह गया। एनडीएफबी संगठन को अवसर दिए जाने के बावजूद, सरकार के किसी भी साक्ष्य के समझ रतीभर भी सुझाव नहीं रखा गया जो आपराधिक मामलों में एनडीएफबी काडरों की कथित भागीदारी से संबंधित उनके आलेख का प्रतिवाद करता हो, जिसके बारे में उनके द्वारा सबूत पेश किए गए हैं।

64. श्री चौधरी, एनडीएफबी संगठन की ओर से पेश होने वाले विद्वान वरिष्ठ कौंसल ने सरकार की ओर से इसकी अधिसूचना दिनांक 23.11.2008 के समर्थन में प्रस्तुत किए गए सबूत की स्वीकार्यता पर तकनीकी आपत्ति जताई, जिसमें कहा गया कि उक्त साक्ष्य, कानूनी तौर पर स्वीकार्य साक्ष्य नहीं है क्योंकि उनके अनुसार, मूल दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए दस्तावेज तैयार करने वाले की जाँच नहीं की गई, अभियुक्त व्यक्तियों के बयान पुलिस द्वारा आपराधिक दण्ड संहिता की धारा 161 के तहत दर्ज किए गए और मामलों के अन्तर्गत छानबीन एक ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा की गई जो उक्त मामलों में छानबीन करने के लिए सक्षम नहीं था।

65. एनडीएफबी संगठन की ओर से सबूत की स्वीकार्यता के संबंध में आपति पर मैंने गहन विचार विमर्श किया परन्तु मामले के इस पहलु पर एनडीएफबी के कौंसल के साथ सहमत होने के लिए अपने आपको बाध्य नहीं कर सका।

66. माननीय उच्चतम न्यायालय ने जमात-ए-इस्लामी हिन्द बनाम भारत संघ, 1995 (1) एससीसी 428 में कहा है कि एक विधिविरुद्ध संस्था के रूप में एक संगठन को प्रतिबंधित करने हेतु सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना पर निर्णय लेने वाली अदालत, संस्था को विधिविरुद्ध घोषित करने के लिए समुचित कारण की उपस्थिति को निर्धारित करने के लिए इसे स्वीकृत करने का निर्णय लेने से पूर्व, उसके समक्ष प्रस्तुत की गई सामग्री की विश्वसनीयता की जाँच और परीक्षण करने के लिए एक उपयुक्त प्रक्रिया का सुझाव दे सकती है। माननीय उच्चतम न्यायालय में इस मामले में कहा गया कि अदालत के समक्ष प्रस्तुत की गई सामग्री को वास्तविक अर्थ में कानूनी साक्ष्य तक ही सीमित रखे जाने की आवश्यकता नहीं है। जमात-ए-इस्लामी हिन्द के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय का पैरा 22 संगत है और इसका सार नीचे दिया गया है:-

“यह जाहिर है कि एक संस्था द्वारा किया जाने वाला विधिविरुद्ध क्रियाकलाप अक्सर गुप्त प्रकृति का होता है और इस प्रकार विधिविरुद्ध क्रियाकलापों के साक्ष्य के स्रोत की जनहित में निरन्तर गोपनीयता बनाए रखना अपेक्षित होता है। ऐसी स्थिति में, ऐसी जानकारी के स्रोत और संभवतः उससे संबंधित पूर्ण व्यौरों का खुलासा करना जनहित के विरुद्ध हो सकता है। अधिनियम की योजना और उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों द्वारा निर्देशित जाँच संबंधी प्रक्रिया में जनहित की अपेक्षानुसार गोपनीयता बनाए रखने का प्रावधान है। हालांकि संस्था तथा इसके पदाधिकारियों को संवेदनशील जानकारी एवं सबूत का खुलासा न किया जाना आवश्यक रूप से यह संकेत नहीं करता कि जब कभी जनहित में औचित्यपूर्ण हो तब उनका खुलासा अधिकरण के समक्ष नहीं किया जा सकता। उन मामलों में जिनमें अधिकरण इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसी जानकारी का खुलासा संस्था अथवा उसके पदाधिकारियों के लिए न किया जाना जनहित में है, तो संस्था अथवा उसके पदाधिकारियों को खुलासा न किया जाना अनुमत

किया जा सकता है किंतु अधिनियम की अपेक्षा के अनुरूप न्याय-निर्णयन के अपने कार्य को निष्पादित करने के लिए अधिकरण सूचना की विश्वसनीयता का आकलन करने के प्रयोजन से उनका निरूपण कर सकता है और स्वयं को इस बात से संतुष्ट कर सकता है कि वह उस पर सुरक्षित रूप से कार्य कर सकता है। ऐसी स्थिति में, अधिकरण एक ऐसी समुचित प्रक्रिया नियत कर सकता है जिसके माध्यम से वह संस्था को विधि विरुद्ध घोषित करने के लिए पर्याप्त कारणों की विद्यमानता निर्धारित करने हेतु उन्हें स्वीकार करने का निर्णय लेने से पूर्व उस सामग्री की विश्वसनीयता की जांच-परख स्वयं कर सकता है। ऐसी सामग्री को केवल विधिक साक्ष्य तक ही सीमित रखे जाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी प्रक्रिया यह सुनिश्चित करेगी कि अधिकरण का निर्णय एक न्याय-निर्णयन है जो केन्द्रीय सरकार की ओर से स्वयं ही निर्णय लेने के अपने कार्य का अधित्याग किए बिना, स्वीकार किए जाने के लिए स्वयं चुनी गई सामग्री की विश्वसनीयता का आकलन करने के पश्चात् निर्विवादित तथ्यों के आधार पर दिया गया है। इस प्रक्रिया से, जनहित को कोई नुकसान पहुँचाए बिना, संस्था और उसके सदस्यों के अधिकारों की रक्षा करते हुए, प्रत्येक मामले की परिस्थितियों के अनुकूल प्राकृतिक न्याय की न्यूनतम आवश्यकता पूरी होगी। इससे यह भी सुनिश्चित होगा कि न्याय-निर्णयन की प्रक्रिया अपनी विषय-वस्तु से पृथक नहीं हुई है और अधिकरण द्वारा जो निर्णय दिया गया है वह न्याय-निर्णयन के पश्चात् निर्विवादित सभी बिंदुओं को ध्यान में रखकर दिया गया है और यह निर्णय केन्द्रीय सरकार द्वारा पहले से ही बना ली गई अपनी राय को मात्र स्वीकार कर लिया जाना ही नहीं है।”

67. भारत संघ बनाम. स्टूडेंट मूवमेंट आफ इंडिया और अन्य, 99(2002)  
डीएलटी.147

इस न्यायालय द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया है कि:-  
“अपराध स्वीकारोक्ति के उल्लिखित बयान जिन पर भारत सरकार भरोसा करती है उन्हें उन अपराधिक मामलों की जांच के दौरान

दर्ज किया गया था जिनमें उन्हें गिरफ्तार किया गया था। साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 में यह प्रावधान है कि किसी पुलिस अधिकारी के समझ अपराध स्वीकारोक्ति को किसी अपराध के दोषी व्यक्ति के खिलाफ प्रमाण नहीं माना जाएगा। 'किसी अपराध का दोषी व्यक्ति' से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके विरुद्ध किसी आपराधिक मामले में सिद्ध किए जाने के लिए साक्ष्य मांगा गया है। अतः 'किसी अपराध का दोषी' नामक आश्रित खंड उस व्यक्ति के बारे में है जिसके खिलाफ अपराध स्वीकारोक्ति को प्रमाणित किए जाने की आवश्यकता है। अपराध स्वीकारोक्ति के बयान का इस्तेमाल दंड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत सिविल कार्यवाहियों और अन्य समतुल्य कार्यवाहियों में किया जा सकता है। इस अधिकरण के समक्ष की गई जांच स्पष्टतः केवल अपराध स्वाकारोक्ति का बयान देने वाले दोषी व्यक्तियों के खिलाफ मात्र एक विचारण नहीं है। इसलिए, यह दर्शाने के लिए कि दोषी व्यक्ति संगम के सदस्य थे अथवा हैं, तथा साथ में यह भी दर्शाने के लिए कि संगम की गतिविधियां विधिविरुद्ध हैं या नहीं, मेरे सुविचारित मत के अनुसार पुलिस अथवा न्यायालय के समक्ष विभिन्न मामलों की जांच के दौरान दोषी व्यक्तियों की अपराध स्वीकृति साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 से प्रभावित नहीं होंगी तथा साक्ष्य में अनुमत है।

68. सुमन और अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य के मामले में 1986 (मद्रास) 318, निम्नानुसार निर्णय दिया गया:-

“यह याद रखना होगा कि जहां धारा 25 उस अपराध स्वकारोक्ति से संबंधित है जिसे किसी अपराध के दोषी व्यक्ति के खिलाफ प्रभावित करना अनुमत नहीं होता वही यह धारा उस अपराध स्वीकारोक्ति का भी उल्लेख भी करती है जिसे उसके विरुद्ध किसी अपराध को सिद्ध करने के लिए प्रभावित किया जाना प्रस्तावित होता है। इसलिए धारा 25 की परिधि दोषी व्यक्ति द्वारा अपराध स्वीकृति तक ही सीमित है जो कि उसके विरुद्ध अपराध सिद्ध करने की कार्रवाई में लागू होती है।”



69. नंदिनी सतपथी बनाम पी एल दानीद और अन्य ए आई आर 1978 ए सी 1025, माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष तौर पर यह माना कि दोषी व्यक्ति का बयान सी आर पी सी की धारा 161 के तहत पुलिस द्वारा रिकार्ड किया जा सकता है। नंदिनी सतपथी मामले (सुपरा) के निर्णय का संबंधित भाग नीचे दिया गया है:-

“.....यह निष्कर्ष कि सी आर पी सी की धारा 161 में “कोई व्यक्ति” में वह व्यक्ति भी शामिल होंगे जब वे उस समय या आखिरकार दोषी पाए जाएंगे। इस विचार का अनुमोदन महाबीर मंडल मामले (1972) 3 एस सी आर 639 पेज 65 (ए आई आर 1972 एस सी 1331, पेज 1341, 1342) में किया गया था। हम मानते हैं कि यदि किसी व्यक्ति के बारे में यह माना जाता है कि वह मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित ऐसे व्यक्ति में वह दोषी व्यक्ति शामिल है जो ऐसा कृत्य करता है तो पुलिस उस व्यक्ति के बारे में यह मानती है कि वह अपराध में शामिल होगा और इसलिए तथ्यों से अवश्य परिचित होगा। ऐसा मानना बाद में काल्पनिक भी हो सकता है परन्तु इससे धारा अस्वीकृत नहीं होती है और ना ही इससे “पुलिस द्वारा साक्षियों की परीक्षा वाली” पार्श्व टिप्पणी मामले को तय करती है। पार्श्व टिप्पणी अस्पष्टता को साफ कर देती है परन्तु अभिप्राय को नियंत्रित नहीं करती है। इसके अतिरिक्त, दोषी माने जाने वाला व्यक्ति गवाह के रूप में कार्य करता है। कार्यात्मक दृष्टिकोण से गवाह बनने के लिए संबंध तथ्यों के संबंध में जानकारी देनी होती है तथा सी आर पी सी की धारा 161 के तहत दोषी से सवाल पूछने का यथार्थ प्रयोजन यही है। “गवाह” और “दोषी” के बीच द्विभाजन करना उचित नहीं है.....”

70. माननीय उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के उल्लिखित निर्णयों की दृष्टि से मेरे मन में कोई संदेह नहीं रह गया है कि पुलिस सी आर पी सी की धारा 161 के तहत दोषी व्यक्ति के बयान दर्ज कर सकती है। सी आर पी सी की धारा 161 के तहत जांच अधिकारी द्वारा दोषी व्यक्ति के बयान को रिकार्ड करने पर एन डी एफ बी संगठन की ओर से उठाई गई आपति में कोई दम नहीं है। वरिष्ठ विद्वान काउंसल द्वारा सहायक साक्ष्य की स्वीकार्यता से संबंधित आपति भी निर्थक है। यह नोट किया जा सकता है कि अधिकरण के सामने सभी सरकारी गवाहों से

की गई जिरह एन डी एफ बी संगठन के लिए काउंसल द्वारा प्रतिपरीक्षा के अधीन की जाती थी परन्तु दस्तावेजों की प्रमाणिकता पर आपति उनके प्रतिपरीक्षा के आधार पर नहीं की जाती है। उन्होंने दस्तावेजों के रचियताओं को प्रस्तुत न करने पर भी आपति नहीं उठाई। वास्तव में, एन डी एफ बी संगठन ने उन्हें उपलब्ध कराए गए उन दस्तावेजों की प्रतियों के आधार पर सरकारी गवाहों से जिरह जिनकी प्रमाणिकता पर उन्हें आपति नहीं थी। मेरा विचार है कि एन डी एफ बी संगठन को अंतिम बहस के दौरान दस्तावेजी साक्ष्यों की स्वीकार्यता के संबंध में ऐसी आपतियों को उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है क्योंकि अधिकरण दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कोई आपराधिक निर्णय नहीं ले रहा है। यह अधिकरण तो एन डी एफ बी संगठन की गतिविधियों के बारे में कोई सम्मति बनाने के लिए सामग्री की उपलब्ध पर्याप्तता के बारे में तथा संगठन को विधि विरुद्ध संगठन घोषित करने की आवश्यकता के बारे में विचार कर रहा है।

71. मुझे एन डी एफ बी संगठन के विद्वान वरिष्ठ काउंसल के इन तर्कों में कोई अच्छाई प्रतीत नहीं होती कि गलत सत्यापन के कारण या सत्यापन सी पी सी के नियम 5 के आदेश 6 के अनुसार होने के कारण सरकारी गवाहों द्वारा साक्ष्यों में दिए गए हलफनामों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। यह नोट किया जा सकता है कि न्याय निर्णय किए जाने वाली अधिसूचना के समर्थन में साक्ष्य के रूप में शपथपत्र प्रस्तुत करने वाले सभी सरकारी साक्षियों ने अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत अपने साक्ष्यों में विशेष रूप से यह साक्ष्य दिए हैं कि उन्होंने अपने-अपने शपथ पत्रों में जिन तथ्यों का उल्लेख किया है वे उन्हें सरकारी रिकार्डों से साक्षियों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर सत्य प्रतीत होते हैं। अतः सरकारी साक्षियों द्वारा अपने साक्ष्यों में प्रस्तुत किए गए शपथपत्रों के जांच अनुच्छेद में कथाकथित कमी की तकनीकी चूक का लाभ उठाने की संगठन को अनुमति नहीं दी जा सकती।

72. एन डी एफ बी संगठन के वरिष्ठ विद्वान कौंसिल द्वारा सरकारी साक्षियों के शपथपत्रों में उल्लिखित अपराधिक मामलों की जांच के संबंध में उठाई गई आपति विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 43 की अपेक्षा के अनुरूप पुलिस उपाधीक्षक के रैंक के पुलिस अधिकारी द्वारा नहीं की गई है और दिनांक 23.11.2008 की अधिसूचना के न्याय निर्णय के लिए उसमें कोई दम प्रतीत नहीं होता। यह नोट किया जा सकता है कि विधि विरुद्ध क्रियाकलाप

(निवारण) अधिनियम, 1967 के अन्तर्गत मामलों की जांच किए जाने के लिए अपेक्षित धारा 43 अध्याय IV और VI के अन्तर्गत उल्लिखित अपराधों के संबंध में है जबकि एन डी एफ बी संगठन के केडरों की संलिप्तता वाले आपराधिक मामले अधिनियम के अध्याय-III में उल्लिखित विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 10 और 13 के साथ भारतीय दंड संहिता के विभिन्न प्रावधानों के अन्तर्गत दर्ज किए गए थे। इसके बावजूद, विगत दो वर्षों के दौरान एन डी एफ बी केडरों के खिलाफ दर्ज किए गए आपराधिक मामलों की जांच किए जाने के लिए पुलिस अधिकारी की समक्षमता से संबंधित प्रश्न पर विचार नामयुक्त दोषी व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक मामलों पर विचारण के दौरान किया जा सकता है न कि इस अधिकरण की कार्यवाही के दौरान।

73. अधिसूचना के पक्ष और विपक्ष में दोनों पक्षों द्वारा दिए गए साक्ष्यों पर गहराई से विचार करने के पश्चात् मुझे सरकारी साक्षियों के साक्ष्य अधिक विश्वसनीय और भरोसेमंद लगते हैं और दिनांक 23.11.2008 की अधिसूचना की संपुष्टि के लिए उन्हें पूरी तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। वास्तव में, एन डी एफ बी संगठन के साक्षियों के जिरह के दौरान दिए गए प्रत्येक बयान एन डी एफ बी संगठन को गैर कानूनी संगठन के रूप में प्रतिबंधित किए जाने के लिए सरकारी मामले का समर्थन करते हैं। एन डी एफ बी के डी डब्ल्यू-1 से डी डब्ल्यू-3 के रूप में तीन साक्षियों से जिरह की गई है। डी डब्ल्यू-1 मि. बी. स्वांखर ने स्वयं को एन डी एफ बी संगठन का महासचिव होने का दावा किया है और उसने अपने साक्ष्य में यह उल्लेख किया है कि एन डी एफ बी का संविधान अभी भी मौजूद है और यह कि उसके शपथपत्र के साथ संलग्न एन डी एफ बी संविधान की प्रति एन डी एफ बी के संविधान का अद्यतन संस्करण है। इस संबंध में डी डब्ल्यू-1 के साक्ष्य के संगत भाग का उल्लेख निम्नवत है :-

“एन डी एफ बी का संविधान” के रूप में उल्लिखित हमारा संविधान आज भी विद्यमान है। यह सही है कि हमारे संविधान में हमारे ध्वज का उल्लेख है। यह सही है कि संविधान का एक अनुच्छेद बोरोलैंड के संबंध में है और यह अनुच्छेद आज भी प्रभावी है।”

74. डी डब्ल्यू-1 के उल्लिखित साक्ष्य के मद्देनजर अब हम एन डी एफ बी के संविधान के प्रावधानों को नोट कर सकते हैं।

“(i) प्रस्तावना

“तीन अक्तूबर 1986 को एकत्रित हुए क्रांतिकारी राष्ट्रभक्तों ने अपनी पैतृक भूमि को और सशस्त्र संघर्ष वाले औपनिवेशिक दमन से लोगों को स्वतंत्र कराने के लिए बोरो सिक्योरिटी फोर्स का गठन किया है जिससे कि सामाजिक-राजनीतिक और आर्थिक-शोषण, दमन, शमन और औपनिवेशिकता से मुक्त स्वतंत्रता, समानता और भाई चारे को संवर्धित करने के लिए जनतांत्रिक सामाजिक समुदाय की स्थापना की जा सके।”

आर्थिक दोहन, उत्पीड़न, दमन और उपनिवेशीकरण ।

ii. अनुच्छेद 4 – सिद्धांत और विचारधारा

- (क) भारतीय विस्तारवाद और अधिपत्य से ब्राडोलैंड को मुक्त करना
- (ख) XXX
- (ग) XXX
- (घ) बोडोलैंड की अखंडता और संप्रभुता कायम करना

iii. अनुच्छेद 18 – बोडोलैंड सेना

राष्ट्रीय मुक्ति के लिए सशस्त्र संघर्ष करने हेतु एन डी एफ बी की अपनी सेना होगी जिसे बोडोलैंड सेना के रूप में जाना जाएगा। बोडोलैंड सेना, सेना प्रतिष्ठान के माध्यम से विनियमित की जाएगी।”

iv. अनुच्छेद 19 – जन क्रांतिकारी सरकार

क्रांतिकारी संघर्ष के दौरान एन डी एफ बी, जन क्रांतिकारी सरकार का गठन और स्थापना करेगी जिसे बोडोलैंड जन गणतंत्र की सरकार के रूप में जाना जाएगा।

v. अनुच्छेद 20 – जन क्रांतिकारी न्यायालय

स्वतंत्र और निष्पक्ष दोष सिद्धि के लिए एन डी एफ बी की जन क्रांतिकारी न्यायालय के रूप में जानी जाने वाली न्यायपालिका होगी।

vi. अनुच्छेद 21 – शपथ

.....राष्ट्र की ईमानदारी और सत्यवादिता से सेवा करने के लिए संविधान, एन डी एफ बी के प्रति सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूँ और पार्टी की एकता और अखंडता के संरक्षण और सुरक्षोपाय के लिए भी शपथ लेता हूँ और एतद्वारा प्रतिजान करता हूँ कि बोडोलैंड की मुक्ति के लिए पूरी जी जान से संघर्ष करूंगा।”

75. डी डब्ल्यू-2, श्री आई. दामिनी, ने स्वयं को एन डी एफ बी संगठन का गृह सचिव घोषित किया और पूछ-ताछ के दौरान उन्होंने निम्नवत स्वीकार किया :-

“हमारे बोडो लोगों को आज भी उनके मान, सम्मान, भू-भाग और संप्रभुता से वंचित किया जाता है। भारत सरकार द्वारा बोडो लोगों का शोषण आज भी जारी है।”

76. डी डब्ल्यू-1 से की गई पूछ-ताछ के दौरान उन्होंने बताया कि एन डी एफ बी संगठन, आत्मनिर्णय के अपने अधिकार पर विश्वास करता है। डी डब्ल्यू-3, श्री बी.के. ओलोंगबार ने इसी आशय का अभिसाक्ष्य दिया है और उन्होंने अपने आप को बोडोलैंड राष्ट्रीय जनतांत्रिक मोर्चे का शिक्षा सचिव घोषित किया है।

76. एन डी एफ बी संगठन के उपर्युक्त गवाहों के अभिसाक्ष्यों से यह स्पष्ट होता है कि उक्त संगठन अभी भी सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से अपने बोडो समुदाय के लिए भारत से पृथक संप्रभुता और भू-भाग में विश्वास करता है। एन डी एफ बी का संविधान, जो संगठन के गवाहों के अनुसार अभी भी अस्तित्व में है, के पास (1) आम सभा, (2) राष्ट्रीय परिषद, (3) सपथ, (4) झंडा, (5) संप्रतीक, (6) न्यायपालिका, (7) सेना प्रशिक्षण, (8) कर निर्धारण और दान के माध्यम से धन जुटाना, (9) अध्यक्ष और (10) बोडो समुदाय के लिए पृथक भू-भाग है।

77. यदि एन डी एफ बी संगठन, 2005 के संघर्ष विराम, जो आज की तारीख तक जारी है, की शर्तों के अनुसार शांति के बारे में गंभीर था तो उन्हें अपनी मांगे मानवाने के लिए हिंसा का सहारा नहीं लेना चाहिए था और इसकी बजाय शांतिपूर्ण हल के लिए परस्पर बातचीत के माध्यम से अपने मांग पत्र के साथ उन्हें सरकार के पास आना चाहिए था। यस्तुतः इस संघर्ष विराम करार ने बोडो समुदाय के सामने आ रही कथित समस्याओं को दूर करने के लिए राजनीति

वार्ता के लिए एक प्लेटफार्म प्रदान किया था। मुझे प्रस्तुत किए गए साक्ष्य से मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि एन डी एफ बी संगठन ने संघर्ष विराम करार की शर्तों के अनुसार शांतिपूर्वक वार्ता करने के बजाय विगत दो वर्षों के दौरान विभिन्न विधिविरुद्ध आपराधिक क्रियाकलापों का सहारा ले करके एन डी एफ बी संगठन और भूत-पूर्व बोडो लिबरेशन टाइगर, उस समय हैग्रामा मौहिलैरी जिसके प्रमुख थे, के बीच महज संभावित झड़पों के कारण सैकड़ों ऐसे निर्दोष लोगों की जान ली जिनका कोई दोष नहीं था। यह नोट करना आवश्यक होगा कि डी डब्ल्यू-1 श्री बी. स्वांखर से की गई पूछ-ताछ के दौरान उन्होंने कहा कि एन डी एफ बी संगठन की तीन बटालियनें हैं और यह भी स्वीकार किया कि उनके संगठन की ये बटालियनें हथियारों के साथ काम कर रही हैं। सामान्यतया, यह सुना गया है कि चाहे कोई संगठन विधिसम्मत हो या विधिविरुद्ध हो, उसकी कोई बटालियन नहीं होती है। डी डब्ल्यू-1 से की गई पूछ-ताछ के दौरान एन डी एफ बी संगठन की तीन बटालियनों की मौजूदगी के बारे में जो उन्होंने बताया है उससे स्वतः संगठन के पास मिलिट्री ढांचे की मौजूदगी परिलक्षित होती है। डी डब्ल्यू-3 श्री ओलॉगबर से की गई पूछताछ के दौरान उन्होंने बताया कि संगठन की आम सभा ने दिनांक 15.12.2008 को उन्हें शिक्षा सचिव के रूप में नियुक्त किया था और उनकी उक्त नियुक्ति से पहले वे संगठन में विदेश सचिव के रूप में कार्य कर रहे थे। उनसे की गई पूछ-ताछ के दौरान उन्होंने स्वीकार किया कि एन डी एफ बी संगठन में विदेश सचिव का यह कार्य है कि वह भारतीय भू-भाग से बाहर स्थित विभिन्न संगठनों के साथ समन्वय करे। उन्होंने बताया कि 2005 के संघर्ष विराम के बाद उन्हें विदेश सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने यह भी बताया कि 2005 के संघर्ष विराम के बाद विदेश सचिव का पद समाप्त कर दिया गया था। मैं यह बात नहीं समझ पाया हूँ कि 2005 के संघर्ष विराम के बाद विदेश सचिव का पद समाप्त किए जाने की सूरत में 2005 के संघर्ष विराम के बाद आम सभा ने डी डब्ल्यू-3 श्री बी.के. ओलॉगबर को विदेश सचिव के रूप में क्यों नियुक्त किया। ऐसा प्रतीत होता है कि इसके पीछे कुछ रहस्य छिपा है। डी डब्ल्यू-3 से की गई पूछताछ के दौरान उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि भारतीय पासपोर्ट के बगैर दो बार वे बांग्लादेश गए थे जो गैर-कानूनी घुसपेठ मानी जाएगी। डी डब्ल्यू-3 का यह बयान कि 2005 के संघर्ष विराम से पहले वे दो बार बांग्लादेश गए थे, वे अभिकरण का विश्वास नहीं जीत सकते हैं। डी डब्ल्यू-3 ने रिकॉर्ड पर ऐसा कोई विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जो यह दर्शाता हो कि उनके अवैध बांग्लादेश दौरे, 2005 के संघर्ष विराम से पहले के हैं।

यह नोट करना दिलचस्प होगा कि डी डब्ल्यू-3 ने पूछताछ के दौरान यह अभिसाक्ष्य दिया है कि 2005 के संघर्ष विराम करार से पहले वे एन डी एफ बी संगठन के उप सेना प्रमुख के रूप में कार्य कर रहे थे और उन्होंने हथियार और गोलाबारूद का प्रयोग करने में विशेषज्ञता हासिल कर ली थी। उनका यह बयान कि शिक्षा सचिव के रूप में उनका यह कार्य है कि वे संगठन के सदस्यों और बोडो समुदाय के लोगों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करें कि वे राज्य सरकार के स्कूलों और कालेजों में पढ़ने जाएं, इसमें मेरा विश्वास इस कारण नहीं बनता है कि उनके स्वयं के साक्ष्य के अनुसार संगठन का एक भी संवर्ग या सदस्य किसी भी उक्त स्कूल या कालेज में नहीं गया है। इस मामले में एक और महत्वपूर्ण पहलू को अभी भी नोट किया जाना है। संगठन के सदस्यों/संवर्गों के विरुद्ध दर्ज किए गए कुछ आपराधिक मामलों का संबंध जबरन धन वसूली से है। दिनांक 23.11.2008 की अधिसूचना के विरुद्ध एन डी एफ बी संगठन द्वारा जिन तीन गवाहों से पूछताछ की गई उन सभी गवाहों ने अपने-अपने बयानों में कहा है कि संगठन के महासचिव, गृह सचिव और शिक्षा सचिव के रूप में कार्य कर रहे हैं लेकिन वे संगठन से कोई वेतन नहीं ले रहे हैं। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि संगठन के सचिवों के रूप में कार्य करने के लिए उनके पास कोई कर्मचारी या आधारभूत व्यय नहीं है। उन्होंने बताया कि अपनी आजीविका के लिए टी.ए. आदि के रूप में संगठन की निधियों पर निर्भर हैं। संगठन ने रिकार्ड पर ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जो इसके निधिकरण के स्रोत के बारे में दर्शाता हो और ऐसा कोई स्रोत न होने की सूरत में यही माना जा सकता है कि अपनी विधिसम्मत और विधिविरुद्ध क्रियाकलापों के लिए अपेक्षित निधि जुटाने हेतु संगठन, जबरन धन वसूली के कार्यों में संलग्न है।

78. एन डी एफ बी संविधान के अनुच्छेद 17 में यह व्यवस्था की गई है कि कर निर्धारण और शुभचिंतकों से दान प्राप्त करके धन जुटाया जाएगा। डी डब्ल्यू-1 श्री स्वम्खबर से कहा गया कि वे अनुच्छेद 17 में प्रयुक्त “कर निर्धारण”, “दान” और “शुभ चिंतक” शब्दों को स्पष्ट करें तो उन्होंने उत्तर दिया कि अनुच्छेद 17 में प्रयुक्त “शुभचिंतक” शब्द का संबंध उन व्यक्तियों से है जो बोडोलैंड संविधान का समर्थन करते हैं तथा अनुच्छेद 17 में प्रयुक्त “कर निर्धारण” शब्द को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि इसका अर्थ, गैर-बोडो लोगों से वसूली करके धन जुटाना है। तथापि उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि यह युद्ध विराम करार, 2005 से पहले का था। डी डब्ल्यू-1 का यह बयान मुझे भरोसेमंद नहीं लगता क्योंकि युद्ध विराम करार

06.01.2009 में संगठन को किसी भी तरह का डोनेशन लेने से मनाही है और उक्त नियम को संगठन के तीनों गवाहों ने अपने साक्ष्य में उनके द्वारा दायर हलफनामा के पैरा 8 में दुर्भाग्यपूर्ण बताया है।

79. डी. डब्ल्यू-3 श्री ओलॉगवार से एक संगत प्रश्न पूछा गया कि उन्होंने डोनेशन बंद करने को दुर्भाग्यपूर्ण क्यों कहा जिसका डी डब्ल्यू-3 ने निम्नलिखित उत्तर दिया:

“हम डोनेशन संग्रह करना बंद करने को दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए समझते हैं क्योंकि नामोद्विष्ट शिविरों में हमारे जीवन का स्तर अत्यधिक दयनीय है। अभी हाल ही में एक तूफान आया जिससे उडालगिरी स्थित हमारा नामोद्विष्ट शिविर पूर्णतया तहस-नहस हो गया और सरकार द्वारा हमारे डोनेशन संग्रह पर रोक लगा दिए जाने से हमारे मन में पूर्व धारणा बन गई कि इसी कारण उडालगिरी नामोद्विष्ट शिविर में अपने सदस्यों एवं काडरों के पुनर्वास के लिए हमारे पास पर्याप्त निधियाँ नहीं हैं। इसी कारण हम डोनेशन संग्रह को बंद करना दुर्भाग्यपूर्ण मानते हैं।”

80. डी डब्ल्यू-3 द्वारा दिए उक्त उत्तर, प्रति-परीक्षण में डी. डब्ल्यू-2 द्वारा दिए गए बयान कि बोरो लोग आज भी अपने मान, सम्मान, अपने भू-भाग एवं सम्प्रभुता से वंचित हैं और यह कि भारत सरकार द्वारा आज भी बोरो लोगों को दबाया जा रहा है आदि के परिप्रेक्ष्य में इनका अत्यधिक महत्व है। डी.डब्ल्यू-1 और डी. डब्ल्यू-3 ने अपने बयान में बताया कि वे अपने अधिकार एवं स्वाधीनता में पूर्ण विश्वास रखते हैं। यह सब क्या दर्शाता है? इसका अभिप्राय यह है कि इस संगठन द्वारा भारत सरकार के साथ किया गया युद्ध विराम समझौता मात्र एक छलावा है। उनका इरादा अन्यथा था। उन्होंने असम में निर्दोष लोगों की हत्या करके अपनी उग्रवादी गतिविधियाँ जारी रखी। मेरे इस निष्कर्ष की पुष्टि प्रति परीक्षण में डी. डब्ल्यू-2 के बयान द्वारा की जाती है। जिसमें वह यह कहता है कि एन डी एफ बी संगठन के कुछ सदस्यों को जिनके नाम सरकार द्वारा प्रस्तुत एन डी एफ बी काडरों की सूची में शामिल किए गए हैं, पिछले दो वर्षों के दौरान विभिन्न आपराधिक मामलों में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। युद्ध विराम करार में दी गई शर्तों के अनुसार यदि एन डी एफ बी काडर तीन नामोद्विष्ट शिविरों में रह रहे होते और शिविर कमाण्डर के प्राधिकृत किए गए बिना शिविर से बाहर नहीं जाते तो नामोद्विष्ट शिविरों में रह रहे उन काडरों को राज्य पुलिस गिरफ्तार नहीं



करती और एन डी एफ बी संगठन द्वारा उनसे स्पष्टीकरण नहीं पूछा जाता। डी. डब्ल्यू.-2 श्री दामिनी दावा करता है कि वह एन डी एफ बी संगठन का गृह सचिव है और ऐसा कहा जाता है कि उसने 1998 में एन डी एफ बी ज्वाइन किया। उसका नाम युद्ध विराम करार के समय सरकार को दी गई सदस्यों की सूची में शामिल नहीं था। डी. डब्ल्यू.-2 ने अपने प्रति परीक्षण में स्वीकार किया कि उसे यह दर्शाने के लिए सरकार ने कोई पहचान पत्र नहीं दिया कि वह एन डी एफ बी काडर से सम्बंधित है। डी. डब्ल्यू.-2 का कहना है कि भूलबश उन्हें पहचान पत्र जारी नहीं किया गया था। क्या गलती थी इसे गवाह ने स्पष्ट नहीं किया। डी. डब्ल्यू.-2 के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि वह एन डी एफ बी संगठन का सदस्य था, परन्तु, संगठन को ज्ञात किसी कारणबश, उसका नाम सरकार को प्रस्तुत की गई सूची में शामिल नहीं किया गया था। पी डब्ल्यू-4 मि. डेका के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत थाना बिजनी के मामले सं० 106/2007 में राज्य पुलिस ने कनक दैमारी नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था। जब वह इस मामले में गिरफ्तार किया गया तो उसके पास से उसका पहचान पत्र जिस पर उसका फोटो लगा था उसके पास से मिला जिस पर उसका नाम डी. खाब्रांग लिखा था। अपने पहचान पत्र पर अलग नाम लिखा प्राप्त होने पर, इस मामले में गिरफ्तार कनक दैमारी ने कहा कि उसे डी. खाब्रांग के नाम से भी जाना जाता है और इसी कारण उस मामले के अभियुक्त व्यक्तियों की सूची में उसके नाम का कनक दैमारी उर्फ डी. खाब्रांग के रूप में उल्लेख किया गया। उस मामले में अभियुक्त इस उर्फ वाले नाम से यह स्पष्ट होता है कि युद्ध विराम करार के दौरान संगठन द्वारा सरकार को प्रस्तुत इसके सदस्यों की सूची में या तो काल्पनिक नाम हैं या काडर के सभी नामों को शामिल नहीं किया गया। इस प्रकार का सुझाव डी. डब्ल्यू.-3 ने अपने प्रति परीक्षण में दिया जिसे उसने नकार दिया। ऊपर उल्लिखित कारणों से डी. डब्ल्यू.-3 द्वारा नकारे जाने का कोई मतलब नहीं है। इस अधिसूचना के विरुद्ध संगठन द्वारा परीक्षण किए गए सभी तीनों गवाहों ने अपने-अपने प्रति परीक्षण में स्वीकार किया है कि इस संगठन ने अपने पूर्ववर्ती अध्यक्ष श्री राजन दैमारी उर्फ डी. आर. नाबला को दिनांक 30.10.2008 में हुए बम विस्फोट के मामले में तथाकथित संलिप्तता के कारण निष्कासित कर दिया था। एन डी एफ बी के गवाह की यह स्वीकारोक्ति से स्पष्ट सिद्ध होता है कि उनके शीर्षस्थ नेता तथा संगठन के अन्य काडर/सदस्य युद्धविराम करार, 2005 पर हस्ताक्षर होने के बावजूद विभिन्न विधिविरुद्ध क्रियाकलापों में संलिप्त हैं। यह पूर्णतया स्पष्ट है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा दिनांक 23.11.2006 की पिछली अधिसूचना के तहत प्रतिबंध लगाए

जाने के बावजूद, प्रतिबंधित संगम और इसके पदधारी/सदस्य अभी भी विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 2(0) में यथापरिभाषित विधिविरुद्ध क्रियाकलापों में संलिप्त हैं।

81. अपनी रिपोर्ट का समापन करने से पहले मैं एन डी एफ बी संगठन की ओर से दायर लिखित विवरण में दी गई एक आत्मस्वीकृति का उल्लेख करना चाहता हूँ जो निम्नलिखित है-

“यह समस्या त्रिपक्षीय करार के सभी पक्षों के गहन प्रयासों से शीघ्र हल की जानी चाहिए। परिस्थितियों गम्भीर हो सकती हैं, जो नहीं होना चाहिए (जोर दिया गया)।

82. एन डी एफ बी संगठन की ओर से की गयी इस आत्मस्वीकृति से स्पष्टतया इंगित होता है कि उनकी ओर से गम्भीर परिणामों की धमकी दी जा रही है।

83. पूर्ववर्ती कारणों से मैं संतुष्ट हूँ कि एन डी एफ डी संगठन को विधिविरुद्ध संगम के रूप में घोषित किए जाने के पर्याप्त कारण मौजूद हैं। तदनुसार, यह अधिकरण विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 3 की उपधारा(1) के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा दिनांक 23.11.2008 को जारी अधिसूचना के तहत घोषणा की सम्पुष्टि करता है।

18 मई, 2009

ह0/

(न्यायमूर्ति एन एन अग्रवाल)

विधिविरुद्ध क्रियाकलाप

(निवारण) अधिकरण

**MINISTRY OF HOME AFFAIRS****NOTIFICATION**

New Delhi, the 17th June, 2009

**S.O. 1507(E).**—In terms of Section 4(4) of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, the order of the Tribunal presided over by Hon'ble Justice Shri S. N. Aggarwal Judge, Delhi High Court to whom a reference was made under Section 4(1) of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 for adjudicating whether or not there is sufficient cause for declaring the associations, namely the National Democratic Front of Boroland (NDFB) Organisation of Assam as unlawful is published for general information.

[No. 11011/54/2008-NE-III]

NAVEENVERMA, Jt. Secy.

**BEFORE THE UNLAWFUL ACTIVITIES (PREVENTION)  
TRIBUNAL PRESIDED OVER  
BY  
HON'BLE MR. JUSTICE S.N. AGGARWAL**

**REPORT OF THE NDFB TRIBUNAL CONSTITUTED BY THE  
GOVERNMENT VIDE ITS NOTIFICATION NO. SO.2869(E)  
DATED 12.12.2008**

In Re: National Democratic Front of Boroland

The Association, namely, the Boro Security Forces, since rechristened as National Democratic Front of Boroland (hereinafter referred to as the 'NDFB'), has as its professed aim, the 'liberation' of Boroland consisting largely of Boro inhabited areas of Assam and to bring the secession of the said areas from India, in alliance with other armed secessionist organizations of the North East Regions. Its activities are said to be for promoting this objective. A

Notification dated 23.11.2008 published in the Official Gazette, the same day, was issued by the Government of India in the Ministry of Home Affairs, as under :-

..

**MINISTRY OF HOME AFFAIRS  
NOTIFICATION**

**New Delhi, the 23<sup>rd</sup> November, 2008**

**S.O. 2714(E)-** Whereas, the Bodo Security Forces since rechristened as National Democratic Front of Boroland (hereinafter referred to as the NDFB) has as its professed aim, the "Liberation" of Bodoland consisting largely of Bodo inhabited areas of Assam and to bring the secession of the said areas from India, in alliance with other armed secessionist organizations of the North East Region;

opinion that the NDFB having agreed to abjure violence after signing of suspension of operation Agreement with Government of India and Government of Assam on 1<sup>st</sup> June, 2005, has continued to -

- (i) indulge in illegal and violent activities intended to disrupt, or which disrupt, the sovereignty and territorial integrity of India in furtherance of its objective of achieving a separate Bodoland;
- (ii) align itself with other undergrounds outfits of the North Eastern Region namely the United Liberation Front of Asom and the National Socialist Council of Nagaland (Isac-Muviah) in furtherance of its objectives to create a separate Bodoland;
- (iii) engage in unlawful and violent activities thereby undermining the authority of the Government of India and Government of Assam and spreading terror and panic among the people;
- (iv) indulge in extortion of money from various sections of the society with a view to finance and execute its plans and activities;
- (v) embark on a systematic drive for recruitment of fresh cadres with a view to continuing its terrorist and insurgency activities;
- (vi) create carnage and ethnic violence resulting in killings, destruction of property of non-Bodos inhabiting in Bodo dominated areas in Assam with a view to spread panic and insecurity among non-Bodos;

- (vii) establish camps and hideouts across the Country's border to carry out its secessionist activities;

And whereas, the Central Government is further of the opinion that the violent activities include-

- (i) 16 violent incidents in 2006 resulting in killing of 9 civilians and 5 personnel of security forces;
- (ii) 31 violent incidents in 2007 resulting in killing of 3 civilians;
- (iii) 63 violent incidents in 2008 (upto 15<sup>th</sup> July, 2008) resulting in killing of 14 civilians.

And whereas, the Central Government is also of the opinion that for the reasons aforesaid, the activities of the NDFB are detrimental to the sovereignty and integrity of India and that it is an unlawful association;

And whereas, the Central Government is also of the opinion that unless the unlawful activities of the NDFB are kept under control, the organizations may re-group and re-arm itself, make fresh recruitments, indulge in violent, terrorist and secessionist activities, collect funds and endanger the lives of innocent citizens and security forces personnel; and therefore, circumstances do exist which render it necessary to declare the NDFB as an unlawful association with immediate effect;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby declares the National Democratic Front of Boroland (NDFB) as an unlawful association;

The Central Government, is of further opinion that it is necessary to declare the NDFB to be an unlawful association with immediate effect and accordingly, in exercise of powers conferred by the proviso to sub-section (3) of Section 3 of the said Act, the Central Government hereby directs that this notification shall, subject to any order that may be made under Section 4 of the said Act, have effect from the date of its publication in the Official Gazette.

**[F.No. 11011/54/2008-NE-III]  
NAVEEN VERMA, Jt. Secy.]**

2. As provided in Section 5(1) of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (hereinafter referred to as the 'UA Act' in short), I was appointed by the Government of India as one-man Tribunal vide its Notification No. S.O. 2869(E) dated 12.12.2008, and the Notification dated 23.11.2008

was referred by the Central Government to me for the purpose of adjudicating whether or not there is sufficient cause for declaring the NDFB organization as an unlawful association.

3. Consequent upon my appointment as one-man Tribunal, vide Government notification dated 12.12.2008 referred above, I appointed Mr. Anil Kumar Koushal as the Registrar of the Tribunal and his appointment as Registrar of the Tribunal was notified by the Government vide order No. 11011/54/2008-NE.III dated 16.12.2008. Thereafter, vide my order dated 07.01.2009, I directed the Registrar of the Tribunal to send notice to the NDFB organization to show cause within 30 days from the date of service of the said notice on it as to why the said organization be not declared as an unlawful association. This direction was given as required under the provisions of Section 4(2) of the UA Act. The notice to show cause was directed to be served on the NDFB organization at all its available addresses besides getting the same published in two daily national newspapers and two local newspapers of Assam. The notice was further directed to be served on the NDFB organization by affixing a copy thereof at conspicuous part of the office of the said organization, if any. The notice, as required under Section 4(2) of the UA Act, was duly served upon the NDFB organization and I was satisfied about the service of notice on the said organization from the affidavits of service filed on record.

4. In response to the notice served upon the NDFB organization, the NDFB has entered appearance before this Tribunal through its advocates, namely, Mr. Atanu Ganguly and Mr. N. Zaman. They filed their reply on behalf of the NDFB on 24.02.2009 before this Tribunal and thereafter, also filed an additional reply on 02.03.2009. The reply and additional reply were filed on behalf of the NDFB within the time limit granted to them in the show cause notice.

5. As the NDFB had filed its reply in opposition to the Notification of the Government banning its activities, I asked Mr. P.P. Malhotra, learned Additional Solicitor General of India, appearing on behalf of Union of India, and also the Standing Counsel for Government of State of Assam and the counsel for the NDFB to file their substantive affidavits in their evidence in support of their rival assertions. In compliance with this direction, thirteen affidavits have been filed in evidence on behalf of Government of State of Assam, one affidavit has been filed by Mr. S.K. Roy, Joint Secretary (Home), Government of State of Assam and one affidavit by Mr. R.R. Jha, Director (North East-II), Ministry of Home Affairs, Government of India, New Delhi. Three affidavits have been filed in evidence on behalf of NDFB. The witnesses who have filed their affidavits in evidence-in-chief have been extensively cross-examined by counsel for opposite parties.

6. Thirteen affidavits filed by the Superintendents of Police of various districts in the State of Assam, have been placed before the Tribunal in three Volumes, i.e., Volume I-

Volume III. All the thirteen Superintendents of Police who have filed their affidavits in evidence have appeared as witnesses before the Tribunal. The particulars of these thirteen Superintendents of Police who have filed their affidavits in evidence are as follows :

- PW-1 Mr. Pradip Chandra Saloi, SP, Guwahati City, Assam (Affidavit – Pages 154-388 in Vol.II)
- PW-4 Mr. Arnab Deka, SP, Chirang District, Assam (Affidavit – Pages 464-499 in Vol.II)
- PW-5 Mr. Devojoyoti Mukherjee, SP, Barpeta District, Assam (Affidavit – Pages 630-660 in Vol.III)
- PW-6 Mr. Arabinda Kalita, SP, Kokrajhar District, Assam (Affidavit – Pages 806-885 in Vol.III)
- PW-7 Mr. Krishna Kumar Sharma, SP, Karbi Anglong District, Assam (Affidavit – Pages 500-615 in Vol.III)
- PW-8 Mr. Nitul Gogoi, SP, Nagaon District, Assam (Affidavit – Pages 616-629 in Vol.III)
- PW-9 Mr. Surendra Kumar, SP, Sonitpur District, Assam (Affidavit – Pages 661-689L in Vol.III)
- PW-11 Mr. Sayed Ataul Karim, SP, Lakhimpur District, Assam (Affidavit – Pages 781-805 in Vol.III)
- PW-12 Mr. Rana Bhuyan, SP, Baksa District, Assam (Affidavit – Pages 389-426 in Vol.II)
- PW-13 Mr. Bir Bikram Gogoi, ASP (HQ), Golaghat District, Assam (Affidavit – Pages 886-905 in Vol.III)
- PW-14 Mr. Anand Prakash Tiwari, SP, Udalguri District, Assam (Affidavit – Pages 427-463 in Vol.II)
- PW-15 Mr. Partha Sarathi Mahanta, SP, Dhubri District, Assam (Affidavit – Pages 689M-780 in Vol.III)
- PW-3 Ms. Banya Gogoi, SP, Special Operation Unit, Government of Assam, Guwahati (Affidavit – Pages 146-153 in Vol.I)

7. The details of the other two witnesses examined on behalf of the Government in support of its notification are as under :-



- PW-2 Mr. S.K. Roy, Joint Secretary, Home and Political Department, Government of Assam, Dispur, Guwahati (Affidavit – Pages 1-145 in Vol.I)
- PW-10 Mr. R.R. Jha, Director, Ministry of Home Affairs, Government of India, New Delhi (Affidavit – Pages 1-31 in separate folder described as Part IV file)

8. The details of the three witnesses examined by NDFB in opposition to the Notification in question are as follows:

- DW-1 Mr. B. Swmkhwr, General Secretary of NDFB (Affidavit – Pages 1-44 in separate folder described as Part V file)
- DW-2 Mr. I. Damini, Home Secretary of NDFB (Affidavit – Pages 1-6 in separate folder described as Part V file)
- DW-3 Mr. B.K. Olongbar, Education Secretary of NDFB (Affidavit – Pages 1-6 in separate folder described as Part V file)

9. Now, I will revert to the evidence produced by the Government of State of Assam and the Central Government in support of its Notification dated 23.11.2008 banning the NDFB organization as an unlawful association. PW-1, PW-3 to PW-9 and PW-11 to PW-15, who are all Superintendents of Police of various districts in State of Assam, have testified in their evidence that they all, besides looking after law and order responsibilities in their respective districts, also monitor the investigation of unlawful cases, particularly those undertaken by the terrorist organizations. According to the police witnesses, the cadres of the NDFB are very active in and around the State of Assam and they are

indulging in large-scale unlawful activities and are waging war against the Government of India including the Government of State of Assam. As per the testimony of the police witnesses, cadres of NDFB are terrorizing the local inhabitants by creating fear in their minds through their various acts of omission and commission.

10. PW-1, Mr. Saloi, in his affidavit, Ex.PW-1/1, has referred to certain incidents of violence that took place in his jurisdiction in which according to him, cadres of NDFB were found involved. He has testified that on 30.10.2008, three serial bomb blasts had taken place in the city of Guwahati in a short time gap of 10 minutes between 11:20 AM and 11:30 AM. As per the testimony of PW-1, Mr. Saloi, around 11:20 AM, a bomb planted in a car parked at the parking place of CJM Court, Kamrup, Guwahati, exploded and due to the said explosion, 13 persons died and 68 were injured. In that explosion, 91 vehicles were reported to be completely gutted. The Court building of CJM Court and the boundary wall of DC, Kamrup (M) office was reported to be damaged partially. Around 11:25 AM, a bomb planted in a car parked by the side of H.B. Road in front of Baptist Church, Pan Bazar, exploded and due to the said explosion, 8 persons were reported to have died and 44 injured. In that explosion that took place around 11:25 AM, 13 number of four wheelers and two wheelers and 7 shops were gutted. The third explosion took place on the same date, i.e.,

30.10.2008 around 11:30 AM when a bomb planted in a car parked beneath the Ganeshguri Flyover in front of Hotel Delecacy, exploded. In this bomb explosion that took place around 11:30 AM, 32 people died and 142 were injured. 65 vehicles were completely smashed, 8 shops and business establishments and Ganeshguri Flyover Bridge are reported to have been damaged partially.

11. Mr. Saloi (PW-1) has deposed in his affidavit that three FIRs with regard to incidents of three serial car bomb blasts were got registered and he has given the details of all the three FIRs in para (1), (2) and (3) of his affidavit Ex.PW-1/1. Mr. Saloi has testified that during the investigation carried out in the case of bomb blast that took place around 11:20 AM in the jurisdiction of PS Pan Bazar, four people of NDFB organization, namely, (1) Rajib Sainary (2) Phungkha Brahma (3) Mridul Basumatary and (4) Pabitra Boro were arrested and they, during their interrogation, admitted that the bomb that blasted in the jurisdiction of PS Pan Bazar around 11:20 AM on 30.10.2008 was planted by the NDFB cadres who are involved in secessionist activities violating ground rules of the ceasefire. With regard to the incident of car bomb blast that took place around 11:25 AM also in the jurisdiction of PS Pan Bazar, Mr. Saloi has stated in his evidence affidavit that two persons of NDFB organization, namely, (1) Dipak Basumatary @ Dengkhaw Raja and (2) Anup Kr. Boro @ Nala were arrested and they have

admitted that the bomb that exploded around 11:25 AM was planted by the NDFB cadres. Similarly, as per the statement of Mr. Saloi, four persons of NDFB organization, namely, (1) Anup Kr. Boro @ Nala (2) Nilim Daimary @ D. Nizimsa (3) Sabin Boro @ B. Susrangu and (4) Sri Bimal Musahary, were arrested in regard to the incident of bomb blast that took place around 11:30 AM beneath the Ganeshguri Flyover and all those four persons arrested in that case, during their interrogation have confessed the involvement of the NDFB cadres in that incident.

12. PW-4, Mr. Deka has given evidence in his affidavit Ex.PW-4/1 with regard to two incidents that took place in his jurisdiction, i.e., Chirang District of Assam, first on 14.06.2007 and second on 06.10.2008. With regard to the incident of 14.06.2007, Mr. Deka has stated in his affidavit that Mr. Rameshwar Singha, Assistant Commandant, D/116 Bn. CRPF, New Bongaigon, Assam had lodged a FIR at Bijni Police Station to the effect that on 14.06.2007 at about 15:30 PM, acting on a tip of CRPF personnel led by him, he had cordoned the area of Fancy Bazar and had apprehended one Boro youth, namely, Shri Konok Daimary with one Hero Honda Motorcycle bearing Registration No. AS 15B 1152. When the person of Konok Daimary was searched by CRPF C/N Santosh Choudhury, Konok Daimary took out a pistol and hit Santosh Choudhury and managed to escape from the hands of CRPF jawans. However, he was

immediately chased and overpowered. Following articles were recovered and seized from his possession:-

- 1 One 7.62 Chinese pistol
- 2 One magazine
- 3 8 rounds live ammunitions.
- 4 4 purses with an total amount of Rs.1,900.00.
- 5 One Nokia mobile phone
- 6 One I-card.
- 7 One Hero Honda motorcycle bearing Regd. No.AS 15 B 1152

13. As per the testimony of PW-4, Mr. Deka, sufficient evidence was found during investigation against arrested accused, Shri Konok Daimary @ D. Khabrang, suspected to be a cadre of NDFB.

14. With regard to second incident of 06.10.2008 deposed by PW-4, Mr. Deka, he has stated that one Azamal Haque Khandakar of Village Muzabari, had lodged an FIR at Police Station Sidli on 06.10.2008 to the effect that in the night of that day at about 0045 hours, some unknown armed miscreants came into his court-yard and fired two rounds of ammunition and after firing, those unknown miscreants went to the houses of his neighbours, namely, Rustam Ali and Kuddus Ali and there, they fired indiscriminately towards his house from outside, as a result of which, married daughter of Rustam Ali received bullet injury on her abdomen and she died on the spot. Rustam Ali received simple bullet injury on his head and Kuddus Ali received bullet injury on his shoulder. The injured persons were

shifted by the Police to lower Assam hospital, Bongaigaon for treatment. With regard to the incident of 06.10.2008, that took place in the jurisdiction of PW-4, Mr. Deka, a case No. 41/2008 was registered in PS Sidli (Annexure 'H' to the affidavit of PW-4, Mr. Deka). During investigation of this case No. 41/2008, two persons, namely, Odal Wary, and Moda Goyari @ Mukle, were arrested and interrogated by the Police and during their interrogation, they disclosed to the Police that they were part of a six-member group of NDFB who had attacked the houses of Muslim community in Village Muzabari with a view to create terror. Mr. Deka has annexed the copies of the statements of the witnesses and of the accused persons recorded by the Investigating Officer along with his affidavit, Ex.PW-4/1 as documents Annexures 'K' and 'L'. Certain arms and ammunition were recovered from the possession of the arrested accused persons of NDFB cadres as mentioned in the Seizure List annexed as Annexure 'M' to the affidavit of Mr. Deka. PW-4, Mr. Deka, has stated on oath that he has himself seen the case diaries of cases of both the incidents of 14.06.2007 and 06.10.2008 which, according to him, reveal the involvement of NDFB and its members in the unlawful activities including assault, murder, illegal possession of arms and ammunition, attempt to murder, attack on non-Boro people with an intention to create a fear psychosis, disrupt communal harmony in violation of the ground rules for Suspension of Operation

agreed between the Government of India, Government of State of Assam and the NDFB on 01.06.2005 and to actively wage war against the State.

15. PW-5, Mr. Mukherjee, has given evidence with regard to two Integrated Electronic Device (IED) explosions that took place in his jurisdiction around the same time and on the same day, i.e., 30.10.2008 when three serial car bomb blasts had taken place simultaneously in the jurisdiction of PW-1, Mr. Saloi. As per the testimony of PW-5, Mr. Mukherjee, an IED explosion occurred around 11:28 AM on 30.10.2008 at the Vegetable Market located on the northern side of Barpeta Road Railway Station and in that explosion, 9 persons died on the spot and 164 sustained grievous/minor injuries, for which case No. 262/08 under Section 120 B/121(A)/126/153 B/302/326 IPC readwith Section 3 of the Explosives Substance Act, was registered in Police Station Barpeta Road vide FIR (Annexure-1 to the affidavit of Mr. Mukherjee). Mr. Mukherjee has further deposed that another IED explosion occurred around 12:29 PM on 30.10.2008 in front of the Choudhury Market Complex under Barpeta Road township, in which 7 persons died on the spot and some died later during treatment and many more were injured. A case No. 261/08 was registered in Police Station Barpeta Road with regard to this explosion.

16. PW-5, Mr. Mukherjee has further testified in his evidence affidavit that during investigation, it was revealed

that the NDFB cadres were involved in both the aforementioned bomb blasts and commission of crime. One accomplice of NDFB, Sri Anup Boro was arrested and he divulged the involvement of NDFB cadres and gave names of several listed NDFB cadres like Rajen Goyari, Mridul Goyari, B. Mudoi and B. Bidai. These names of listed NDFB cadres were given by accused Anup Boro in his statement under Section 164 recorded by the Judicial Magistrate. As per PW-5, the case diaries of cases No. 261/08 and 262/08 of PS Barpeta Road, reveal the involvement of NDFB and its members in twin IED explosions that took place in his jurisdiction.

17. PW-6, Mr. Kalita, has given evidence with regard to 5 incidents of kidnapping and killings that took place in his jurisdiction on 24.02.2007, 27.02.2007, 24.09.2007, 28.05.2008 and 29.07.2008. PW-6 has annexed the copies of FIRs of all these 5 cases along with the copies of the statement recorded by the Investigating Officer during investigation of these cases with his affidavit. He has testified that a perusal of case diaries of all these 5 cases reveal involvement of NDFB and its members in the unlawful activities including killings, assaulting, kidnapping, extortion and illegal possession of arms, etc.

18. PW-7, Mr. Krishan Kumar Sharma, in his affidavit Ex.PW-7/1, has given evidence of several incidents of abduction, murder, etc. that took place in his jurisdiction on



various dates from April 2007 to July 2008. He has testified that on 03.04.2007 at about 12:30 PM one Romesh Narzary aged about 45 years, was murdered at his house by four suspected NDFB cadres and during investigation of this murder case (Case No. 27/07 of Police Station Howraghat), it came to the light that five known NDFB cadres namely, (i) Rudra Basumatary, (ii) Bana Basumatary, (iii) Laichon, (iv) Dokmai and (v) Sri Mar were involved in the incident and were named in the FIR as accused persons.

19. PW-7 has further deposed that on 12.03.2008 one Binda Gour, about 22 years old was abducted by suspected NDFB cadres from Langhin Itapara area in the jurisdiction of Police Station Howraghat. Based on the confessional statement of Bistu Basumatary @ Ranjan Basumatary, Second-in-Command of NDFB for Karbi Anglong District, who was arrested on 23.03.2008 by Dokmoka Police and as led by him, the dead body of Binda Gour was recovered by Dokmoka police on 31.03.2008. The dead body was exhumed in the presence of a Magistrate. A case No. 21/2008 was registered in PS Howraghat with regard to this incident of abduction and killing of above-named Binda Gour. PW-7 has deposed that during investigation and from the statement of witnesses, it was revealed that Binda Gour was killed by the NDFB cadres.

20. PW-7 has also deposed that on the intervening night of 6/7.07.2008 around 12:30 AM, one Robin Basumatary of

Manikpur village had informed the Dokmoka Outpost that when he heard the sound of gun fire, he came out with a torch light and saw some unknown miscreants suspected to be NDFB cadres firing upon him, as a result of which he sustained bullet injuries on his left hand and leg. During investigation, it was revealed that the NDFB group led by one Samar Basumatary was involved in the said incident. One NDFB cadre, namely, Ashu Basumatary @ Ribison was arrested by Dokmoka Police and 20 Bn. CRPF. As per the testimony of PW-7, this arrested NDFB cadre had admitted his involvement in the incident of firing at the complainant Robin Basumatary.

21. PW-7 has further given evidence of the fact that on 13.07.2008, around 7:30 PM, one hand Grenade was lobbed at the back side of the office of Ex- BLT welfare society, Langhin under Howraghat Police Station by some militants which exploded. These militants also indiscriminately fired with automatic weapons at the Ex-BLT welfare society office. As per PW-7, this incident of 13.07.2008 shows that the NDFB cadres are regularly indulging in terrorizing surrendered militants who have come to terms. He has stated in his affidavit that the incident of 13.07.2008 is strongly suspected to be handy work of NDFB cadres and a plan to attack the Ex- BLT camp as reported by unconfirmed intelligence input. According to PW-7, one witness has stated that approximately 11 NDFB cadres were involved in

the explosion that took place on the night of 13.07.2008 at the backside of the office of Ex-BLT Welfare Society, Langhin.

22. PW-7 has further stated in his affidavit that on 06.05.2007, acting on a tip-off that certain suspected NDFB cadres were taking shelter in Panbari, Beltola, Mithiphang and Artungso Kacharigaon areas, he along with his staff had conducted raid/search operations in the said areas and picked-up the NDFB militants from there, namely, (i) Sri Bharat Basumatary (ii) Sri Moheswar Boro @ Tutu (iii) Sri Logan Basumatary (iv) Sri Swapan Boro (v) Sri Siraj Moshahari and (vi) Sri Babulal Hasnu and he brought all of them to Police Station Diphu where the Police recovered incriminating documents from their possession relating to NDFB militants. The incriminating documents recovered by the Police include 10 Extortion notes, one diary containing voucher statement, expenditure etc. and a mobile handset with Sim No-9854415516, 9435574296 from NDFB militants, namely, Bharat Basumatary and Moheswar Boro respectively. A case No. 84/2007 with regard to this incident of 06.05.2007 was registered in the jurisdiction of PS Diphu on 08.05.2007.

23. PW-7, Mr. Sharma, has also given evidence of some other incidents in his affidavit. He has stated that on 15.03.2008, around 12:30 PM, acting on a tip-off about one Sunil Rusit, being called at a place near a bridge at Panbari

Diphu under Police Station Diphu by suspected NDFB militants, Diphu police rushed to that area and on seeing the Police, three suspected NDFB militants fled away towards the nearby hills taking the cover of thick jungles and on seeing the Police chasing them, they started firing upon the Police party. In retaliation, the Police also returned the fire as a result of which one unidentified suspected NDFB cadre got killed in the exchange of fire and the other two managed to escape. During search of NDFB cadres, the Police recovered one '32 Pistol loaded with one round live ammunition, one Chinese hand Grenade and one mobile phone from the possession of the slain unidentified suspected NDFB cadre and these articles were duly seized as per seizure list annexed to the affidavit of PW-7 as Annexure 18(Colly.). The slain militant was later identified as Gupen Swargiary of Panbari village. A case no.47/08 with regard to the aforesaid incident of 15.03.2008 was registered in the PS Diphu.

24. On 12.04.2008, around 6:15 AM, acting on an intelligence tip-off about the probability of NDFB cadres coming to collect money which had been demanded from one Sri J.K Borman, Principal, Diphu Govt. Higher Secondary School, Diphu, the Officer in Charge of Diphu Police Station along with his staff laid an ambush at the boundary side of the said School near the house of one Gonesh Deka and others. While the party was at ambush, two suspected NDFB

cadres came along the route and on seeing the Police personnel in plain clothes, the Extremist cadres opened fire aiming to the plain clothed-men suspecting them to be Police. Police also gave a chase to apprehend them and shot dead one of the two extremists in self-defence who tried to lob a Grenade to the Police. The other extremist managed to escape taking the cover of nearby habitations. Later on, the Police recovered one Chinese hand Grenade and one mobile hand set (Nokia-5300) No-9859381016 from the pocket of the deceased militant. During search of the Place of Occurrence, Police also recovered another Hand Grenade (Chinese make) and six empty cases suspected to be M-20 ammunition, from the Place of Occurrence and these articles recovered from there were duly seized as per seizure list annexed as Annexure-21 (Colly.) to the affidavit of PW-7. A Case No. 66/2008 with regard to the aforesaid incident of 12.04.2008 was registered at Police Station Diphu.

25. On 25.04.2008, around 6:00 AM, again acting on a tip-off about suspected NDFB ultras coming to collect extortion money from one Paniram Bey of Englong Cherop, an employee of PWD (Housing) near Chandra sing Teron High School, the Police of Diphu Police Station laid a trap at the nearby area and was able to apprehend two women extortionists namely (1) Smt Muskan Choudhuri and (2) Smt Mampi Roy, when they came to collect the demanded

money from Sri Paniram Bey. During investigation, it was discovered that suspected NDFB militants had demanded an extortion money of Rs 2 Lakhs from one Paniram Bey through Mobile No- 9854422208 and these two women extortionists were nabbed when they came to collect extortion money in the name of NDFB. The Police is stated to have recovered one Nokia mobile handset with Sim No- 9854422208 which was allegedly used in demanding extortion money from the aforesaid person. This incident relates to Case No. 75/2008 of PS Diphu.

26. On 05.08.2008 at wee hours around 2:00 AM, 5<sup>th</sup> Bihar Regiment camp/Dhansiri, while conducting search operation at Doldoli area under the jurisdiction of Police Station Diphu, apprehended two suspected NDFB cadres, namely, (1) Pobitra Basumatary and (2) Abita Mushahari from a place near Doldoli Railway Station and recovered one 9 mm Revolver loaded with 4 rounds of ammunitions from their possession. This incident refers to Case No. 143/2008 under Section 25(1-B)/35 of Arms Act, PS Diphu.

27. On 03.07.2008 based on source information about the movement of NDFB militants at Bengenaati under Bokulia Police Station, E/Coy 20 Bn. CRPF Camp/Langhin conducted search operation in that area from 4:00 AM onwards and was able to apprehend one known and wanted NDFB cadre namely, Ajoy Basumatary @ Binda who at that time was holding the rank of Corporal of NDFB and also recovered 2

Mobile handsets (Nokia and Spice) with one charger and one Motor cycle TVS Star without registration. This incident refers to Bokulia Police Station Case No. 20/08 Under Section 120(B)/121/121(A)/122 IPC, R/W sec-10/13 UA(P) Act.

28. PW-7, Mr. K.K. Sharma, has deposed in his affidavit Ex.PW-7/1 that all the above referred incidents, according to him, establish the involvement of NDFB cadres in large illegal/criminal activities against the spirit of the ceasefire agreement and show that the NDFB members are still continuing their secessionist activities by violating the terms and conditions of ceasefire. He has annexed copies of all the FIRs and the documents prepared by the Police during investigation of the above referred cases with his affidavit filed by him in his evidence.

29. PW-8, Mr. Nitul Gogoi has testified in his affidavit, Ex.PW-8/1, that on 26.02.2007, around 5:30 PM, the police of Police Station Howraghat along with two commandos of CRPF had rushed to Beltola Bazar on getting a secret information regarding collection of money from the businessmen of Beltola Bazar by some armed youths showing fear to their lives. On arriving at Beltola Bazar, the raiding party immediately cordoned the Bazar and in the meanwhile, 3 armed youths started firing aiming to the Police party indiscriminately and in self-defence, the Police also retaliated the firing. The firing went on for about 15

minutes. After the incident, one youth was found dead at the spot in Beltola Bazar. However, his two associates were stated to have managed to flee away from the spot. During the search, the Police was stated to have recovered one Chinese grenade, one mobile phone, one pocket diary from the possession of the deceased militant and these articles recovered from the spot were seized vide seizure lists annexed as Annexures 2, 3 and 4 to the affidavit of PW-8. PW-8 has further stated that in this incident of 26.02.2007, 2 NDFB cadres, namely, Pulin Barman and Ranjay Basumatary were arrested and they both along with the deceased Santosh Basumatary were identified as NDFB militants by the independent witnesses/members of the Police party. This incident refers to Kaki Police Station, Case No. 11/2007 u/S.387/307 IPC R/W Section 5 [1][a]/27 of Arms Act and Section 5 of the Explosive Substance Act.

30. PW-9, Mr. Surendra Kumar, has given evidence of the following incidents in his affidavit Ex. PW-9/1. On 21.04.2008, around 5.20 P.M, the complainant Major Sunil Kumar of Assam Rifles, had handed over 5 militant youths, namely [i] Ringkhang Basumatary, [ii] Naba Deka, [iii] Ishrail Doimary, [iv] William Doimary, and [v] Biki Khaklary along with one Fully Loaded Revolver, one 9 mm. Pistol, one Magazine loaded with 6 rounds of ammunition, 2 Motor Cycles, 2 Mobile Phones, 5 SIM Cards, cash and Bhutan currency along with some other incriminating documents,



to the Police of Police Station Missamari under the jurisdiction of Sonitpur District. The apprehended militant youths, arms and ammunition along with other incriminating material, handed over by the complainant Major Sunil Kumar to the Police of Police Station Missamari were allegedly seized by the complainant in an operation carried out by him in Village Basbera on receiving a source information about the movement of some armed youths in Village Basbera on that day. All the above named 5 militant youths, during their interrogation by the Police of Police Station Missamari, were alleged to have confessed that they are cadres of NDFB. In this connection, Case No. 15/2008 U/S 120(B) IPC R/W, Sec. 25(I-A) of the Arms Act was registered against the above named accused persons (militant youths) with the Police of PS Missamari.

31. On 30.04.2008, at 7:00 AM, the complainant, Naib Subedar, I.B. Thapa produced 7 youths, namely, (1) Dharmeswar Basumatary (2) Tapan Doimari (3) Subodh Basumatary (4) Parsuram Basumatary (5) Seelapha Narzary (6) Sanjoy Narzary and (7) Amit Khaklary, to the Police of Police Station Behali. He lodged an FIR with the Police of PS Behali stating that on 29.04.2008, he was at Village Dishiri for area domination duty and during that time he got an information that 7 suspected youths were taking shelter in the house of one Kamal Doimari of Village Dishiri. He searched the said house and apprehended 7 youths handed

over by him to the Police at the time of registration of the FIR. He also stated in the FIR that one Nokia Mobile Phone and cash of Rs. 3570/- were recovered from the persons apprehended by him. The complainant had told the Police in the FIR that the above-named seven persons, apprehended by him had disclosed that they were NDFB cadres and were posted at Village Dishri for organizational works. The amount received from their possession was disclosed to have been extorted from a contractor. This complaint made by the complainant Naib Subedar I.B. Thapa on 30.04.2008 relates to FIR case No. 88/2008 of PS Behali.

32. On 16.06.2008, at 2:45 PM, the complainant Ms. Raimali Khaklari gave a written report to the Police of Police Station Rangapara to the effect that on 15.06.2008 at 6/7 PM, her cousin brother Shri Biru Basumatary along with his friend Shri Pronoy Basumatary were coming from his native village towards Rangapara by a Motor cycle bearing Registration No. AS-12-C/6544. They were way-laid near Urahiloga L.P. School. The NDFB cadre DONDA along with two others stopped the brother of the complainant and Pronoy Basumatary, saying that they wanted to have some discussions with them. Pronoy Basumatary was asked to stay on the spot along with one of the NDFB cadres while Biru Basumatary was removed to another place. Later, the Motor cycle was returned to Pronoy Basumatary on the

same night but Biru Basumatary did not return till writing the FIR on 16.06.2008. The dead body of Biru Basumatary was recovered in a jungle at Village Mainaoshri. This incident refers to Rangapara Case no. 95/08 dated 16.06.2008 U/S 341/365/34 IPC added Section 302/201 IPC. PW-9 has testified that NDFB cadres were involved in the murder of Biru Basumatary.

33. PW-11, Mr. Sayed Ataul Karim, has testified in his affidavit filed in his evidence that on 26.02.2008, at about 12:30 PM, a Police party from Narayanpur Out-Post was executing Naka-checking duty at Narayanpur to check the movement and activities of extremist elements. Around that time, one Indica car bearing registration No. AS-01-X-5629 coming from Lakhimpur side towards Narayanpur was stopped and checked by Police. There were 5 people who were inside the car. During search of the above stated vehicle, one Pistol (USA made, no.2211) along with one magazine, cash of Rs. 78,083.00, 6 mobile phones, 9 Sim card and one camera were seized from the possession of the group. The youths confessed to be active members of banned NDFB organization. It is stated by PW-11 that further investigation in the case revealed that the youths travelling in the Indica Car stopped at the check post, were involved in extortion of money from the people for NDFB organization. The apprehended NDFB members are (1) Punja Basumatary (2) Rajesh Mochahari (3) Bibung

Basumatary (4) Lohiram Swargiary and (5) Binosh Nake.

During investigation, statements of 8 witnesses were recorded and they identified the apprehended persons as members of NDFB cadres and are stated to have corroborated the contents of the FIR being Case No. 65/2008 dated 27.02.2008 U/S 384 IPC, R/W Sec. 25 (1-A) Arms Act and 10 / 13 UA(P) Act.

34. PW-12, Mr. Rana Bhuyan, has deposed in his affidavit Ex.PW-12/1 that in the district of Baksa, members of NDFB are very active and they are indulging in large-scale unlawful and violent activities undermining the authority of the Government and spreading terror among the people and are also targeting the surrendered NDFB activists, Ex-BLT members, civilians, non-Bodos and causing them immense impediments in leading a normal life. It is stated that the inmates of the Designated Camp of NDFB located at Dhanbil, under Barbari Police Station, are indulging in large-scale violence by taking the plea of ceasefire.

35. PW-12 has stated that these NDFB cadres are very frequently found violating the ground rules and they fail to comply the "Standard Operating Procedure", (SOP), formulated and approved by the Joint Monitoring Committee (JMC) for the management of the Designated Camp. As per the testimony of PW-12, the NDFB cadres, staying both inside and outside the Designated Camps, have committed different heinous crimes which amount to unlawful

activities, during the relevant period of time and due to such criminal activities, large number of cases have been registered against them under different Police Stations and quite a number of NDFB cadres were arrested from time to time. PW-12 has given specific evidence in his affidavit with regard to the following incidents of unlawful activities of NDFB cadres.

36. On 07.08.2008, an FIR was lodged by one Sri Phulen Brahma, at Tamulpur Police Station to the effect that on the same day at about 12:30 PM, 4 known NDFB activists namely- 1) Sri Bipul Boro, 2) Sri Ratneswar Boro, 3) Sri Monil Daimary, and 4) Sri Keder Boro had suddenly attacked his brother Sri Somesh Brahma at Village Katribari, while, the victim along with another person was returning home on a motor cycle from Lotibari Market. The victim was shot dead on the spot. Another person, Sri Biswa Goyari, received grievous injury in the said attack and he was shifted for treatment to Guwahati Medical College Hospital, Guwahati. A case No. 134/2008 dated 07.08.2008, U/S 307/326/302/34 IPC, R/W Sec 25 (I-B)/27, Arms Act was registered with regard to this incident of 07.08.2008 with the Police of Police Station Tamulpur.

37. On 18.06.2008, at about 2:00 PM, an FIR was lodged by one Sri Bethal Mushary with the Police of Police Station Tamulpur to the effect that on 17.06.2008 at 7:40 PM, while Sri Raja Basumatary and Sri Bhim Boro were proceeding

back after dinner at the BPF (Youth) Office, Darrangamela, few NDFB Cadres forcefully restrained them in front of N.K Darranga Bazar and killed them by firing at them from sophisticated weapons and after committing the crime, they left the place on Motor cycles towards Bogyajuli area. A Case No. 101/08 U/S 302/34 IPC, R/W sec 25(I-B)/ 27 Arms Act was registered with regard to this incident at Police Station Tamulpur. From the statement of the witnesses recorded by the Investigating Officer during the investigation of this case, it was found that 4 NDFB cadres, namely, (1) Jala Goyari, (2) Abhayan Boro, (3) Sukur Singh Basumatary and (4) Ratan Basumatary, were involved in the murder of Raja Basumatary and Bhim Boro in the incident that took place on 17.05.2008 for which above Case No. 101/2008 was registered on 18.05.2008.

38. On 05.10.2008, an FIR was lodged by one Md. Sarbes Ali with the Police of Police Out Post at Nagrijuli under Tamulpur Police Station to the effect that on that day his wife, Sarbanu Begum (approx. 24) and their son Md. Siraj Ali with his younger brother Md. Manshar Ali were on the way to attend a marriage ceremony at No.2 Pipalasi village, then near Anthaibari village, 2 unknown Boro youths gagged his wife. His younger brother Manshar Ali managed to escape. Later Manshar Ali took some neighbors and came there where he found Sarbanu Begum and her son lying cut with a sharp weapon. Later at about 1200 hrs he came to know

that in a joint operation of Police and Army, 2 persons were arrested who both were identified by his younger brother Manshar Ali as persons involved in the killing of complainant's wife and his son and the names of these arrested persons as mentioned in the affidavit of PW-12 are (1) Jabrang Boro and (2) Dahar Boro. A Case No. 169/08 u/s 302/34 IPC was registered with regard to this incident at Police Station Tamulpur and during investigation of this case, it was revealed from the statement of witnesses that both the above named persons arrested by the Police were members of NDFB.

39. PW-13, Mr. Bir Bikram Gogoi, in his affidavit Ex.PW-13/1 filed before the Tribunal has given evidence of three crimes that took place in his jurisdiction and these crimes stated by him in his affidavit are as follows:

40. On 03.06.2007, a FIR was lodged by one Sri Romesh Boro, to the effect that on 02.06.2007 at about 8:00 PM, about 7/8 NDFB militants had entered his house and picked up his brother Shri Suresh Boro, and brutally assaulted him with rod, dao and lathi, and left him on the road in a critical state. Later, on the way to Guwahati, Suresh Boro (complainant's brother) succumbed to his injuries. During investigation, two bamboo lathies and a piece of iron rod were recovered by the Police from the place of occurrence which were suspected to be used by the accused persons in commission of the crime. During the course of investigation,

it was found that the NDFB militants were directly involved in the case, which was also, corroborated by the statements of various witnesses. This crime refers to Merapani Case No. 43/07 dated 03.06.2007, U/S 147/452/325/326/365/302 IPC.

41. On 08.05.2007, 2 NDFB militants are stated to have come to Haldhibari village and demanded a payment of Rs.20000/- from the shopkeepers and villagers. Next on 16.05.2007 at about 6 AM, the said NDFB members came to the house of the complainant Shri Babu Kumar S/O Shri Kulu Kumar and demanded the payment of the said amount from him. Then the complainant raised hue and cry, and because of that some people of the village gathered and caught the two NDFB members who on questioning, were identified as (1) Shri Jiten Basumatari, and (2) Shri Ramesh Khakhlari. Both these accused persons apprehended from the spot, during their interrogation divulged that they are the hardcore cadres of the banned NDFB organization. On the statement of the witnesses recorded by the Investigating Officer in this case, it was revealed that both the above-named persons were members of the banned NDFB organization and they were continuing their unlawful activities to create panic in the area. This refers to Sarupathar P.S. Case No. 56/07 dated 16.05.2007 U/ 384 IPC. R/W sec. 10/13 UA (P) Act.



42. On 13.12.2008, one Shri Deepak Kumar Tiwari, Sector Commander of 155 Bn. CRPF, Rangapani lodged an F.I.R. to the effect that on the same day on receipt of an information about few suspected militants entering into the DAB area (Disputed Area Belt of Assam –Nagaland Border) from Dimapur to "A" sector towards Pohoto village, the information was immediately shared with SDPO Sarupathar, O/C Sarupathar and senior Officers of CRPF. After getting the information, the above officers with available forces rushed to Pohoto village at about 1120 Hrs. At that time, one auto-rickshaw bearing Registration No. NL-07/3673 was coming from Dimapur side. When the auto-rickshaw was signalled to stop by the Police-CRPF party, the passengers of the said auto-rickshaw, three unknown youths, jumped off from the auto-rickshaw and opened fire upon the Police-CRPF party. On retaliation and for self defence, the Police-CRPF party had to open fire upon them. The firing was continued for 15 minutes and as a result one youth, who was later on identified as Joy Charan Musahary, S/o Bijoy Musahary, a hardcore NDFB militant sustained bullet injuries on his person. He was immediately shifted to Bokajan PHC for treatment. The other two NDFB militants were able to flee away under the cover of Jungle. During search, one .32 pistol made in Italy and 3 live rounds of ammunition were recovered. After preliminary treatment at Bokajan PHC, the injured Joy Saran Musahahary was

referred to Golaghat Civil Hospital for better treatment. On arrival, the doctor of Civil Hospital Golaghat declared him brought dead. During investigation, it was found that Joy Saran Mushahary, S/o Bijay Musahahary was an active member of NDFB and area commander of Golaghat District. His other two associates, namely Amar Basumatary and Deblai both were also active members of NDFB. During investigation, it also appeared that the deceased and absconding NDFB militants were involved in various kidnapping cases. This refers to Sarupathar P.S. Case No. 121/08 dated 13.12.2008 U/S 120 (B)/353.307 IPC. R/W sec. 25 (1) (a) /27 Arms Act. R/W sec. 10/13 UA (P) Act.

43. PW-13 has testified in his affidavit filed by him in his evidence that he has seen the case diaries of all the three criminal cases and on perusal of the same, according to him, the case diaries would reveal involvement of NDFB members in the unlawful activities including extortion, kidnapping, murder, illegal possession of arms and ammunitions, attempt to murder, assault etc. thereby violating the ground rules for suspension of operation agreed between the Government of India, Government of Assam and NDFB on 01.06.2005.

44. PW-14, Mr. Anand Prakash Tiwari, in his affidavit Ex.PW-14/1 filed by him in his evidence before the Tribunal

has supported the evidence given by the Superintendents of Police of other districts of State of Assam. He has also deposed in his affidavit that the NDFB organization is very active and its members are indulging in large-scale unlawful activities as well as waging war against the State.

45. PW-14, Mr. Tiwari, has cited certain instances/ cases in his affidavit in which members of NDFB were found involved in unlawful activities. These instances/cases cited by him are as follows :-

(i) Odalguri PS Case No. 24/2008 u/s 147/148/341/353/ 387/435/427 IPC. Date of Occurrence : 29.02.2008, Time: 7:30 AM, Place of Occurrence : Golandi bridge, Odalguri. It is stated that on the date and time of occurrence of this case, accused, Hulunga Narzary @ Habila Narzary who was an inmate of NDFB camp situated near Gohpur Police Station, District Sonitpur, along with 10/11 other persons had wrongfully restrained the complainant to proceed on Government duty and burnt his motor cycle after forcefully snatching it.

(ii) Odalguri Case No. 26/08 u/s 147/148/448/427/353/224/325 IPC, Date of Occurrence : 01.03.2008, Time: 2:30 PM, Place of Occurrence : PSI Court, Odalguri, Complainant:

ASI Uttam Borah of Odalguri Police Station. It is stated that on the date of occurrence, while the accused person namely Hulunga Narzary @ Habila Narzary was taken to PSI court Udalguri, about 20 NDFB cadres criminally trespassed inside the PSI court and forcefully taken away the arrested accused. Later on, he was again arrested. This case is stated to be pending for arrest of other accused persons.

- (iii) Mazbat PS Case No. 32/08 u/s 25(I)(A) Arms Act. Place of Occurrence : Merabil, Date of Occurrence : 15.05.2008, Time : 10:00 PM, Date of Reporting : 16.05.2008 at 8:00 AM. It is stated that on the date of occurrence, 46 Bn. Assam Rifles camp Mazbat apprehended 2 NDFB cadres, namely, (1) Sri Dwrwmsa Basumatary and (2) Sri Jakhan Narzary and recovered one 7.65 mm auto pistol with magazine, 7.65 MM live ammunition (5 Nos.), 1 Bajaj Pulsar Motor cycle no. AS-01/AC-1020, one Mobile phone with SIM Card, their identity cards, cash of Rs. 3000/- from their possession. Both the above accused persons were arrested from the spot and the

case against them is stated to be pending under investigation.

- (iv) Mazbat PS Case No. 60/08 u/s 387 IPC, Date of Occurrence : 10.09.2008, Time : 1:30 AM, Place of Occurrence : Jawalia Centre, Orang Basti, Date of Reporting : 10.09.2008 at 11:00 AM, Complainant: Captain C. Shibu John, 'E' Coy. 46 Bn. Assam Rifle, Camp - Mazbat, District Odalguri, Accused : - Hogam Swargiary. Brief of this case is that on 10.09.2008, the complainant received an information from reliable source regarding carrying out extortion by NDFB cadres in general area at Place of Occurrence and the complainant along with 'E' & 'C' Coy of 46 Bn. Assam Rifles conducted search operation and apprehended the above noted accused person and recovered one Khukri, 5 Extortion receipts, 4 books containing details of amount. This case is stated to be still under investigation.

46. PW-14, Mr. Tiwari, has testified on the basis of case diaries of the above cases that NDFB organizations and its members are involved in unlawful activities including firing

towards the public, illegal possession of arms and explosives and waging war against the State etc .

47. PW-15, Mr. Partha Sarathi Mahanta, in his affidavit Ex. PW-15/1 has deposed that in his District, i.e., District of Dhubri, the members of NDFB are very active and they are indulging in large-scale unlawful activities undermining the authority of the Government and spreading terror among the people as well as waging war against the State. Mr. Mahanta has further testified that the NDFB cadres are also targeting the surrendered Boro Liberation Tiger (BLT) cadres and causing them immense impediment in leading a normal life. He has cited three instances in his affidavit in which according to him, members of NDFB are involved. The cases cited by him in his affidavit are as under :-

- (i) On 12.03.2008, at about 2:00 PM, a group of NDFB youths armed with deadly weapons came to the Forest Inspection Bungalow at Sapatgram where some Ex-Bodo Liberation Tiger (BLT) and members of youth wing of Bodoland Peoples Front (BPF) were staying and opened 8/10 rounds of fire in the air and also set fire to the Forest Inspection Bungalow and as a result the Forest Inspection Bungalow was completely gutted. During investigation,

from the statement of the witnesses, it was revealed that the NDFB cadres, namely, (1) Kamal Brahma, (2) Sri Kumanta Brahma, (3) Jasush Brahma, (4) Prano Brahma, , (5) Mukkel Sangma, alongwith 40/45 other cadres were involved in the above incident and it is stated that the investigation is on to trace the culprits. This refers to Bagribari P.S. Case No. 32/08 dated 12.03.2008 u/s 147/148/149/447/436/427 IPC R/W. Section 25 (I) (A)/27 Arms Act.

- (ii) On 14.07.2008, on receipt of a source information regarding movement of NDFB in Bagribari area, Police and Army personnel of 21 JAT conducted search operation/ambush and around 2:17 P.M. 3 NDFB cadres, namely, (1) Jaydeep Dey, (2) Kaniram Basumatary and (3) Swajal Sarkar, were apprehended near Mahamaya Mandir under Bagribari P.S. alongwith a Santro car and one 7.65 mm auto pistol and two rounds of live ammunition recovered from the possession of Sri Jaydeep Dey (inmate of the Santro car). Two other NDFB cadres, namely, Goda Narzary and Lauri

Brahma were also apprehended with a motorcycle at the same place when they tried to flee on seeing the Police and Army. During investigation, one 7.65 mm auto pistol and two rounds of live ammunition, Santro car, Motor cycle (Bajaj Pulsar), two Mobile phones and a cash of Rs. 2000/- were seized. The accused Jaydeep Dey during his interrogation by the Investigating Officer admitted that he is a NDFB cadre and possessed the pistol and ammunition seized from him as stated above. It is stated that the other accused persons arrested from the spot had also confessed to their guilt in this case. This refers to Bagribari P.S. Case No. 123/08 dated 14.07.2008 u/s 384 IPC R./W Section 25 (i) (A)/27 Arms Act.

- (iii) On 12.08.2008, at about 2:00 PM, on receipt of a source information that some NDFB cadres are camping at Bhelakoba Reserve Forest (hilly area) under Sapatgram Out Post, SDPO Bilasipara, C.I. Bilasipara, O/C Bilasipara P.S. alongwith staff and Army personnel of 21 JAT jointly conducted a search operation at



**Bhelakoba forest area.** During search operation, police apprehended NDFB cadres , namely, (1) Alle Brahma (2) Sri Markhow Basumatary (3) Sri Mokley Goyari (4) Sri Sibru Basumatary (5) Sri Danshaw Khaklary (6) Sri Jiten Basumatary and (7) Sri Kharkhu Basumatary. On being led by Danshaw Khaklary and Jiten Basumatary among the above apprehended boys, 1 AK-56 Rifle, 10 rounds of live ammunition and 1 motorcycle 'Hero Honda Glamour' were recovered from the said temporary camp and seized by the police at the spot. This refers to Bagribari P.S. Case No. 207/08 dated 12.08.2008 u/s 25 (1) (A) Arms Act.

Section 10/13 of the UA(P) Act was added, later on, in all the above mentioned three cases, as per permission for such addition granted by the Magistrate vide order dated 17.02.2009, and a copy of the order of the Magistrate dated 17.02.2009 is annexed as Annexure 'J' (Colly.) to the affidavit of PW-15.

48. PW-3, Ms. Banya Gogoi, is the Superintendent of Police, Special Operation Unit (SOU), Assam and she has

stated in her affidavit Ex.PW-3/1 that she, in discharge of her official duties, monitors the terrorist activities in the entire State of Assam and receives reports from Senior Superintendent of Police and all the Superintendents of Police of various Districts regarding the unlawful acts of terrorist organizations including the banned NDFB operating in the State of Assam. She has deposed that on the basis of these information, she submits her reports to the Government of Assam and also shares information with SSPs and SPs so that timely action can be taken to prevent unlawful activities of terrorist organizations including NDFB.

49. As per testimony of PW-3, Ms. Gogoi, there was an agreement of Suspension of Operation (SoO) executed on 01.06.2005 between the Government of India, Government of Assam and NDFB for a period of 6 months, and this agreement has been extended in phased manner with an aim to have lasting peace in the region. Ms. Gogoi has deposed that in spite of the aforesaid agreement, NDFB continues to violate the ground rules for suspension of operation as agreed on 01.06.2005 and is actively waging war against the State. In spite of the above agreement, the NDFB continued its secessionist and violent activities with a view to establish a sovereign Boroland by stepping up its acts of terrorist violence including attacks on

Army/Police/Security Force personnel and law abiding civilians and destruction of public and private properties. The NDFB outfit has established a number of camps/hide outs in Sherpur District and Chittagon hill tracks of Bangladesh bordering with Meghalaya and Mizoram respectively. The establishment of camps in foreign soil facilitated the training of the NDFB cadres which remained unchecked. This has facilitated the continuance of their depredatory activities in the State after imparting training to the newly recruited cadres in the foreign soil. The existence of similar camps of other North-Eastern militant outfits like ANBC, HNLC, NSCN(IM), ATTF and NLFT in close proximity to the NDFB camps in Bangladesh helps the outfit in the transshipment of arms. The unholy nexus of NDFB with HNLC of Meghalaya and ULFA is still continuing. They have established a camp on Assam-Meghalaya Border shared by Ribhoi District of Meghalaya which is within the vicinity of Guwahati City. In 2008, from the said place, they jointly conducted operation in Guwahati City like kidnapping of businessman for realizing ransom. Similarly, the arrest of KLO (Kamatapur Liberation Organization) Activist, Ramnath Ray @ Babu by West Bengal Police (September 9, 2008) brought the fact to the light that new KLO recruits underwent arms training in an NDFB Camp located at

Mashim Khatal Training Camp and that they were imparted training by the senior leaders of KLO and NDFB. The latest two batches of KLO cadres were imparted training in 2008 at the NDFB Camp at Mashim Khatal of Bangladesh by the NDFB instructors. The NDFB leadership stationed in Bangladesh including Chairman Ranjan Doimary is stated to be still espousing the cause of establishment of a sovereign independent Boroland. Ranjan Doimary (Chairman, NDFB) urged trainees in a passing out parade held in Khagrachari camp of Bangladesh to sacrifice their lives for establishing independent Boroland. Gobinda Basumatary, the General Secretary of NDFB in an open meeting of "All Bodo Peace Forum" in Dhemaj district held on 28.02.2007 is alleged to have stated that the aim and objective of NDFB is to liberate and save Bodo people and secede from the Union of India. PW-3, Ms. Gogoi, has annexed a copy of Compact Disc (CD) along with her affidavit to show the passing out parade of NDFB cadres in Bangladesh held in the month of August, 2007. Ms. Gogoi has stated that the investigation into the 9 serial bomb blasts that took place on 30.10.2008 in several places of Guwahati, Barpeta Road, Bongaigaon and Kokrajhar where 89 innocent persons lost their lives and 593 were injured, revealed the clear involvement of NDFB cadres in the blast. According to her, these cases

have now been handed over to the CBI for further investigations vide Government of Assam Notification No. PLA.633/2008/17 dated Dispur, 16.12.2008. PW-3, Ms. Gogoi has also deposed that the NDFB members were found involved in issuing demand letters to the different persons/organizations for extortion of funds. The modus operandi of collection of money by the NDFB cadres is euphemistically called "contribution" or "donation" or "financial help", which is stated to be nothing but a tactical move of extorting money. The NDFB is stated to be still continuing its recruitment drive and recruited a good number of youths from different parts of the State. The new recruits are sent to Bangladesh in batches for undergoing training in handling of arms and explosives, etc. According to PW-3, the NDFB organization continues to indulge in various unlawful activities including murder, extortions, bomb blasts, possession of illegal arms, ammunition and explosive materials, creating terror in the mind of non-Boro populace, with a view to disrupt the sovereignty and integrity of India and to create a deep sense of insecurity among the people. During the period from 23.11.2006 to 22.11.2008, a total of 138 persons are stated to have been killed by NDFB and 656 persons are stated to have received injuries in their murderous attempts. The NDFB

organization is stated to have committed 176 incidents of violence. They also kidnapped 20 persons for ransom. It is because of these facts stated by PW-3 in her affidavit, she has justified the declaration of NDFB as an unlawful organization vide notification dated 23.11.2008 as according to her, the said declaration is necessary to curb and control the unlawful activities of NDFB which is detrimental to the sovereignty and integrity of India.

50. PW-2, Mr. S.K. Roy, Joint Secretary, Government of Assam, Home & Political Department and PW-10, Mr. R.R. Jha, Director to the Government of India, in the Ministry of Home Affairs, New Delhi, in their separate affidavits Ex. PW-2/1 and Ex. PW-10/1 respectively have justified the Notification in question, by which the NDFB has been declared as an unlawful organization stating that the said declaration is necessary to curb and control the unlawful activities of NDFB which is detrimental to the sovereignty and integrity of India. Both these witnesses have in fact corroborated the testimony of the Police witnesses referred above on all material aspects of the matter and, therefore, the contents of their affidavit are not specifically referred herein to avoid repetition.

51. The NDFB, in opposition to the Notification banning their organization have filed three affidavits of Sri

B.Swmkhwr, General Secretary of the NDFB, Sri I.Damini, Home Secretary of the NDFB and Sri B.K.Olongbar, Education Secretary of the NDFB. Their affidavits have been exhibited as Ex.DW-1/1, Ex. DW-2/1 and Ex. DW-3/1 and are on similar lines. In their examination-in-chief all the three defence witnesses have stated that the Boro people, which are of the Sino-Tibetan origin of the Mongoloid stock, once ruled throughout the Brahmaputra and Barak Valley extending to some parts of Assam, Tripura, North Bengal, North Bihar and some parts of Nepal and Bangladesh having a distinct political and socio-cultural entity. They further stated that since the British invasion and annexation of the Boro kingdom they lost their sovereign territories and after the independence of India in 1947, the Boro people lost everything, their dignity, honour and above all territories and sovereignty. They stated that the Government of India has totally shattered the socio-economic and political structure of the Boro people. They have further stated that the Boro people being the indigenous people of North East India as per Article (A3) of the UN Declaration on the Rights of the indigenous people, have the right to self-determination and freely determine the political power and freely pursue their progress for economic, social and cultural development. But the

Government of India has failed to honour its constitutional obligation as guaranteed under Article 38 of the Constitution of India. They stated that in the backdrop of this, the Boro Security Force was formed on 3<sup>rd</sup> October, 1986 and thereafter in a meeting of the General Council of BSF it was re-christened as the National Democratic Front of Boroland. They stressed that the ideology and objective of the NDFB is to liberate Boroland from colonialist oppression and establish a democratic socialist society to promote liberty, equality and fraternity and to strive for social economic reformation and protect and safeguard the natural resources of their land.

52. The witnesses of the NDFB have further stated that there was an end from their side to the hostilities as their organization agreed to a political negotiation by signing an agreement of truce on 25<sup>th</sup> May, 2005 called the Suspension of Operation (SoO) with the Government of India and the Government of Assam. As per this agreement effective since 1<sup>st</sup> June, 2005 which is continuing till date, the NDFB has shunned the path of violence and remained committed to solve the various problems faced by them within the framework of Constitution of India. Their cadres are staying in the three designated camps of Sabkaithi in Odalguri



District, the Khumguri (Serfanguri) in Kokrajhar and Dhanbil (Barbari) in Baska Districts of Assam, which are being maintained and supervised by the Government of Assam. They stated that the Government is falsely implicating its members in the violent and unlawful activities being carried out by other anti-social elements. They categorically denied the allegation that their organization was involved in the communal clashes in the District of Odalguri and Darrang on 3<sup>rd</sup> October, 2008 and the bomb blasts which took place on 30<sup>th</sup> October, 2008 in Guwahati. They stated that their organization is not at all maintaining close nexus with the militants outfits viz, ULFA, NSCN etc and they are trying their level best to follow the Ground Rules in force. The witnesses made a strong plea that sufficient cause did not exist for declaring their organization as an unlawful association under Section 3(1) of the Act.

53. I have heard the arguments of Mr. A.B. Chowdhury, learned senior counsel who appeared on behalf of the NDFB organization and of Mr. Sanjeev Bhandari, Advocate who appeared on behalf of Central Government and also of Mr. J.R. Luwang, Standing Counsel for Government of State of Assam. I have also gone through the written arguments filed by the counsel on both sides and have given my anxious consideration to the same.

54. The learned counsel appearing on behalf of the Central Government and the Government of State of Assam, have argued that the Notification dated 23.11.2008 by which the NDFB organization was declared as an unlawful association, be confirmed by this Tribunal because according to them, their witnesses have proved that the NDFB organization, even after ceasefire agreement of 2005, had continued to indulge in various unlawful criminal activities during the last two years and, therefore, according to them, there were sufficient reasons with the Government to declare the NDFB organization as an unlawful association vide Notification dated 23.11.2008 sent to this Tribunal for adjudication.

55. On the other hand, Mr. Chowdhury, learned senior counsel appearing on behalf of the NDFB organization, had argued that there is no legally acceptable evidence on record to prove the existence of sufficient reasons for declaring the NDFB organization as an unlawful association. Mr. Chowdhury had argued that no credence can be given to the police witnesses or the Government officials examined on behalf of the Government as the affidavits filed by them in their evidence have not been verified in accordance with the provisions contained in Order 6 Rule 15 of the Code of Civil Procedure, 1908 which provides "the person verifying the pleadings shall specify by reference to

the numbered paragraphs of the pleadings, what he verifies of his own knowledge and what he verifies upon information received and believed to be true." The argument of Mr. Chowdhury was that since all the witnesses examined by the Government have admitted in their cross-examination that the verification clause contained in their affidavits does not state as to which paragraphs of their affidavits are true and correct to their personal knowledge and which paragraphs are believed to be correct on information derived from the records, no reliance or credence should be placed by the Tribunal on the evidence contained in their affidavits. Mr. Chowdhury had further argued that since all the documents annexed by the witnesses of the Government are only photocopies of their originals, no reliance or credence should be placed by the Tribunal on such photocopies as according to him, no foundation is laid by the Government for admissibility of secondary evidence. It was submitted that the documents annexed with the affidavits of the witnesses of the Government, even otherwise, cannot be used or acted upon by the Tribunal because the author of these documents have not been examined before the Tribunal. According to the learned senior counsel appearing on behalf of the NDFB organization, none of the witnesses examined by the

Government was able to withstand the test of credibility when they were subjected to cross-examination and, therefore, according to him, no reliance should be placed on their testimony while adjudicating the Notification dated 23.11.2008 under adjudication by the Tribunal. Further argument of learned senior counsel appearing on behalf of the NDFB organization was that reliance on the witnesses of the Government cannot be placed also for the reason that various criminal cases registered during the last two years suspecting the involvement of the NDFB cadres were not investigated by a Police Officer of the rank of Deputy Superintendent of Police as required under Section 43 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967. It was submitted by Mr. Chowdhury that the Notification dated 23.11.2008 under adjudication be cancelled by this Tribunal for want of legal admissible evidence in support of the said Notification.

56. I have carefully scanned, weighed and evaluated the evidence for and against the Notification dated 23.11.2008 produced before me by both sides.

57. Clauses (o) and (p) of Section 2 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 contain definitions of 'unlawful activity' and 'unlawful association' respectively, and they read as follows :-

“(o) “unlawful activity”, in relation to an individual or association means any action taken by such individual or association (whether by committing an act or by words, either spoken or written, or by signs or by visible representation or otherwise), —

- (i) which is intended, or supports any claim, to bring about, on any ground whatsoever, the cessation of a part of the territory of India or the secession of a part of the territory of India from the Union, or which incites any individual or group of individuals to bring about such cessation or secession.
- (ii) which disclaims, questions, disrupts or is intended to disrupt the sovereignty and territorial integrity of India; or
- (iii) which causes or is intended to cause disaffection against India;”

“(p) “unlawful association” means any association, —

- (i) which has for its object any unlawful activity, or which encourages or aids persons to undertake any unlawful activity or of which the members undertake such activity; or
- (ii) which has for its object any activity which is punishable under Section 153A or Section 153B of the Indian Penal Code (45 of 1860), or which encourages or aids persons to undertake any such activity, or of which the members undertake any such activity;

Provided that nothing contained in sub-clause (ii) shall apply to the State of Jammu & Kashmir;”

58. It is clear from the above definitions that an ‘unlawful activity’ defined in clause (o) means ‘any action’ taken of

the kind specified therein and having the consequences mentioned. In other words, 'any action' taken by such individual or association constituting an 'unlawful activity' must have the potential specified in the definitions. Determination of these facts constitute the foundation for declaring an association to be unlawful under sub-section 1 of Section 3 of the Act. Clause (p) defines 'unlawful association' with reference to 'unlawful activity' in sub-clause (i) thereof, and in sub-clause (ii) the reference is to the offences punishable under Section 153-A or Section 153-B of the Indian Penal Code. In sub-clause (ii), the objective determination is with reference to the offences punishable under Section 153-A or Section 153-B of the IPC while in sub-clause (i), it is with reference to 'unlawful activity' as defined in clause (o). These definitions make it clear that the determination of the question whether any association is, or has become, an unlawful association, justifies such decision and the determination should be that 'any action' taken by such association constitutes an 'unlawful activity' which is the object of the association.

59. The NDFB (originally known as Boro Security Force) was formed on 03.10.1986 with the avowed aim and objectives of liberating the Boro inhabited areas of Assam from India and to form an independent and sovereign

**Boroland through armed struggle. The aims and objectives of the NDFB are :**

- i) To liberate Boroland from the Indian expansionism and occupation;
- ii) To free the Boro nation from the colonialist exploitation, operation and domination;
- iii) To establish a democratic, socialist society to promote liberty, equality and fraternity;
- iv) To uphold the integrity and sovereignty of Boroland.

60. The NDFB organization had entered into an agreement for 'Suspension of Operation' (SoO) with the Government of India and Government of Assam initially for one year w.e.f. 01.06.2005. [This agreement for Suspension of Operation (SoO) will hereinafter be referred to as the 'ceasefire agreement of 2005'.] The ceasefire agreement of 2005 which was initially for one year effective from 01.06.2005 was extended from time to time and last such extension was granted on 06.01.2009. The ceasefire agreement of 2005 continues even today. The copies of agreed ground rules of Ceasefire Agreement are Annexure 'C' and Annexure 'D' at pages 32 to 36 of the affidavit of Mr. B. Swmkhwr, first witness of NDFB organization. A perusal of Annexure 'C' and Annexure 'D' referred above would show

that the NDFB organization, while entering into the Ceasefire Agreement with the Government, had agreed to maintain peace and not to move around with arms or in uniform. The NDFB organization had further agreed that its members/cadres will stay in the Designated Camps and will not move out from the Camps without authorization of the Camp Commander.

61. The case of the Government is that despite the ceasefire agreement of 2005, the NDFB cadres have not participated in the peace talks and their leaders have exhorted the cadres to remain in readiness to resume armed struggle in case the Government of India rejects their demand for sovereignty. Further case of the Government is that the NDFB organization continues to be active in the Boro-dominated areas of Kokrajhar, Chirang, Odalguri, Baska, Barpeta, Nalbari, Darrang, Kamrup, Sonitpur, Bongaigaon and Karbi Anglong Districts of Assam. It was submitted that the movement of its cadres was also noticed in the upper Assam district of Golaghat, Lakhimpur, Dhemaji and Dibrugarh. During the last two years, several criminal cases in which involvement of NDFB cadres was suspected, were registered in various districts of State of Assam and the arrested insurgents, during their interrogation in those cases, have disclosed that the NDFB



organization has links with the Pakistan Intelligence Agencies and their cadres were trained in Bhutan, Bangladesh and other foreign territories.

62. The NDFB organization was banned as an unlawful association by the Government, for the first time, vide Notification dated 23.11.1992 and the said ban thereafter continued since then till date, through issuance of fresh Notification after every two years. The last Notification dated 23.11.2006 (Notification prior to Notification of 23.11.2008 under adjudication) was confirmed by the Tribunal, then presided over by Justice Pradeep Nandrajog vide order dated 14.05.2007.

63. PW-10, Mr. R.R. Jha, Director in the Ministry of Home Affairs, Government of India, New Delhi, has testified in his evidence before the Tribunal about the criminal activities of the NDFB cadres during the years 2006, 2007 and 2008. He has deposed that the NDFB organization, in pursuance of its aims and objectives, continues to indulge in several violent activities and is spreading terror and panic amongst the people. He has given the details of major incidents of violence by NDFB cadres in 2006, 2007 and 2008 in a list annexed as Annexure-III to his affidavit Ex.PW-10/1. The details of major incidents in which NDFB cadres were allegedly involved include incidents of bomb explosions,

attack on civilians, kidnappings, extortion, encounter with security forces and incidents of arson. Mr. Jha (PW-10) has further deposed in para 10 of his evidence affidavit that nine serial bomb blasts took place in different districts of Assam on 30.10.2008 which resulted into killing of 86 civilians and injuries to 477 persons and the preliminary investigations made by the Government of State of Assam shows the involvement of some active members of NDFB and the conspiracy being hatched in Bangladesh. PW-10 was subjected to searching cross-examination by the NDFB counsel but there is not even an iota of suggestion put to him in relation to the details of the incidents contained in Annexure-III to his affidavit. All the witnesses examined by the Government have deposed about the involvement of the cadres/members of the NDFB organizations in various unlawful criminal activities which resulted into killings and extortion of money for the purpose of achieving their objectives and aims. The documents annexed with the affidavits of the witnesses of the Government not only reveal the involvement of the members/cadres of the NDFB organization in unlawful criminal activities but also proves that at the time when the ceasefire agreement was entered into by the NDFB organization with the Government of India and the Government of State of Assam, they had not given

complete list of their members to the Government for reasons best known to them, presumably with their mala fide intention to bluff, hoodwink and mislead the Government regarding involvement of their cadres in the unlawful activities. Admittedly, Mr. Ranjan Diamary, before he was expelled by the NDFB organization on 29.12.2008, was the President of the said organization. His name was not included in the list of NDFB members given to the Government at the time of ceasefire agreement of 2005 and even thereafter, till he was expelled from the organization on 29.12.2008. The learned senior counsel for the NDFB organization could not give any explanation, much less a cogent explanation, as to why the name of Ranjan Diamary, the erstwhile President of NDFB organization, was not included in the list of members submitted by the organization to the Government at the time of ceasefire agreement. Not only the name of Ranjan Diamary alone was not included in the list of members given to the Government, but the names of various other NDFB cadres who were arrested in the criminal cases in the last two years, were also not included in the said list. PW-1, Mr. Saloi, has given evidence of three bomb blasts that took place in his jurisdiction on 30.10.2008. In the first case of

bomb blast being Case No. 1419/2008 of Police Station Dispur, four accused persons suspected to be NDFB cadres were arrested and two of them; namely, Nilim Diamary @ Di. Nizumsa and Sabin Boro @ B. Susrangu in their confessional statement admitted themselves to be members of NDFB cadres. Accused Nilim Diamary @ D. Nizumsa has told the Police that he had joined the NDFB cadre in March 2007 and had taken training in arms in Bangladesh. Reference is made to Page 339 in Volume II in this regard. The statement of accused Nilim Diamary @ D. Nizumsa shows that the NDFB organization had been making fresh recruitment of its cadres even after it entered into ceasefire agreement with the Government in 2005. The statement of accused Sabin Boro @ B. Susrangu reveals that he had joined the NDFB cadre in 1990 and had taken military training in Bhutan. Reference in this regard may be made to page 340 in Volume II. Similarly, accused Mridul Basumatary and Pabitra Boro @ B. Phuthai @ Lengra in their statement to the Police, had admitted that they were enrolled as cadres of NDFB prior to ceasefire agreement but strangely enough, their names were not included in the list of members submitted to the Government. There are several other accused persons

suspected to be NDFB cadres arrested in the criminal cases regarding which evidence has been given by the Government witnesses, though admitted in their statement about their being members of the NDFB cadres but their names being not included in the list submitted to the Government. Why the NDFB organization withheld the complete list of members, has remained totally unexplained before the Tribunal. Despite opportunity given to the NDFB organization, there is not even an iota of suggestion put to any of the witnesses of the Government to contradict their testimony regarding the alleged involvement of NDFB cadres in the criminal cases for which evidence is given by them.

64. Mr. Chowdhury, the learned senior counsel appearing on behalf of the NDFB organization had taken a technical objection to the admissibility of the evidence produced on behalf of the Government in support of its Notification dated 23.11.2008 contending that the said evidence is not a legally acceptable evidence because according to him, the original documents have not been produced, the maker of the documents have not been examined, statement of accused persons was recorded by the Police under Section 161, Cr.P.C. and the investigation into the cases was done

by a Police Officer not competent to investigate the said cases.

65. I have given my anxious thought to the objection regarding admissibility of evidence taken on behalf of the NDFB organization but I could not persuade myself to agree with the counsel for the NDFB on this aspect of the matter.

66. The Hon'ble Supreme Court in Jamaat-E-Islami Hind Versus Union of India, **1995 (1) SCC 428** has held that the Tribunal adjudicating a Notification issued by the Government banning an organization as an unlawful association can devise a suitable procedure to examine and test the credibility of the material placed before it, before it decides to accept the same for determining the existence of sufficient cause for declaring the association to be unlawful. It was held by the Hon'ble Supreme Court in this case that the material placed before the Tribunal need not be confined only to legal evidence in the strict sense. Para 22 of the judgment of the Supreme Court in Jamaat-E-Islami Hind's case (supra) is relevant and is extracted below :-

"It is obvious that the unlawful activities of an association may quite often be clandestine in nature and, therefore, the source of evidence of the unlawful activities may require continued confidentiality in public interest. In such a situation, disclosure of the source of such information, and, may be, also full particulars thereof, is likely to be against the

public interest. The scheme of the Act and the procedure for inquiry indicated by the Rules framed thereunder provide for maintenance of confidentiality, whenever required in public interest. However, the non-disclosure of sensitive information and evidence to the association and its office-bearers, whenever justified in public interest, does not necessarily imply its non-disclosure to the Tribunal as well. In such cases where the Tribunal is satisfied that non-disclosure of such information to the association or its office-bearers is in public interest, it may permit its non-disclosure to the association or its office-bearers, but in order to perform its task of adjudication as required by the Act, the Tribunal can look into the same for the purpose of assessing the credibility of the information and satisfying itself that it can safely act on the same. In such a situation, the Tribunal can devise a suitable procedure whereby it can itself examine and test the credibility of such material before it decides to accept the same for determining the existence of sufficient cause for declaring the association to be unlawful. The materials need not be confined only to legal evidence in the strict sense. Such a procedure would ensure that the decision of the Tribunal is an adjudication made on the points in controversy after assessing the credibility of the material it has chosen to accept, without abdicating its function by merely acting on the ipse dixit of the Central Government. Such a course would satisfy the minimum requirement of natural justice tailored to suit the circumstances of each case, while protecting the rights of the association and its members, without jeopardizing the public interest. This would also ensure that the process of adjudication is not denuded of its content and the decision ultimately rendered by the Tribunal is reached by it on all points in controversy after adjudication and not by mere acceptance of the opinion already formed by the Central Government."

67. In Union of India Versus Students Islamic Movement of

India & Others, **99 (2002) DLT 147**, it was observed by

this Court as under :-

"The confessional statements referred to and relied upon by the Government, were recorded during investigation of the criminal cases in which they were arrested. Section 25 of the Evidence Act provides that no confession made to a police officer shall be proved against a person accused of any offence. The expression 'a person accused of an offence' describes the person against whom evidence is sought to be proved in a criminal case. The adjective clause 'accused of an offence', is therefore, descriptive of the person against whom a confession is sought to be proved. The confessional statements, can be used in civil proceedings and other collateral proceedings under the Criminal Procedure Code. The inquiry before this Tribunal is clearly not a trial against the accused persons, who made the confessional statements. Therefore, in my considered view confessional statements made by the accused persons during investigation of different cases to the police or before the Court, would not be hit by Section 25 of the Evidence Act and are admissible in evidence, to show whether the accused persons were or are the members of the association, as well as to show whether the activities of the association are unlawful or not."

68. In Suman & Ors. etc. versus State of Tamil Nadu, **AIR**

**1986 (Madras) 318**, it was held as under:-

"It has to be remembered that when Section 25 refers to a confession which is not permitted to be proved as against a person accused of any offence, it refers to a confession made by an accused person which is proposed to be proved against him to establish an offence. The scope of Section 25 is therefore restricted only to a confession made by a person who is



**an accused that is being used in a proceeding to establish an offence against him."**

69. In Nandini Satpathy Versus P.L. Dani and Another, AIR 1978 SC 1025, it was categorically held by the Hon'ble Supreme Court that the statement of the accused person can be recorded by the Police under Section 161, Cr.P.C. The relevant portion of the judgment in Nandini Satpati's Case (supra) is extracted below :-

"....the conclusion that 'any person' in Section 161 Cr.P.C.; would include persons then or ultimately accused. The view was approved in Mahabir Mandal's case (1972) 3 SCR 639 at p. 657 : (AIR 1972 SC 1331 at pp. 1341, 1342). We hold that 'any person' supposed to be acquainted with the facts and circumstances of the case' includes an accused person who fills that role because the police suppose him to have committed the crime and must, therefore, be familiar with the facts. The supposition may later prove a fiction but that does not repel the section. Nor does the marginal note 'examination of witnesses by police' clinch the matter. A marginal note clears ambiguity but does not control meaning. Moreover, the suppositious accused figures functionally as a witness. 'To be a witness', from a functional angle, is to impart knowledge in respect of a relevant fact, and that is precisely the purpose of questioning the accused under Section 161, Cr.P.C. The dichotomy between 'witnesses' and 'accused' used as terms of art, does not hold good here....."

70. In view of the above referred judgments of the Hon'ble Supreme Court and of the High Courts, there is no manner

of doubt in my mind that the Police can record the statement of the accused person under Section 161, Cr.P.C. The objection to the recording of the statement of the accused persons by the Investigating Officer under Section 161, Cr.P.C. taken on behalf of the NDFB organization is thus without any substance. The objection to the admissibility of secondary evidence taken by the learned senior counsel also is without any substance. It may be noted that all the Government witnesses examined before the Tribunal were subjected to searching cross-examination by the counsel for the NDFB organization but the objection to the mode of proof of the documents was not taken on its behalf in their cross-examination. They also did not take objection to the non-production of the maker of those documents. In fact, the NDFB organization proceeded to cross-examine the Government witnesses on the strength of the copies of documents made available to them without taking any objection to the mode of their proof. I am of the view that the NDFB organization cannot be permitted to raise such an objection regarding admissibility of the documentary evidence at the time of final arguments because the Tribunal is not deciding a criminal trial against the accused persons. What the Tribunal is looking into is the availability of the sufficiency of material for forming an

opinion about the activities of the NDFB organization, whether it requires the organization to be declared as an unlawful association.

71. I do not find any merit in the argument of the learned senior counsel for the NDFB organization that the affidavits filed by the Government witnesses in their evidence cannot be relied upon because of defective verification or the verification being not in accordance with Order 6 Rule 15, CPC. It may be noted that all the witnesses of the Government who have filed their affidavits in evidence to support the Notification under adjudication have categorically deposed in their evidence before the Tribunal that whatever facts have been stated by them in their respective affidavits are believed to be true by them on the basis of information derived by the witnesses from the official records. Hence, the organization cannot be permitted to take any advantage out of the technical lapse of alleged defect in the verification clause of the affidavits filed by the witnesses of the Government in their evidence.

72. The objection raised by the learned senior counsel for the NDFB organization regarding investigation of criminal cases, referred to in the affidavits of the Government witnesses, not been done by a Police Officer of the rank of

Deputy Superintendent of Police as required by Section 43 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, also seems to be without any merit for adjudicating upon the Notification dated 23.11.2008. It may be noted that Section 43 which requires investigation of cases under the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 to be done by a Police Officer of the rank of Deputy Superintendent of Police, deals with offences under Chapter IV and VI whereas the criminal cases involving the cadres of NDFB organization were registered under various provisions of the Indian Penal Code along with Section 10 and 13 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 which falls in Chapter III of the Act. Even otherwise, the question regarding competence of the Police officer to investigate the criminal cases registered against the NDFB cadres during the last two years, can be considered only during trial of the criminal cases against the named accused persons and not in proceedings before this Tribunal.

73. On a careful evaluation of the evidence for and against the Notification produced by both sides, I find the testimony of the Government witnesses to be more credible and reliable and can be safely acted upon for confirming the Notification dated 23.11.2008. Rather, every bit of the statement of the witnesses of NDFB organization in their

cross-examination supports the case of the Government for banning the NDFB organization as an unlawful association. The NDFB has examined three witnesses as DW-1 to DW-3. DW-1, Mr. B. Swmkhwr, claims himself to be the General Secretary of NDFB organization and he has stated in his deposition that the NDFB's Constitution still exists and that the copy of the NDFB Constitution annexed to his affidavit is the latest version of NDFB's Constitution. The relevant portion of the testimony of DW-1 in this regard is quoted below :-

"Our Constitution, described as the 'Constitution of NDFB' exists even today. It is correct that our Constitution owns a flag. It is correct that one of the Articles in the Constitution deals with Boroland and the said article holds the field even today."

74. In view of the above testimony of DW-1, we may now note the provisions of the NDFB's Constitution.

" i. Preamble :

"The Revolutionary Patriots who gathered together on the THIRD October, 1986, have formed THE BORO SECURITY FORCE to liberate their inherited land and the people from the colonist oppression with armed struggle therein to transform a DEMOCRATIC SOCIALIST SOCIETY to promote LIBERTY, EQUALITY AND FRATERNITY - free from SOCIO-POLITICO and

ECONOMIC exploitation, oppression, suppression and colonization.

ii. Article 4 — Principles and Ideology

- (a) Liberate Boroland from the Indian expansionism and occupation.
- (b) XXX
- (c) XXX
- (d) Uphold the Integrity and Sovereignty of Boroland.

iii. Article 18 — The Boroland Army

To carry out the armed struggle for national liberation the NDFB shall have its own army known as the BOROLAND ARMY. The Boroland Army shall be regulated through Boroland Army Foundation."

iv. Article 19 — The People's Revolutionary Government

The NDFB in the course of revolutionary struggle shall form and establish the People's Revolutionary Government known as the Government of the People's Republic of Boroland.

v. Article 20 — The People's Revolutionary Court

The NDFB shall have a JUDICIARY known as the People's Revolutionary Court for free and fair conviction

vi. Article 21 — The Oath

..... do solemnly swear allegiance to the Constitution, the NDFB, to serve the nation sincerely and honestly and also do swear to protect and safeguard the Party's unity and integrity and hereby pledge to struggle for liberation of Boroland with all my heart and soul."

75. DW-2, Shri I. Damini, claimed himself to be the Home Secretary of NDFB organization and he has admitted in his cross-examination as under :-

“Our Boro people are deprived of their dignity, honour, territories and sovereignty even today. The suppression of the Boro people by the Government of India continues even today.”

76. DW-1, in his cross-examination has testified that the NDFB organization believes in its right of self-determination. To the same effect is the testimony of DW-3, Mr. B.K. Olongbar, who claims himself to be the Education Secretary of National Democratic Front of Boroland.

76. From the above testimony of the witnesses of the NDFB organization, it is evident that the said organization still believes in having a separate sovereignty and territory separate from India for its Boro community through use of armed struggle. The NDFB's Constitution, which according to the witnesses of the organization, exists even today, has (1) General Assembly, (2) National Council, (3) Oath, (4) Flag, (5) Emblem, (6) Judiciary, (7) Military Training, (8) Raising of funds through taxation and donation, (9) Speaker and (10) separate territory for Boro community.

77. If the NDFB organization was serious about peace in terms of the ceasefire agreement of 2005 which continues till date, they should not have taken recourse to the path of violence for pressing their demands and should have rather

submitted themselves with a charter of their demands to the Government for a peaceful solution through a mutual dialogue. In fact, this ceasefire agreement provided them a platform for a political dialogue for addressing the alleged problems faced by the Boro community. From the evidence that has been placed before me, I am convinced that the members of the NDFB organization instead of taking recourse to peaceful negotiations in terms of ceasefire agreement have resorted to various unlawful criminal activities during the last two years, which have taken lives of hundreds of innocent persons, for no fault on their part merely because of possible clash between the NDFB organization and the ex-Boro Liberation Tiger then headed by Hagrama Mohilray. It shall be pertinent to note that DW-1, Mr. B. Swmkhwr, has testified in his cross-examination that there are three battalions in the NDFB organization and he has further admitted that these three battalions in his organization are working with arms. Normally, a battalion in an association, whether lawful or unlawful, is not heard of. The presence of three battalions in the NDFB organization as stated by DW-1 in his cross-examination, itself reflects the military structure of the organization. DW-3, Mr. Olongbar has stated in his cross-examination that he was



appointed as Education Secretary by the General Assembly of the organization on 15.12.2008 and before his said appointment, he was working as Foreign Secretary in the organization. He has admitted in his cross-examination that the duties of a Foreign Secretary in NDFB organization is to co-ordinate with various organizations which are situated outside the territories of India. He has stated that he was appointed as Foreign Secretary after the ceasefire of 2005. He has further stated that the post of Foreign Secretary became dysfunctional after ceasefire agreement of 2005. I fail to understand in case the post of Foreign Secretary has become dysfunctional after ceasefire agreement of 2005, why DW-3 Mr. B.K. Olongbar was appointed as Foreign Secretary by the General Assembly after ceasefire of 2005. There appears to be some hidden mischief in this. DW-3 has further admitted in his cross-examination that he had visited Bangladesh on two occasions without Indian passport, which amounts to illegal infiltration. The statement of DW-3 that he had visited Bangladesh on both the occasions prior to ceasefire of 2005 does not inspire confidence of the Tribunal. No reliable evidence has been placed by DW-3 on record to show that his illegal visits to Bangladesh were prior to ceasefire agreement of 2005. It will be interesting to note that DW-3 has also deposed in his

cross-examination that prior to ceasefire agreement of 2005, he was working as Deputy Army Chief of NDFB organization and had acquired expertise in operating arms and ammunition. His statement that his duties as Education Secretary is to encourage the cadre of the organization and the people of Boro community to go to schools and colleges, run by the State Government does not inspire my confidence because according to this witness himself, not even a single cadre or member of the organization has gone to either school or college. There is yet another significant aspect of the matter to be taken note of. Some of the criminal cases registered against the members/cadres of the organization pertain to extortion of money. All the three witnesses examined by the NDFB organization against the notification dated 23.11.2008 have testified in their respective cross-examination that though they are working as General Secretary, Home Secretary and Education Secretary in the organization but they are not getting any salary from the organization. They also admitted that they have no office or infrastructure to work as Secretaries of the organization. They have stated that they depend for their livelihood upon the funds of the organization in the form of TA, etc. No evidence has been placed by the organization on record to show the source of its funding and in the

absence of the same, it can only be presumed that the organization is indulging in extortion of money for raising funds required by it for its legal and illegal activities.

78. Article 17 of the NDFB's Constitution, provides for raising of funds through taxation and donation from well-wishers. DW-1, Mr. Swmkhwr, was asked to explain the terms 'taxation', 'donation' and 'well-wisher' used in Article 17 to which he replied that the term 'well-wisher' used in Article 17 refers to those persons who support the constitution of Boroland and the term 'taxation' used in Article 17 was explained by him stating that the term 'taxation' means raising of funds through the collection of money from non-Boro people. However, he volunteered that this was prior to the entering of ceasefire agreement of 2005. This statement of DW-1 does not inspire my confidence for the reason that the new ground rules contained in the ceasefire agreement of 06.01.2009 prohibit the organization from collection of any donations and the said rule has been described as unfortunate by all the three witnesses of the organization in para 8 of their affidavits filed by them in their evidence.

79. DW-3, Mr. Olongbar was asked a pertinent question as to why they have described the stoppage of donation as

unfortunate to which answer given by the DW-3 was as follows :

“We feel stoppage of collection of donation to be unfortunate because our living conditions in the Designated Camps are extremely poor. Recently, there was a storm which wholly destroyed our Designated Camp at Odalguri and stoppage of collection of donation by the Government has worked to our prejudice as we do not have sufficient funds for rehabilitation of our members and cadres in Odalguri Designated Camp. That is why we call stoppage of collection of donation to be unfortunate.”

80. In the backdrop of the above answer given by DW-3, the statement of DW-2 in his cross-examination that the Boro people are deprived of their dignity, honour, territories and sovereignty even today and that the suppression of Boro people by Government of India continues even today, assumes great importance. DW-1 and DW-3 state that they believe in their right of self-determination. What does it all show? This only implies that the ceasefire agreement of 2005 entered into by the organization with the Government was only an eye-wash. Their intentions were otherwise. They continued in their extremist activities taking toll on the lives of innocent people of Assam. My this conclusion is fortified by the statement of DW-2 in his cross-examination where he says that some of the members of the NDBF

organization whose names are included in the list of NDFB cadres furnished to the Government were arrested by the Police in the last two years in connection with several criminal cases. If in terms of ceasefire agreement, the cadres of NDFB organization were staying in the three Designated Camps and could not have moved out of the Camps without authorization of the Camp Commander, then how those cadres staying in the Designated Camps were arrested by the State Police, remained unexplained by the NDFB organization. DW-2, Mr. Damini claims to be the Home Secretary of the NDFB organization and is stated to have joined the organization in 1998. His name was not there in the list of members submitted to the Government at the time of ceasefire agreement. DW-2 has admitted in his cross-examination that he was not issued any Identity Card by the Government to show that he belongs to the NDFB cadre. DW-2 says that the identity card was not issued to him by mistake. What was that mistake, has not been explained by the witness. From the testimony of DW-2, it is evident that he was a member of NDFB organization but for reasons best known to the organization, his name was not included in the list submitted to the Government. One person by the name of Konak Diamary was arrested by the State Police in Case No. 106/2007, PS

Bijni, under the jurisdiction of PW-4, Mr. Deka. When he was arrested in that case, his identity card bearing his photograph was recovered from his possession on which his name was mentioned as D. Khabrang. Confronted with this different name on his identity card, Konak Diamary arrested in that case said that he was also known by the name of D. Khabrang and this is how his name came to be mentioned in the list of accused persons in that case as Konak Diamary @ D. Khabrang. This alias name given by the accused in that case shows that the list of members given by the organization to the Government at the time of ceasefire agreement either contained fictitious names or did not include names of all its cadres. A suggestion to this effect was put in cross-examination to DW-3 which was denied by him. This denial by DW-3 carries no meaning for the reasons mentioned above. All the three witnesses examined by the organization against the notification have admitted in their respective cross-examination that the organization had expelled its erstwhile President, Mr. Ranjan Diamary @ D.R. Nabla because of his alleged involvement in bomb blast cases that rocked the Assam State on 30.10.2008. This admission by the witnesses of NDFB clearly proves that their top leaders including other cadres/members of the organization are involved in various

unlawful acts in spite of the signing of the ceasefire agreement of 2005. It is crystal clear that despite the ban imposed by the Central Government vide last Notification dated 23.11.2006, the banned association and its office bearers/members still have been indulging into the unlawful activities as defined in Section 2(o) of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967.

81. Before I conclude my report, I would like to refer one of the submissions contained in the written synopsis filed on behalf of NDFB organization, which is extracted herein below :-


"The problem must be solved at an early date with sincere efforts of all the parties to the tripartite agreement. Things might turn for the worst, this should not happen."(Emphasis added).

82. The above submission made on behalf of the NDFB organization clearly points out a threat on their part for dire consequences.

83. For the foregoing reasons, I am satisfied that there is sufficient cause for declaring NDFB organization as an unlawful association. This Tribunal, accordingly, confirms

the declaration made by the Central Government vide notification dated 23.11.2008 issued under sub-section (1) of Section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967.

MAY 18, 2009

  
**(JUSTICE S.N. AGGARWAL)**  
UNLAWFUL ACTIVITIES (PREVENTION)  
TRIBUNAL